चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

02 सितंबर–08 सितंबर 2013

फोटो– प्रभात पाण्डेय

इतिहास के आईने में

एक ईमानदार प्रधानमंत्री

यूपीए सरकार के दस साल पूरे होने वाले हैं. इन दस सालों में क्या हुआ? हम विकास की राह पर कहां तक पहुंचे? भारत आगे बढ़ा या पीछे छूट गया? देश की एकता व अखंडता मजबूत हुई या फिर हम बिखरने लगे? वर्षों से चल रही समस्याओं का क्या हुआ? सरकार की नीतियां कितनी सफल हुईं और संवैधानिक संस्थाओं पर लोगों का विश्वास कितना बढ़ा? इतिहास मनमोहन सिंह सरकार का किस तरह आकलन करेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब आने वाले दिनों में ढूंढा जाएगा.

मनीष कुमार

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के बारे में चर्चा करने से पहले एक घटना सुनाता हूं. वीपी सिंह के इस्तीफे के बाद देश में चंद्रशेखर जी की सरकार बनी. मनमोहन सिंह इस सरकार के आर्थिक सलाहकार थे. राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनी कि सरकार गिर गई. चंद्रशेखर जी ने प्रधानमंत्री पद से 6 मार्च, 1991 को इस्तीफा दिया था, लेकिन वे अगले चुनाव तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे. सरकार के जाने के बाद चंद्रशेखर जी अपने सहयोगियों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बना रहे थे. मनमोहन सिंह भी चंद्रशेखर जी से आकर मिले. उदास मन से मनमोहन सिंह ने पूछा, अब मेरा क्या होगा. अब मैं क्या करूंगा. वहां मौजूद लोग चक्कर खा गए कि मनमोहन जी क्या कह रहे हैं. एक तरफ तो सरकार गिर गई है, सब दुखी हैं और इन्हें अपनी चिंता लगी हुई है. मनमोहन सिंह ने आगे जो कहा, वह भी चौंकाने वाला था. उन्होंने चंद्रशेखर जी से कहा कि यूजीसी के चेयरमैन की सीट खाली है, मुझे वहां भेज दीजिए. चंद्रशेखर जी ने शायद इस्तीफा देने के बाद अकेला यही फैसला लिया. मनमोहन सिंह 15 मार्च, 1991 को यूजीसी के चेयरमैन बन गए.

दरअसल, मनमोहन सिंह एक पदलोलुप (कैरियरिस्ट) व्यक्ति हैं. उनमें एक ऐसे पेशेवर अधिकारी के गुण हैं, जो हर पल अपनी पदोन्नति की चिंता में मग्न रहता है. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री भले ही हैं, लेकिन वे कोई राजनेता नहीं हैं. वे जन नेता भी नहीं हैं. 2004 से पहले वे वित्त मंत्री भी रहे, लेकिन जनता के साथ कोई रिश्ता नहीं बना सके. एक कड़वा सच यह है कि देश के अधिकांश लोगों को यह भी पता नहीं है कि राज्यसभा में वे किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं. वे अच्छा भाषण नहीं दे सकते और न ही युवाओं मे जोश भर सकते हैं. वे जनता के दिलों पर राज करने वाले प्रधानमंत्री नहीं हैं और न ही कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं. यही नहीं, उनकी कैबिनेट के सहयोगी भी उन्हें अपना नेता नहीं मानते हैं. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए बने, क्योंकि उन्हें सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए चुना था. एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना कर कांग्रेस ने जो गलती की है, उसका खामियाजा आने वाले कई सालों तक कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है.

जब 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो देश के लोगों को लगा कि एक पढ़ा-लिखा, विश्वस्तरीय अर्थशास्त्री भारत को एक सुपरपावर बनाएगा, लेकिन आज देश की जनता निराश है. निराशा का स्तर यह है कि ऐसा लगता है कि मानो देश किसी ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है, जो कभी भी भड़क सकता है. इसमें कोई शक नहीं है कि यूपीए सरकार के दस साल आजाद भारत के इतिहास का सबसे काला धब्बा साबित हुआ है. इस दौरान एक के बाद एक व एक से बढ़कर एक समस्याएं आती रहीं, लेकिन अफसोस किसी का भी समाधान नहीं निकला. कृषि की हालत पहले से बदतर हुई. उद्योग का विकास थम गया. विदेशी निवेश आने बंद हो गए. निर्यात को झटका लगा. बेरोजगारी बढ़ी. मंहगाई बढ़ी. बाजार मंदा हुआ. सोना मंहगा हुआ. इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास का काम बिल्कुल ठप्प रहा.

दरअसल, मनमोहन सिंह एक पदलोलुप (कैरियरिस्ट) व्यक्ति हैं. उनमें एक ऐसे पेशेवर अधिकारी के गुण हैं, जो हर पल अपनी पदोन्नति की चिंता में मग्न रहता है. वे प्रधानमंत्री भले ही हैं, लेकिन राजनेता नहीं हैं. वे जननेता भी नहीं हैं. वे वित्त मंत्री भी रहे, लेकिन जनता के साथ कोई रिश्ता नहीं बना सके.

पिछले दस सालों में मनमोहन सरकार की योजनाओं का फायदा समाज के गरीब वर्ग को नहीं हुआ. सरकारी नीतियों का फायदा गिने-चुने तीन से पांच फीसद लोगों को पहुंचा है. किसानों की हालत ऐसी हो गई कि वे आत्महत्या कर रहे हैं. भारत में हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है. यह किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है.

सड़क नहीं, पानी नहीं और बिजली की कमी लगातार बनी रही. यूपीए के शासनकाल में लोग हमेशा परेशान रहे. हैरानी की बात यह है कि सरकार इन समस्याओं से निपटने के बजाए आंकड़ों की जालसाजी के जरिये जनता को धोखा देती रही. वित्तमंत्री और प्रधानमंत्री झांसा देते रहे कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश बन गया है. यूपीए की कलई तब खुली, जब रुपये का मूल्य रसातल में चला गया.

पिछले दस सालों में मनमोहन सिंह की सरकार की योजनाओं का फायदा समाज के गरीब वर्ग को नहीं हुआ. पिछले दस सालों में सरकारी नीतियों का फायदा गिने-चुने तीन से पांच फीसद लोगों को पहुंचा है. किसानों की हालत ऐसी हो गई कि वे आत्महत्या कर रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक, भारत में हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है. यह किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है. विकास के नाम पर किसानों की जमीन जितनी इन दस सालों में छीनी गई, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया. सरकार की भूमिका मानो किसी प्रॉपर्टी डीलर जैसी हो गई है. किसानों की जमीन छीन कर निजी कंपनियों को देकर उन्हें करोड़ों-अरबों का फायदा पहुंचाना सरकार की नीति बन गई. किसानों के लिए पानी नहीं है, लेकिन नदियों के पानी को निजी कंपनियों को दिया जा रहा है. विदेशी कंपनियों की वजह से खाद व बीज की कीमत आसमान छू रही है. खेती करना मंहगा सौदा हो गया है. दूसरी तरफ जंगलों में रहने वाली जनजातियों की हालत किसानों से भी बदतर है. औद्योगीकरण व खनन के नाम पर जंगल कट रहे हैं. उनकी जिंदगी व आशियानों को नष्ट किया जा रहा है. पिछले दस सालों में सरकार की एक भी पुनर्वास योजना सफल नहीं हुई.

सच्चाई तो यही है कि पिछले दस सालों में यूपीए सरकार किसानों और जनजातियों को खुशहाल करने व उनकी समस्याओं का समाधान निकालने में पूरी तरह से विफल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का बड़ा दंभ भरती है. 2009 के चुनाव से पहले यूपीए सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर चुनावी फायदा जरूर उठाया, लेकिन जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो पता चला कि मनरेगा व कर्ज माफी योजना में घोटाला हुआ है. मनरेगा में अनियमितताओं को लेकर इतनी सारी मीडिया रिपोर्ट आ चुकी हैं कि लोगों ने तो अब यह मान

(शेष पृष्ठ 2 पर)

वादाख़िलाफ़ी के दस साल 03

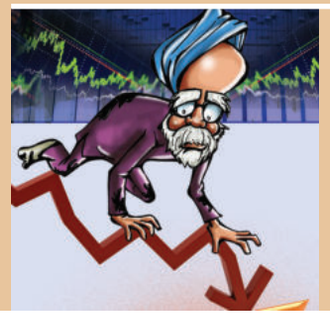

दबंग डॉलर रोता रुपया सिसकता सेंसेक्स 05

अब शिक्षा में भी क्रांति की दरकार... 07

साई की महिमा 12

इतिहास के आईने में एक ईमानदार प्रधानमंत्री

पृष्ठ एक का शेष

लिया है कि देश का पैसा इस योजना के जरिये बर्बाद किया जा रहा है. पता नहीं मनमोहन सिंह और वित्तमंत्री चिदंबरम का यह कौन सा अर्थशास्त्र है, जिसमें असफल योजानाओं और सरकारी पैसे की बर्बादी को अपनी उपलब्धि बताते हैं.

जब मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बने तो पहले पांच साल का वक्त यूं ही बीतता चला गया. सच्चाई ये है कि एनडीए की सरकार के दौरान हुए कामों और विकास की वजह से यूपीए–1 के दौरान विकास की गति बरकरार रही. मनमोहन सिंह सरकार सिर्फ आंकड़ों की कलाबाजी करती रही और क्रेडिट लेती रही. यूपीए–1 के दौरान सरकार ने हर सफलता का क्रेडिट लिया और हर विफलता के लिए गठबंधन धर्म को दोषी ठहराया. यूपीए–1 को लेफ्ट पार्टियों का समर्थन था तो हर असफलता के लिए कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया. जब 2009 में चुनाव हुए तो जनता ने मनमोहन सिंह की सरकार को फिर से सरकार चलाने का मौका दिया था, क्योंकि वे ईमानदार हैं. जब उन्हें एक बार फिर से मौका मिला तो उन्हें हर कोशिश करनी चाहिए थी कि जनता के विश्वास को और भी मजबूती प्रदान करें. उन्हें 2009 के बाद भ्रष्टाचार खत्म करने के उपाय करने थे, नौकरशाही में बदलाव लाकर उन्हें जिम्मेदारी निर्धारण करने के उपाय करने थे. असफल योजनाएं कैसे सफल हों, उसकी रणनीति बनानी थी. सरकार का पैसा सही लोगों तक पहुंचे, उसके रास्ते निकालने थे. सरकारी कामकाज में पारदर्शिता कैसे लाई जाए व जबावदेही कैसे तय की जाए, इस पर फैसला लेना था. देश की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी, उसे पटरी पर कैसे लाया जाए, उस पर नीतियां बनानी थीं, लेकिन अफसोस की बात है कि मनमोहन सिंह ने न सिर्फ जनता का विश्वास तोड़ा है, बल्कि खुद का दामन भी दागदार कर दिया. मनमोहन सिंह न सिर्फ खुद को अब तक का सबसे कमजोर, बल्कि फैसले न लेने वाला प्रधानमंत्री घोषित करने में जुट गए.

मनमोहन सिंह के दस साल के शासन के बाद देश के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. आज देश में प्रजातांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों का भरोसा उठ गया है. कांग्रेस पार्टी ने पिछले दस सालों में इस तरह से देश को चलाया है, जिससे बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण संस्थाओं के औचित्य व सार्थकता पर सवाल उठने लगे हैं. अगर सीबीआई सरकार के मंत्रियों से जांच रिपोर्ट बदलवा कर सुप्रीम कोर्ट में पेश करे तो ऐसी जांच पर कौन विश्वास करेगा. सरकार पर कौन विश्वास करेगा और वह भी ऐसे केस में, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री पर शक की सुई हो. मनमोहन सिंह ने पहले सीवीसी की नियुक्ति में गड़बड़ी की. एक दागी को सीवीसी बना दिया. सुप्रीम कोर्ट ने जब कड़े आदेश दिए, तब जाकर उसे बदला गया. देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एक थल सेना अध्यक्ष और सरकार आमने–सामने हो गई. पहली बार मनमोहन सिंह की सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को कहा. कोर्ट का विश्वास सरकार पर से उठ गया, क्योंकि कई बार कोर्ट ने सरकार को कोर्ट के अंदर झूठ बोलते और माफी मांगते पकड़ा है. कई बार इस सरकार के नुमाइंदों ने लोकसभा और राज्यसभा में झूठ बोला. पहली बार सीएजी और सरकार के बीच तू–तू–मैं मैं हुई, जबकि संविधान में साफ लिखा है, अंबेडकर और नेहरू ने संविधान सभा में भी समझाया कि सीएजी का महत्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कम नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता व मंत्री सत्ता के नशे में इतने चूर नजर आए कि उन्होंने सीएजी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

इतना ही नहीं, लोकसभा के अंदर भी आजीबोगरीब नाटक चलता रहा. अन्ना हजारे के अनशन को खत्म करने के लिए रात भर संसद में बहस होती रही, जनलोकपाल लाएंगे, ऐसा प्रस्ताव भी पास हुआ और मनमोहन सिंह के काबिल नेतृत्व के चलते पहली बार सरकार संसद में पास हुए प्रस्ताव से मुकर गई. आधार कार्ड को देखिए, इससे जुड़ा बिल संसद से पास नहीं हुआ है, लेकिन देश में करोड़ों कार्ड बना दिए गए हैं, जबकि इसकी वैधता पर एक केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है. यूपीए–2 के दौरान कई स्थायी समितियों और चयन समितियों में उठापटक होती रही. पहली बार यूपीए सरकार के दौरान संसदीय समितियों का राजनीतिकरण देखा गया. इतना ही नहीं, संसद का सबसे ज्यादा समय बर्बाद करने का रिकॉर्ड भी यूपीए–2 ने अपने नाम किया है. मतलब यह कि मनमोहन सिंह को इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाएगा, जिनके शासनकाल में देश की महत्वपूर्ण सस्थाओं का क्षरण हुआ है. वैसे मनमोहन सिंह की दूसरी पारी में सबसे बड़ी चुनौती तो यह थी कि कैबिनेट के अंदर प्रधानमंत्री की प्रमुखता को फिर से स्थापित करना था, लेकिन वे प्रधानमंत्री की गरिमा को स्थापित करने में भी विफल रहे हैं. अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज सोशल मीडिया में भारत का प्रधानमंत्री एक मजाक का पात्र बना हुआ है.

देश में 270 जिले ऐसे हैं, जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं. जब मनमोहन सिंह ने इस देश में उदारवादी आर्थिक नीतियों को लागू किया, तब से नक्सलवाद करीब 30 जिलों से बढ़ कर 270 जिलों तक पहुंच गया. इन जगहों पर सरकार नहीं है. यहां समानांतर सरकार चल रही है. मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया था, लेकिन हर साल सैकड़ों जानें जाती हैं, लेकिन पिछले दस सालों में उन्होंने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए और न ही कोई शुरुआत की. लोग मरते रहे, अर्धसैनिक बल के जवान शहीद होते रहे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला. एक तरफ नक्सली संगठन आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, साथ ही साथ नेपाल के साथ भी रिश्ते खराब हो चुके हैं. पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव है. पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होता रहा है. हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उधर आए दिन चीन की सेना सरहद के अंदर घुस आती है. विदेश मंत्रालय और उसकी नीतियों में विरोधाभास की वजह से बाह्य खतरा भी मंडरा रहा है. भारत की आर्थिक स्थिति और पड़ोसियों व शक्तिशाली देशों के साथ रिश्तों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुए हैं. कुछ साल पहले तक देश सुपरपावर बनने की तरफ बढ़ रहा था. संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी थी. अब हालत यह है कि इसके बारे में बात करना भी मजाक लगने लगा है.

एक जमाना था जब बोफोर्स घोटाले के नाम पर देश की राजनीति बदल गई. सरकार को चुनाव हारना पड़ गया था. वह घोटाला महज 64 करोड़ का था, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार की कृपा से देश में आज 64 करोड़ रुपये के घोटाले को घोटाला नहीं माना जाता है, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार घोटाले के सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है. अगर यूपीए के दौरान हुए घोटालों के बारे में जिक्र किया जाए तो यह अखबार ही पूरा भर जाए, लेकिन घोटालों के इतिहास में जो कीर्तिमान यूपीए ने बनाए हैं, उसका जिक्र करना जरूरी है. मनमोहन सिंह की सरकार देश की पहली सरकार है, जिसका कोई मंत्री जेल गया हो. पहली बार देश को पता चला है किस तरह सरकार में बैठे लोग निजी कंपनियों के साथ मिल कर अरबों–खरबों की हेरा–फेरी कर देते हैं. दुनिया का कोई भी देश ओलंपिक या विश्व कप का आयोजन करता है तो उससे वह देश अपनी इज्जत में इजाफा करने की नीयत से काम करता है. मनमोहन सिंह सरकार के दौरान उनकी ही पार्टी के लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के बहाने हजारों करोड़ रुपये निगल गए. पूरी दुनिया में बदनामी हुई, लेकिन मनमोहन सिंह जी किसी भी घोटालेबाज को सजा नहीं दिलवा सके.

भ्रष्टाचार का आलम तो यह है कि प्रधानमंत्री भी नहीं बच पाए. पहली बार किसी घोटाले में प्रधानमंत्री कार्यालय पर शक की सुई जा टिकी है. कोयला घोटाले के पर्दाफाश होते ही मनमोहन सिंह ने ऐलान किया था कि अगर उन पर शक की सुई भी आई तो वे सार्वजनिक जीवन का परित्याग कर देंगे. मनमोहन सिंह जब कोयला मंत्री थे, तब कोयला खदानों का आवंटन हुआ था. हर आवंटन पर उनके दस्तखत हैं. सारी कार्रवाई प्रधानमंत्री कार्यालय से हुई है, यही आरोप है. सीबीआई ने जांच की, जिसकी रिपोर्ट मनमोहन सिंह के करीबी मंत्री अश्विनी कुमार ने बदल दी. मामला सिर्फ घोटाले का नहीं रहा, बल्कि यह चोरी और सीनाजोरी में तब्दील हो गया, लेकिन कोर्ट में इन करतूतों का पर्दाफाश हो गया. अश्विनी कुमार को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया. मामला कोर्ट में चल ही रहा था कि पता चला कि कोलया घोटाले से जुड़ी फाइलें मंत्रालय से गायब हैं. फाइलों के पैर नहीं होते, इसलिए वह स्वत: गायब नहीं हुईं, बल्कि गायब की गई हैं. जांच चल रही है, लेकिन कोयला घोटाले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इतनी आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं कि कोई भी आत्मसम्मान वाला और राजनीतिक मर्यादा को मानने वाला व्यक्ति इस्तीफा दे चुका होता. मनमोहन सिंह ने एक ईमानदार प्रधानमंत्री की छवि के साथ 2004 से शुरुआत की थी, लेकिन 2013 में वह लोगों की नजरों में ईमानदार नहीं रहे. अब लोग उन्हें मिस्टर क्लीन नहीं मिस्टर क्लीन अप कहने लगे हैं. ■

manish@chauthiduniya.com

फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

मनमोहन सिंह के दस साल के शासन के बाद देश के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. आज देश में प्रजातांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों का भरोसा उठ गया है. कांग्रेस पार्टी ने पिछले दस सालों में इस तरह से देश को चलाया है, जिससे बड़ी-बड़ी महत्वपूर्ण संस्थाओं के औचित्य व सार्थकता पर सवाल उठने लगे हैं.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 05 अंक 26
दिल्ली, 02 सितंबर–08 सितंबर 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999
6450888
6452888
011–23418962
विज्ञापन व प्रसार +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

प्रशासन में राजनीति का दखल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन करके अधिकारियों के एक तबके की नाराजगी मोल ले ली है. ऐसी धारणा बनी है कि पूर्ववर्ती सरकार से भिन्न मुख्यमंत्री प्रशासन को लेकर अपनी आंखें बंद किए हुए हैं और सरकार के चलने में राजनीति को दखल देने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि अखिलेश ने जहां नागपाल के निलंबन पर सख्त रुख अपनाया, वहीं उन्होंने कुछ तेज–तर्रार और समझदार आईएएस अधिकारियों की टीम को जिम्मेदारी दी हुई है, जो मीडिया द्वारा सरकार की कटु आलोचना के बीच, उसकी निगरानी में बड़ी कमठता से काम कर रहे हैं.

सूत्रों के अनुसार इन समर्पित अधिकारियों में से कुछ नाम हैं– 1982 बैच के अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह, जो उत्तर प्रदेश के आईडीसी विभाग में मुख्य सचिव हैं. 1984 बैच के अधिकारी संजय अग्रवाल, जो उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग में मुख्य सचिव और यूपी पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं. ये बाबू लोग अन्य बाबुओं के बीच सच्चरित्र और उन गुणों से परिपूर्ण माने जाते हैं, जो नौकरशाहों में होने चाहिए. हाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अध्ययन अवकाश से लौटे सिंह के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी. सिंह ने इसे दुर्भावना से प्रेरित ओछी हरकत बताया. शायद अखिलेश यादव भी जानते हैं कि वे बिना आईएएस अधिकारियों के बहुत कुछ कर नहीं सकते. ■

बंगाली बाबुओं की बेदखली

बंगाल में बाबू, जिन्हें कई वर्षों से रायटर्स बिल्डिंग का चक्कर लगाने की सख्त मनाही थी, ममता बनर्जी के आगे घुटनों के बल चलते रहे हैं. तमाम तर्क–वितर्क और वाक्छल के बाद 17 विभागों और सचिवालयों को ऐतिहासिक बिल्डिंग से हटाकर हावड़ा भेजने का ममता का निर्णय स्वीकार कर लिया गया है. इस स्थानांतरण का विरोध करने का विचार पेश करने से पहले यह उल्लेख करना जरूरी है कि मुख्यमंत्री ममता पिछले साल से ही बाबुओं को बाहर करने की कोशिश कर रही थीं. सूत्रों का कहना है कि अनिच्छुक बाबुओं को हटाने की योजना सिर्फ कागजों में ही थी. पिछले साल अक्टूबर में संजय मित्रा के मुख्य सचिव बनने के बाद इस योजना को गति मिली. ममता बनर्जी ने मित्रा को छूट दी और सभी विरोधी लाइन में आ गए. ममता ने आदेश दिया कि एक अक्टूबर तक सभी कार्यालय पुनर्स्थापित किए जाएं, क्योंकि ऐतिहासिक बिल्डिंग की मरम्मत कराने की बहुत सख्त जरूरत है. ■

मोरे ने मार लिया मैदान

महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनने के लिए 40 पूर्व नौकरशाहों और अधिकारियों ने कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक को ही सफलता मिल सकी. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहाण की अध्यक्षता में गठित एक पैनल ने कमीशन को पुन: आकार दिया, जो कि एक साल से अधिक समय से काम नहीं कर रहा था. आयोग के पास 11,367 मामले लंबित हैं. चौहान की अध्यक्षता वाले पैनल ने पूर्व न्यायाधीश एसआर बनुर्मठ को अध्यक्ष, एमजी गायकवाड़ को दूसरा सदस्य और पूर्व आईपीएस अधिकारी भगवंत मोरे को तीसरा सदस्य नियुक्त किया है. मोरे की नियुक्ति ने काफी ध्यान खींचा, क्योंकि उनके विरोध में पूर्व मुख्य सचिव जेपी डांगे, पूर्व गृह सचिव एपी सिन्हा, अतिरिक्त मुख्य सचिव बीपी पांडेय जैसे दिग्गज थे. ■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

अनिरुद्ध तिवारी केंद्र में जाएंगे

1990 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अनिरुद्ध तिवारी को संयुक्त सचिव या भारत सरकार में इसी के समकक्ष पद के लिए नामित किया गया है. वर्तमान में वह पंजाब सरकार के कार्मिक और सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग में सचिव हैं.

हिमांशु केंद्र सरकार के साथ जुड़ेंगे

1990 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस हिमांशु कुमार को भारत सरकार में संयुक्त सचिव या उसके समकक्ष पद के लिए नामित किया गया है.

मीणा भी पैनल में शामिल

1991 बैच के आईएएस बाबू लाल मीणा को भारत सरकार संयुक्त सचिव या उसके समकक्ष पद के लिए पैनल में शामिल किया गया है. वर्तमान में वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) में विशेष अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं.

अमित बन सकते हैं संयुक्त सचिव

1991 बैच के आईएएस अमित यादव को भारत सरकार में संयुक्त सचिव या उसके समकक्ष पद के लिए पैनल में शामिल किया गया है. वर्तमान में वह भूमि एवं भवन, दिल्ली सरकार में सचिव हैं.

अरुण के कार्यकाल का विस्तार

1981 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अरुण झा वर्तमान में डीओपीटी के तहत प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग में अपर सचिव के रूप में काम कर रहे हैं. उन्हें छह महीने का सेवा विस्तार दिया गया है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

वर्ष 2008 में महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे सामने बढ़ती हुई महंगाई की चुनौती है. प्रधानमंत्री को तब भी लोंगों की परेशानी से ज्यादा विकास दर को बनाए रखने की चिंता थी. तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल न तो विकास दर को बनाए रख पाया और न ही महंगाई को काबू कर पाया. प्रधानमंत्री ने वर्ष 2006 में दिए अपने भाषण में महंगाई शब्द का पहली बार प्रयोग किया था.

लाल किले की प्राचीर से वादाख़िलाफ़ी के दस साल

वैसे तो सामान्य परिस्थितियों में हमारे यहां प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा देश को संबोधित करने की परंपरा नहीं है. राष्ट्रीय पर्वों या आपात स्थिति में ही देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री देशवासियों को संबोधित करते हैं. देशवासियों के साथ सीधे संवाद में उनसे आशा की जाती है कि वे लोगों के सामने देश की सच्ची तस्वीर रखेंगे. उनसे सच्चे वादे करेंगे. आजादी के बाद जिन प्रधानमंत्रियों ने देश को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया, उन्होंने देश को किसी धोखे में नहीं रखा, लेकिन पिछले दस सालों से देश पर शासन कर रही यूपीए सरकार और उसके प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों से झूठे वादे किए. देश की भोली-भाली जनता आज भी उन वादों के पूरे होने की बाट जोह रही है.

नवीन चौहान

15 अगस्त, 2013 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से देश को 10वीं और संभवत: आखिरी बार संबोधित कर रहे थे. वह देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के बाद स्वतंत्रता दिवस पर देश को लाल किले से सर्वाधिक बार संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं. अपने एक दशक के कार्यकाल के आखिरी भाषण में प्रधानमंत्री ने देश के छह दशकों की उपलब्धियों को गिनाया, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि निरंकुश भ्रष्टाचार के बारे में कुछ नहीं कहा. प्रधानमंत्री ने 2004 के अपने भाषण में कहा था कि टुडे, आई हैव नो प्रॉमिस टू मेक, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप.(आज मैं कोई वादा नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने वादों को पूरा करने का वादा करता हूं.). देश की जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्याओं को खत्म करने के प्रधानमंत्री के वादों के पूरा होने का इंतजार कर रही है. दरअसल, 2004 से 2013 तक प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में जो भी वादे किए, उनमें से अधिकांश आज भी अधूरे हैं.

वर्ष 2008 में महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे सामने बढ़ती हुई मंहगाई की चुनौती है. प्रधानमंत्री को तब भी लोंगों की परेशानी से ज्यादा विकास दर को बनाए रखने की चिंता थी. तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल न तो विकास दर को बनाए रख पाया और न ही महंगाई को काबू कर पाया. प्रधानमंत्री ने वर्ष 2006 में दिए अपने भाषण में महंगाई शब्द का पहली बार प्रयोग किया था. यूपीए सरकार पूरे एक दशक तक महंगाई पर काबू नहीं पा सकी. बड़ा सवाल यह है कि महंगी प्याज से शुरू हुई कहानी कहीं महंगी प्याज पर ही आकर खत्म न हो जाए. जनता महंगाई की वजह से त्राहि-त्राहि कर रही है. किसी भी देश में एक दशक तक शासन करने वाली सरकार मंहगाई के सामने अपने हाथ खड़े कर दे तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि देश को नेता नहीं दलाल और माफिया चला रहे हैं.

15 अगस्त, 2012 को लाल किले से दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार और प्रशासन के काम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का हमारा संकल्प बरकरार है, लेकिन गंभीर बात यह है कि 2012 से 2013 के बीच प्रधानमंत्री के भाषण में लोकपाल को लेकर कोई बदलाव नहीं आया. लोकपाल को नख-दंत विहीन बनाने की जो कोशिश संसद में हो रही है, वह लोगों की इच्छा के अनुरूप नहीं है. पीएम ने अपने भाषण में कहा था कि सरकार में आपके प्रतिनिधि होने के नाते हम आपके प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन केंद्र सरकार पिछले दो सालों से लोकपाल बिल को लेकर लुका-छिपी का खेल खेलने में लगी है. इसे देखने से तो यही लगता है कि सरकार को अपनी ज्यादा और लोगों की चिंता कम है.

वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें अपने कुदरती और वित्तीय संसाधनों का सूझ-बूझ के साथ इस्तेमाल करना होगा. आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जवाबदेही है, लेकिन प्रधानमंत्री की बात यहां भी उल्टी ही साबित हुई. उनके इस वक्तव्य को आदर्श वाक्य मानकर उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने देश की आने वाली पीढ़ी का नुमाइंदा मानकर अपने बच्चों, उनके बच्चों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए टू-जी स्पेक्ट्रम और कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधनों को कॉर्पोरेट हाउसों को कौड़ियों के मोल बेचकर अपनी जेबें भर लीं.

2008 में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक मजबूती के लिए पूरी ईमानदारी से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की ज्यादातर सिफारिशों को लागू कर रहे हैं, लेकिन आज इस वादे की घोषणा के पांच बरस बीत चुके हैं, लेकिन मुसलमानों की स्थिति जस की तस बनी हुई है. चुनावों के पहले मुस्लिम वोट पाने के लिए इस तरह की घोषणा करना कांग्रेस के लिए आम बात हो गई है.

पिछले दस सालों में हमारी स्थिति हमारे पड़ोसी मुल्कों के सामने बेहद कमजोर हुई है. पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देश लगातार दोगला रवैया अपना रहे हैं और भारत इन दोनों देशों से किसी भी मुद्दे का सर्वमान्य हल नहीं निकाल सका है. दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपने भाषणों में दोनों ही मुल्कों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने की बात करते हैं.

2009 में प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा था कि देश को एक और हरित क्रांति की जरूरत है. उन्होंने कहा था कि मुझे विश्वास है कि अगले पांच सालों में हम कृषि में चार फीसद की सालाना विकास दर के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे. यदि हम पिछले पांच सालों की राष्ट्रीय कृषि विकास दर पर नजर डालें तो वर्ष 2009-10 में यह 0.04 फीसद, वर्ष 2010-11 में 7.00 फीसद, वर्ष 2011-12 में 2.8 फीसद रही, लेकिन 2012-13 के दौरान तीन सील के निचले स्तर 1.8 फीसद पर आ गई है. रासायनिक उर्वरकों के सब्सिडी के तरीके में हुए बदलाव का फायदा भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है. किसान अच्छी किस्म के बीजों के लिए मोंसेंटो जैसी विदेशी कंपनी के जाल में फंस गए हैं. किसानों को जैविक खेती की ओर वापस ले जाने के बजाए सरकार दूसरी हरित क्रांति के नाम पर जीन संवर्धित (जेनेटिक मोडिफाइड) फसलें खेतों में उगाने के लिए मजबूर कर रही है.

खाद्य सुरक्षा के विषय में 2009 के भाषण में मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखा न सोये, इसलिए हमारा वादा है कि हम खाद्य सुरक्षा कानून बनाएंगे. आज चार साल बाद चुनावों की भनक लगते ही केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में इस कानून को अध्यादेश के रूप में लागू कर दिया. जो बिल देश की 81 करोड़ आबादी से वास्ता रखता हो, ऐसे बिल को संसद के पटल पर पहले ही चर्चा के लिए रखना सरकार ने क्यों उचित नहीं समझा.

2007 में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कुपोषण को राष्ट्रीय शर्म बताया था, लेकिन आज भी भारत के पचास प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं. यूनीसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के 33 प्रतिशत कुपोषित बच्चे भारत में हैं.

2008 में दिए अपने भाषण में मनमोहन सिंह ने इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ और सोनिया गांधी के रोजगार बढ़ाओ, के नारे की बात कही थी, लेकिन योजना आयोग की नई परिभाषा के तहत अब गांवों में रोजाना 26 की जगह 27.20 रुपये और शहरों में 32 की जगह 33.30 रुपये से ज्यादा कमाने वाले गरीब नहीं कहे जाएंगे. कमरतोड़ महंगाई को थामने में नाकाम रही सरकार ने चुनावी साल में आंकड़ों में हेर-फेर कर के 17 करोड़ गरीब कम करने का चमत्कार कर दिखाया है. सरकार मनरेगा के अंतर्गत लोगों को रोजगार तो दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनका शोषण भी कर रही है. मतलब साफ है कि सरकार की मंशा लोगों का वेलफेयर करने के बजाए सत्ता तक एक बार फिर येन-केन-प्रकारेण पहुंचने की है.

15 अगस्त, 2013 के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के वन्यक्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने लघु वन उपज की खरीद का मूल्य निर्धारित करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है. आजादी के 60 साल बाद, आदिवासियों के कल्याण के लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं, अगर वे पहले लिए गए होते, तो आज नक्सलवाद देश के आदिवासी इलाकों में अपना पैर नहीं पसार पाता. दरअसल, प्रधानमंत्री द्वारा अपने किए गए वादों को पूरा करने का रिकॉर्ड बेहतर नहीं है. ऐसे में उनसे और उनकी सरकार से इस निर्णय को जल्दी और बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है. जनता को लुभाने, बरगलाने और वोट पाने के लिए देश के नेता किसी भी हद तक चले जाते हैं, झूठे वादे करते हैं. परंपरा के अनुरूप वादाखिलाफी का यह कारनामा देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर कर दिखाया है.■

feedback@chauthiduniya.com

प्रधानमंत्री के भाषणों के मुख्य अंश

2004 : न्यू डील फॉर रूरल इंडिया

ग्रामीण भारत के लिए नई पहल (न्यू डील फॉर रूरल इंडिया) के अंतर्गत ग्रामीण भारत के लिए एक नई पहल की गई, जिसके अंतर्गत सिंचाई, स्वास्थ्य, सड़क और प्राथमिक शिक्षा में निवेश करने की बात की गई. इसके साथ-साथ कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के साथ-साथ बिजली और किसानों के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात की गई थी. प्रधानमंत्री ने सात मुख्य क्षेत्रों (सात सूत्र) कृषि, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देने की बात की थी. प्रधानमंत्री ने इन सात सूत्रों को विकास के पुल का मुख्य स्तंभ बताया था.

2005: भारत निर्माण

ग्रामीण क्षेत्रों के ढांचागत विकास के लिए भारत निर्माण की शुरुआत की घोषणा की. अगले दस वर्षों में विद्युत क्षेत्र में जल विद्युत और ताप विद्युत के क्षेत्र में 1,50,000 मेगावाट और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में 40,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी का वादा किया था.

2006: विकास और गरीबी

गरीबी के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार रोजगार है और ऊंची विकास दर रोजगार सृजन का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है.

2007: शिक्षा का प्रसार

भाषण मुख्यतः शिक्षा व्यवस्था में सुधार से संबंधित था. प्रधानमंत्री ने देश के हर ब्लॉक में 6000 नए स्कूलों की स्थापना की घोषणा की. साथ ही देश के जिन 370 जिलों में इनरॉलमेंट लेवल कम है, उन सभी जिलों में एक कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा की. इसके साथ ही वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए 1600 नये आईटीआई और पॉलीटेकनिक, 10000 वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल और 50000 नये स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने की घोषणा की.

2008: चुनावी भाषण

अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार के लिए सच्चर कमेटी की अनुसंशाओं को लागू करने का वादा किया. बढ़ती मंहगाई के लिए बाहरी तत्वों को जिम्मेदार ठहराया. आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए खूफिया तंत्र को सुदृढ़ करने की बात कही.

2009: यूपीए की वापसी

गरीबी रेखा से नीचे खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया. सूचना का अधिकार कानून को और सुदृढ़ करने की बात कही. प्रतिदिन 20 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा.

2010: बढ़ती महंगाई के प्रति चिंता जाहिर की.

महंगाई चिंता का विषय है. हम इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं. जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा.

2011: नया भूमि अधिग्रहण कानून

अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून को बदलकर नया भूमि अधिग्रहण कानून लाने की बात कही. नक्सलवाद से प्रभावित 60 पिछड़े और आदिवासी बाहुल्य जिलों के लिए 3300 करोड़ रुपये विकास योजना की घोषणा की. मंहगाई पर चिंता जाहिर की और इसे कम करने के उपायों की बात कही.

2012: लोकपाल बिल लाने की घोषणा की

सरकार और प्रशासन के काम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का हमारा संकल्प बरकरार है. हम लोकपाल बिल जल्द ही लाएंगे.

2013 : तरक्की के दस साल

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दस सालों में जैसी प्रगति हमने की है, यदि हम आगे भी उसे जारी रखें, तो वह वक्त दूर नहीं, जब भारत को ग़रीबी, भूख, बीमारी और अशिक्षा से संपूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी.

सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव को बैकफुट पर धकेल कर उनके मंत्री आजम खान और कुछ अन्य मुस्लिम नेता भले ही फूले नहीं समा रहे हों, लेकिन परिक्रमा पर रोक की खबर से विहिप और संत–समाज में खासी नाराजगी है. मुलायम की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे विहिप नेताओं ने 24 घंटे के भीतर ही सुर बदल लिए. विहिप ने इसे एक मुस्लिम समुदाय को खुश करने वाला कदम बताया.

मुलायम सिंह

पल में तोला पल में माशा

आगामी लोकसभा चुनाव में हिंदू और मुस्लिम वोटों पर पकड़ बनाने की कवायदों के चलते सपा सुप्रीमो और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कशमकश आजकल देखते ही बन रही है. वे विहिप से मुलाकात कर राममंदिर और 84 कोसी परिक्रमा पर चर्चा करते हैं, आश्वासन देते हैं, तो अगले ही दिन मुसलमानों की नाराजगी कम करने के लिए यात्रा को प्रतिबंधित कर यूटर्न ले लेते हैं. वे दोनों समुदाय को साधने की कोशिश में लगे हैं और दोनों समुदाय के लोग, जो अपने-अपने हितों को लेकर सक्रिय हैं, उनसे नाराज चल रहे हैं.

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली जबरदस्त कामयाबी का खुमार पार्टी नेताओं के दिलो–दिमाग से उतर गया है. अब उन्हें 2014 का लोकसभा चुनाव दिखाई दे रहा है, जहां उनकी राह एकदम आसान नहीं दिख रही. पिछले डेढ़ वर्षों में प्रदेश के राजनीतिक हालात काफी बदल चुके हैं. 2012 में सपा के सामने बसपा राज की खामियां गिनाने के लिए कई मुद्दे थे. जनता को विश्वास करने के लिए अखिलेश यादव जैसा युवा नेता था. वहीं माया की तानाशाही थी, पत्थरों पर पानी की तरह पैसा बहाने की अतिशयता थी, और जनता बेलगाम भ्रष्टाचार से त्रस्त थी, लेकिन 2014 में ऐसा कुछ नहीं होगा. समाजवादी पार्टी को आम चुनाव में बढ़त बनाने के लिए अपनी ही सरकार की नाकामयाबी पर पर्दा डालना होगा. खासकर कानून व्यवस्था को लेकर उसके सामने काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. सपा नेताओं को राष्ट्रीय राजनीति में छाये ङ्कमोदी फैक्टरफका भी सामना करना होगा. ऐसे में सपा के थिंक टैंक का चिंतित होना लाजिमी है.

बदले राजनीतिक परिदृष्य ने सपा नेताओं, यहां तक की खुद पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को भी पाला बदल–बदलकर आगे की रणनीति तय करने को मजबूर कर दिया है. मुस्लिम मत सपा के खाते में गिरेंगे या नहीं, इस बात को लेकर सपा नेतृत्व के माथे पर लकीरें साफ देखी जा सकती हैं. उसे चिंता सता रही है कि कहीं मोदी को हाशिये पर डालने के चक्कर में मुस्लिम वोट उसकी झोली से निकलकर कांग्रेस की झोली में न चले जाएं. इसी चिंता ने मुलायम जैसे धुरंधर नेता को बेचैन कर दिया है. इसी बेचैनी ने सपा सरकार ने हिंदू–मुस्लिम सभी धर्मगुरुओं के स्वागत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास पर एक दिन मुस्लिम धर्मगुरुओं का स्वागत होता है तो दूसरे दिन विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेताओं और संतों के साथ सीएम और सपा प्रमुख मुलाकात करते हैं. वे विहिप को प्रस्तावित 84 कोसी परिक्रमा में सहयोग का अश्वासन देते हैं, फिर दो दिन बाद उस पर प्रतिबंध लगाकर अगले दिन राज्य की 30 विभागों की 85 योजनाओं में अल्पसंख्यकों को 20 प्रतिशत कोटे की घोषणा करते हैं. सपा आलाकमान के बीच यह बेचैनी तब और बढ़ जाती है जब नरेंद्र मोदी सरीखा नेता दिल्ली में बैठकर देशभर के मुस्लिम वोटों को हासिल करने की रणनीति बनाने लगता है. इस भाजपाई पैंतरे पर सपा नेतृत्व अपने को हिंदुत्व के थोड़ा करीब लाने की कोशिश करता है. गत दिनों दबे कदमों से ही सही, मुलायम और उनकी सरकार लखनऊ में विहिप के करीब दिखी तो कई राजनीतिक पंडितों का गणित गड़बड़ा गया. विहिप नेताओं से सपा प्रमुख मुलायम सिंह और मुख्यमंत्री अखिलेश मिलने को लेकर कितने गंभीर थे, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि विहिप नेताओं और साधु–संतों से मुलाकात के लिए 17 अगस्त को विकास के एजेंडे पर आयोजित मुख्यमंत्री की प्रेस कांफ्रेस तक को दो घंटे खिसका दिया गया.

ताजा हालात पर गौर किया जाए तो लग रहा था कि सपा खेमे में एक नयी तरह की राजनीति करवट ले रही है, जिसमें सपा आलाकमान द्वारा मौलानाओं और संतों को एक साथ साधने की कोशिश की जा रही है. वहीं मुलायम को खलनायक की उपाधि देने वाले विहिप नेता उनकी सरपरस्ती में अयोध्या विवाद हल हो जाने का सपना देखने लगे हैं. वैसे विहिप का विश्वास कुछ हद तक सही भी था, क्योंकि सपा प्रमुख की तरफ से भी यह संकेत आने लगे थे कि अयोध्या मंदिर विवाद के समाधान में उनकी तरफ से कुछ गलतियां हो गई थीं. अयोध्या विवाद के लिए मध्यस्थता की बात जब संतों ने की तो मुलायम चुप रहे, जिसको लेकर भी अटकलें लगाई जाने लगीं. बात आगे बढ़ती इससे पहले ही तुनकमिजाज नेता और मंत्री आजम खान साहब ने आस्तीनफ चढ़ा ली. विहिप नेताओं से मुलाकात पर सवाल खड़ा करते हुए आजम यहां तक कह गए कि बाबरी मस्जिद विध्वंसकारियों को मुलायम महत्व दे रहे हैं। इस मुलाकात ने मुस्लिमों का जख्म कुरेदा है. मुस्लिम समाज में गलत संदेश जा रहा है. शायद आजम की नाराजगी के बाद ही विहिप की 84 कोसी परिक्रमा पर सरकार ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी. उधर, राजनीति के जानकार कहते हैं कि आजम ने भले ही अपनी नाराजगी विहिप–मुलायम की मुलाकात के बहाने प्रकट की हो, लेकिन इसकी वजहें और भी थीं. बीच–बीच में मुलायम का बुखारी प्रेम उजागर होने जैसे तमाम मसलों को लेकर आजम पार्टी आलाकमान से खफा चल रहे थे. विहिप नेताओं से सपा नेताओं और सीएम की मुलाकात रिहाई मंच को भी रास नहीं आई. रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शोएब ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह मुलायम सिंह और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विहिप नेताओं के साथ बैठकें करने लगे हैं, उससे प्रदेश की जनता को समझ लेना चाहिए कि सपा और भाजपा में 2014 के लिए अंदरूनी गठजोड़ हो गया है. और ये दोनों पार्टियां अब पूरे सूबे में हिंदुओं और मुसलमानों के ध्रुवीकरण के लिए दंगे कराने का खेल खेलेंगी. उन्होंने कहा कि सपा के मुस्लिम मंत्रियों और नेताओं को मुसलमानों के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि वे अशोक सिंघल और मुलायम की मुलाकात के बारे में क्या सोचते हैं. आजम और अन्य मुस्लिम संगठनों की नाराजगी को कम करने के लिए ही मुलायम को एक दिन की चुप्पी के बाद अयोध्या विवाद में किसी तरह की मध्यस्थता से इन्कार करना पड़ गया. गौरतलब है कि 17 अगस्त को विहिप के संरक्षक अशोक सिंहल और कई संतों की मौजूदगी में स्वामी चिन्मयानंद ने मुलायम से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने दावा किया था कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव मंदिर मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। इन नेताओं का कहना था कि मुलायम भी इस बात से सहमत हैं कि इस समस्या के समाधान में बहुत समय लग चुका है. अब और समय नहीं लगना चाहिए. खबर यह भी चली कि विहिप नेता अशोक सिंहल व चिन्मयानंद के साथ संतों का प्रतिनिधिमंडल जब लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पहुंचा तो सीएम अखिलेश यादव ने सभी का गर्मजाशी से स्वागत किया. इसी बीच वहां मुलायम सिंह यादव भी पहुंच गए और सभी का जोरदार अभिवादन किया. संतों के अनुसार, मुलायम व मुख्यमंत्री का रुख पूरी तरह सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण रहा. बातचीत के बाद मुलायम सभी को गाड़ियों तक छोड़ने आए और पूरे आदरभाव के साथ विदा किया. सब कुछ ठीकठाक निपट गया था लेकिन आजम के एक बयान के बाद हालात बदलते देर नहीं लगी. मुलायम ने मध्यस्थता की बात से यूटर्न लिया तो राज्य सरकार ने अयोध्या में 25 अगस्त से 13 सितंबर तक चलने वाली चौरासी कोसी परिक्रमा को हरी झंडी देने से इन्कार करने में ही भलाई समझी. बात यहीं नहीं रुकी. डैमेज कंट्रोल के तहत 19 अगस्त को गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को कानपुर में कुशीनगर एक्सप्रेस से उस समय उतार लिया गया, जब वह झांसी स्थित महाकालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे. इस पर पर कब्जे और पूजा–पाठ को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है. सांसद को सुबह तक पड़ोसी जिला उन्नाव के पक्षी विहार में बैठाए रखा गया. सुबह उन्हें और उनके साथ जा रहे राकेश सिंह बघेल को जर्बदस्ती दिल्ली जाने वाले विमान में बैठा दिया गया. उनके साथ रोके गए और लोगों को पुलिस प्रशासन ने अपनी कस्टडी में गोरखपुर भेज दिया. यह सब तब हुआ, जबकि झांसी प्रशासन ने योगी को मंदिर आने की इजाजत दे रखी थी और कहीं किसी तरह का कोई तनाव भी नहीं था.

खैर, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव को बैकफुट पर धकेल कर उनके मंत्री आजम खान और कुछ अन्य मुस्लिम नेता भले ही फूले नहीं समा रहे हों, लेकिन परिक्रमा पर रोक की खबर से विहिप और संत–समाज में खासी नाराजगी है. मुलायम की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे विहिप नेताओं ने 24 घंटे के भीतर ही सुर बदल लिए. विहिप ने इसे एक मुस्लिम समुदाय को खुश करने वाला कदम बताया.

हालात दिन पर दिन सपा के लिए दुश्वारी वाले होते जा रहे हैं. 2014 पर नजर लगाए सपा आलाकमान सबको खुश करने के चक्कर में फंसता ही जा रहा है. उसके सामने ऐसी–ऐसी मांगें रखी जा रही हैं जिसे पूरा करना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल नहीं है. विहिप नेताओं ने जो उम्मीद मुलायम से लगाई थी, वह तो 24 घंटे में टूट ही गई. वही गत दिनों युवा सीएम अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे मुस्लिम धर्मगुरु भी मांगे न पूरी होने से नाराज हैं. धार्मिक जुलूस के विवाद को लेकर शिया–सुन्नी दोनों ही तबके सरकार से नाराज चल रहे हैं. मुसलमानों को आरक्षण, जेलों में बंद मुस्लिम युवाओं की रिहाई आदि का मसला सपा का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है. बसपा राज में जो लोग जूतियां उतारकर मुख्यमंत्री के सामने खड़े होते थे, निजाम बदलते ही बेकाबू हो गये हैं. सपा की स्थिति को देखकर बसपा और भाजपाई फूले नहीं समा रहे हैं. बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि सीएम प्रदेश के विकास से अधिक राजनीतिक बिसात की गोटें बिछाने में लगे रहते हैं. उनके ऊपर जो चाहता है, आकर दबाव बना लेता है. सपा सरकार पापा और चाचाओं की कठपुतली बन गई है. जहां फैसले कहीं लिए जाते हैं और सुनाए कहीं और जाते हैं.■

आजम और अन्य मुस्लिम संगठनों की नाराजगी को कम करने के लिए ही मुलायम को एक दिन की चुप्पी के बाद अयोध्या विवाद में किसी तरह की मध्यस्थता से इन्कार करना पड़ गया. गौरतलब है कि 17 अगस्त को विहिप के संरक्षक अशोक सिंहल और कई संतों की मौजूदगी में स्वामी चिन्मयानंद ने मुलायम से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने दावा किया था कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव मंदिर मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। इन नेताओं का कहना था कि मुलायम भी इस बात से सहमत हैं कि इस समस्या के समाधान में बहुत समय लग चुका है.

विहिप नेताओं से मुलाकात पर सवाल खड़ा करते हुए आजम यहां तक कह गए कि बाबरी मस्जिद विध्वंसकारियों को मुलायम महत्व दे रहे हैं। इस मुलाकात ने मुस्लिमों का जख्म कुरेदा है. मुस्लिम समाज में गलत संदेश जा रहा है. शायद आजम की नाराजगी के बाद ही विहिप की 84 कोसी परिक्रमा पर सरकार ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी.

feedback@chauthiduniya.com

मनमोहन सिंह ने कहा कि रिजर्व बैंक की पॉलिसी रही है लुकिंग बैक ऐंड लुकिंग अहेड. लुकिंग बैक में तो 1991 के हालात दिखते हैं और जब हम लुकिंग अहेड की बात करते हैं, तो रुपया तेजी से गिरता और सेंसेक्स सिसकता नजर आता है. यह वही मनमोहन सिंह हैं, जिन्होंने 1993 में वित्त मंत्री रहते हुए रुपया को परिवर्तनीय बनाया था. उनके इस कदम से विदेशी निवेश में तेज वृद्धि हुई और आर्थिक विकास की गति बढ़ी, लेकिन आज मनमोहन सिंह का कोई उपाय काम नहीं कर रहा है.

दबंग डॉलर

रोता रुपया

सिसकता सेंसेक्स

पिछले दस वर्षों में रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर है. दबंग डॉलर उसे अभी कितना नीचे ले जाएगा, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी रुपये का गिरना जारी है. भारतीय अर्थव्यवस्था में इस बात को लेकर निराशा का माहौल है कि गिरते रुपये से देश आर्थिक बदहाली की स्थिति में न पहुंच जाए.

राजीव रंजन

रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम का विश्वास अभी भी ऊंचे स्तर पर बना हुआ है. जैसा वे स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रुपये के तेजी से गिरते स्तर को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा. अगर स्थितियां पटरी पर आती भी हैं, तो निवेशकों, शेयर बाजार, ग्राहकों सहित कंपनियों का विश्वास लौटने में समय लग सकता है. इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर पीएम ऐसा क्यों कह रहे हैं. क्या पीएम जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह सब कह रहे हैं या फिर अर्थव्यवस्था सचमुच जल्द ही पटरी पर आ जाएगी. कम से कम रुपया जिस तेजी से अपना मूल्य खोता जा रहा है, उसे देखकर तो यह कहना बेमानी है. एक बड़ा सवाल यह भी है कि पीएम की बातों पर विश्वास कैसे हो. अगर पीएम इतने सक्षम होते या उनके आर्थिक विभागों की नीतियां इतनी कारगर होतीं, तो यह स्थिति आती ही क्यों? अभी हाल यह है कि चाहे आरबीआई हो या वित्त मंत्री या सरकार के अन्य विभाग, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सभी हाथ-पांव मार रहे हैं, लेकिन किसी कि एक भी नहीं चल रही है और रुपया फुल स्पीड में नीचे लुढ़क रहा है.

क्यों गिर रहा है रुपया

फेडरल रिजर्व की ओर से क्यूई नीति को वापस लेने की घोषणा के बाद से ही रुपये की कीमत में गिरावट आ रही है. लिक्विडिटी कम करने के लिए आरबीआई के शॉर्ट टर्म रेट में इजाफा करने के बाद भी रुपया गिरता गया. फलस्वरूप आरबीआई ने देश से बाहर जाने वाले डॉलर प्रवाह पर रोक लगाने के मकसद से निवेशकों और कंपनियों पर प्रतिबंध लाद दिए, जिससे निवेशकों में हड़कंप मच गया. इन कारणों ने मिलकर रुपये की स्थिति बदतर कर दी. रही बात सेंसेक्स की, तो पिछले कुछ दिनों से सेंसेक्स लगातार नीचे गिरता जा रहा है. सरकार सोचती है कि एफडीआई बढ़ाने से बड़े पैमाने पर निवेश होगा, लेकिन वह भूल जाती है कि जब तक निवेशकों को इस बात की गारंटी नहीं मिलती कि गैरकानूनी रूप से बिना पैसा दिए आसानी से कारोबार किया जा सकता है, जब तक देश में कारोबारी माहौल पैदा नहीं होता, निवेशक भारत की तरफ कभी आकर्षित नहीं होंगे. हम गलतफहमी में जी रहे हैं. वास्तविकता तो यह है कि एफआईआई हो या एफडीआई, दोनों तरह के निवेश की पहली पसंद अब भारत नहीं रह गया है. प्रधानमंत्री एक जाने-माने अर्थशास्त्री भी हैं. बावजूद इसके, देश की अर्थव्यवस्था और बाजार इस स्थिति में है. पीएम को चाहिए कि देश में फैली निराशा को दूर करें और एक नया विजन पेश कर देश की अर्थव्यवस्था को इस भंवर से निकालें. सालों से भ्रष्टाचार, लालफीताशाही ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिससे निवेशक यहां से भाग रहे हैं. पीएम द्वारा 1991 की बात करना उस समय की डरावनी तस्वीर पेश करने के समान है. 1991 की स्थिति भले अभी नहीं आई है, लेकिन उस तरह की स्थिति का देश को सामना करना पड़ सकता है. कमजोर रुपया भारतीय मुद्रा संकट को बढ़ावा देगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर यह कमजोरी विदेशी लेनदारों के बकाया भुगतान को कठिन बना देती है, तो ऐसे में यह एक समस्या बन सकती है.

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक के नये गवर्नर रघुराम राजन अपने प्रोफेशनल स्किल और अनुभव से पॉलिसी को सुलझाएंगे. यहां यह सवाल उठता है कि पुराने गवर्नर के पास क्या स्किल की कोई कमी थी. अगर नहीं, तो अर्थव्यवस्था की यह स्थिति क्यों हुई. दूसरी बात यह है कि नये गवर्नर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सुझाव तो दे ही रहे होंगे, उनके पास प्रोफेशनल स्किल और अनुभव की कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके रुपया क्यों गिरता जा रहा है.

मनमोहन सिंह ने कहा कि रिजर्व बैंक की पॉलिसी रही है लुकिंग बैक ऐंड लुकिंग अहेड. लुकिंग बैक में तो 1991 के हालात दिखते हैं और जब हम लुकिंग अहेड की बात करते हैं, तो रुपया तेजी से गिरता और सेंसेक्स सिसकता नजर आता है. वैसे भी सेंसेक्स का ऊपर चढ़ना इस बात पर निर्भर करता है कि देश की अर्थव्यवस्था का सेंटिमेंट कैसा है. दुर्भाग्य से इस समय सेंटिमेंट ठीक नहीं है. यह वही मनमोहन सिंह हैं, जिन्होंने 1993 में वित्त मंत्री रहते हुए रुपये को परिवर्तनीय बनाया था. उनके इस कदम से विदेशी निवेश में तेज वृद्धि हुई और आर्थिक विकास की गति बढ़ी, लेकिन आज मनमोहन सिंह का कोई उपाय काम नहीं कर रहा है.

पिछले दिनों वित्त मंत्री पी.चिदंबरम ने भी कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था किसी भी बड़े संकट से दूर है. चिदंबरम ने ग्लोबल स्थितियों को वजह बताते हुए कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट मंदी के दौर से गुजर रहा है. ऐसे में इंडियन इकोनॉमी पर भी असर पड़ना लाजिमी है, लेकिन यह दौर जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन वित्त मंत्री रुपये के गिरने की गति देख कर खुद ही हैरान हैं. ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रुपये की अस्थिरता को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए. कई प्रयास किए गए, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद रुपया अस्थिर बना हुआ है. निकट भविष्य में रुपये की अस्थिरता दूर होने के आसार भी नहीं हैं. ऐसे में उनकी यह भविष्यवाणी टांय-टांय फिस्स ही साबित हो रही है. गिरते रुपये का क्या असर हो सकता है, इसके बारे में आइए हम जान लेते हैं.

क्या होगा असर

आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि रुपये की गिरावट सिर्फ बड़ी-बड़ी कंपनियों को ही प्रभावित करेगा, लेकिन रुपये के गिरने से रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे खान-पान और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी महंगी होंगी. अगर आपका कोई बच्चा विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहा है और उसके शिक्षा मद में 10 फीसद की वृद्धि हो जाती है, तो समझिए कि आपके पॉकेट पर 3 लाख रुपये का भार आ जाएगा. मतलब साफ है, रुपया में उतार-चढ़ाव बड़ी कंपनियों या दलाल स्ट्रीट तक सीमित नहीं है, बल्कि घर के खर्चे को भी यह सीधे तौर पर प्रभावित करेगा.

खर्च चलाना होगा महंगा

रुपये के गिरते स्तर से आपके आस-पास की चीजें महंगी होंगी, यह तय है. रुपया कमजोर होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें प्रभावित होंगी. नतीजा, ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी, दूसरे देशों से आने वाले समान महंगे हो जाएंगे. साबुन, डिटरजेंट, डियोडरेंट और शैंपू भी महंगे हो सकते हैं. इसके अतिरिक्त जो भी वस्तुएं विदेशों से आयात होती हैं, उसके मूल्य में वृद्धि अवश्य होगी.

इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रुलाएंगे

रुपये के गिरते स्तर से इलेक्ट्रॉनिक चीजों जैसे कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल फोन, एसी, फ्रिज आदि भी महंगी होंगी, क्योंकि सभी में आयातित कॉम्पोनेंट का प्रयोग होता है. डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये के कारण ऑटो उद्योग भी महंगा हो सकता है. चूंकि ऑटो उद्योग में बहुत सारे पार्ट्स आयात करने पड़ते हैं, इसलिए ऑटो कंपनियों के पास कार की कीमत बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा.

विदेशों में पढ़ना नहीं होगा आसान

स्टूडेंट्स की चाह होती है विदेश में रहकर पढ़ाई करना, लेकिन गिरते रुपये के कारण यह चाह अब महंगी होने वाली है. चूंकि विदेश में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी रुपये में लोन लेते हैं, लेकिन उनका सारा खर्च विदेशी मुद्रा में होता है. इसका सीधा असर विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रखने वाले बच्चों पर पड़ेगा. यानी विदेश में रहना और पढ़ना महंगा हो जाएगा.

वेतन कटौती का भी टेंशन

अभी ज्यादा वर्ष नहीं बीते हैं, जब अमेरिकी मंदी के कारण भारत में नौकरियां खतरे में पड़ने लगी थीं. अगर रुपया इसी तरह से गिरता रहा, तो यह लोगों की नौकरी और वेतन कटौती का कारण भी बन सकता है. जो इंडस्ट्री आयात पर निर्भर हैं, वह प्रोडक्शन और ऑपरेशन लागत पर बढ़ते बोझ को महसूस करेंगी. इससे निपटने के लिए कंपनियां लागत को नियंत्रित करना चाहेंगी. इसके लिए वह लोगों की छंटनी कर सकती हैं.

जेब करनी होगी ढीली

रुपये का गिरता स्तर आम आदमी की जेब ढीली करेगा. अगर आप टीवी, फ्रिज, एसी, ओवन, वॉशिंग मशीन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदना चाहते हैं, तो अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए. ज्यादातर टिकाऊ उपभोक्ता सामान कंपनियां एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग नॉर्म्स में बदलावों और रुपये के डेप्रिसिएशन से आने वाली अतिरिक्त लागत के प्रभाव को कम करने के लिए कीमतों में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने ही वाली हैं. बाजार को ध्यान में रखते हुए कुछ कंपनियां अपने उत्पादों की कीमत बढ़ाने की योजना तैयार कर ली हैं, तो कुछ रुपये के उतार-चढ़ाव पर निगाह रखे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

रघुराम राजन की चुनौतियां

रघुराम राजन, आरबीआई के नवनियुक्त गवर्नर हैं, जिन्होंने कहा है कि यह चुनौतीपूर्ण समय है और हम इन चुनौतियों से पार पा लेंगे. भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय चालू खाता घाटा, रुपये में गिरावट, विदेशी निवेश में कमी और विकास दर में कमी जैसे चौतरफा दबावों से जूझ रही है. ऐसे में 5 सितंबर से रिजर्व बैंक के गवर्नर की ज़िम्मेदारी संभाल चुके रघुराम राजन के लिए यह तलवार की धार पर चलने जैसा है. अब देखना यह होगा कि राजन देश की अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाते हैं. हालांकि उनके शानदार करियर और अनुभव को देखते हुए उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता. बतौर गवर्नर उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना है, उसमें सोने के आयात को नियंत्रित करना भी शामिल है. इसके अतिरिक्त राजन के समक्ष जो अन्य चुनौतियां हैं, वे हैं :

- भारत को 1991 जैसे भुगतान संतुलन के संकट से बचाना.
- अत्यधिक राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति से निपटना.
- विदेशी निवेशक भारत से निकलना चाह रहे हैं, उनमें विश्वास लौटाना होगा.
- आर्थिक विकास दर तेज करना, जो घटकर पांच प्रतिशत से कम हो गई है.
- विदेशी मुद्रा देश से बाहर जा रही है, उसे रोकना होगा. अन्यथा गंभीर संकट पैदा हो जाएगा.
- विदेशी देनदारी चुकाने को लेकर देश के समक्ष संकट पैदा हो सकता है.
- केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीति के जरिये उद्योगों को राहत देने की स्थिति में नहीं हैं.
- सुधारों की प्रक्रिया में पिछड़ने के कारण विकास को झटका, जिसे फिर से पटरी पर लाना होगा.
- विदेशी निवेशकों की पूंजी की कीमत घटती जा रही है, जिसे रोकना होगा. ■

रुपये का सफर

भारतीय मुद्रा की स्थिति पिछले दो वर्षों से काफी डावांडोल है, जबकि 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब भारतीय रुपये का मूल्य अमेरिकी डॉलर के बराबर ही था. आज डॉलर की कीमत लगभग 64 रुपये है. इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय रुपये में पिछले 66 वर्षों में डॉलर की तुलना में 64 गुना गिरावट आई है. पिछले तीन महीनों से वृद्धि, महंगाई, व्यापार और निवेश से जुड़े आंकड़ों के प्रभाव से रुपये की स्थिति अत्यधिक कमजोर हो गई है. आजादी के बाद भारत ने जन कल्याण और विकास योजनाओं के लिए धन जुटाने की खातिर विदेशों से कर्ज लेना शुरू किया. साथ ही चीन और पाकिस्तान के साथ युद्धों के कारण भी रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा.

1991 का गंभीर संकट

भारत के सामने 1991 में भुगतान संतुलन का एक गंभीर संकट पैदा हो गया था. भारत को अपनी मुद्रा में तीव्र गिरावट करनी पड़ी. देश उस समय महंगाई, कम वृद्धि दर और विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहा था. गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय विदेशी मुद्रा तीन हफ्तों के आयात के लिए भी पर्याप्त नहीं थी. हालात इतनी भयावह थी कि रुपये का अवमूल्यन करके उसकी कीमत 17.90 रुपये प्रति डॉलर तय करनी पड़ी. भारत के ख़जाने में विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर था. ऐसी स्थिति में सरकार को अपने आयात के खर्च को पूरा करने के लिए देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था.

वेंटिलेटर पर रुपया

रुपया वेंटिलेटर पर है. जिस तरह से रुपये में गिरावट हो रही है, उससे आने वाले दिनों में लोगों की क्रय शक्ति प्रभावित होगी. जो सामान आपको जनवरी में 100 रुपये में मिल रहा था, वह अब 116 रुपये में मिलेगा. इस साल की शुरुआत से अब तक रुपये में 20 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है. ऑटो और होम लोन के ईएमआई पर भी आपको ज्यादा चुकाना होगा. रुपये के गिरते स्तर का असर बैंक द्वारा दिए जाने वाले ग्राहकों के लोन पर भी पड़ेगा. भारत प्रमुख तेल आयातक देश है. चूंकि यहां की तेल कंपनियां तेल को शोधित कर तेल पंपों को बेचती हैं, इसलिए रुपये के गिरने से तेल कंपनियों पर बोझ बढ़ेगा, जिससे वे बाध्य होकर तेल का मूल्य बढ़ाएंगी. मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी, जिससे आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी. खासतौर पर कोयला, तेल और गोल्ड के मूल्य में बढ़ोत्तरी होगी. तैयार माल के मूल्य में भी वृद्धि होगी. रुपया में जैसे-जैसे गिरावट दर्ज की जाएगी, मुद्रास्फीति की दरों में भी वृद्धि दर्ज की जाएगी. विदेशों में पढ़ाई अब महंगी हो जाएगी. एसोचेम ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका जाना पहले की तुलना में 2 से 4 लाख रुपया तक महंगा हो सकता है. विदेशों में छुट्टियां मनाना भी अब महंगा हो जाएगा. हालांकि रुपये के गिरने से प्रवासी भारतीयों को फायदा होगा, क्योंकि डॉलर या अन्य मजबूत करेंसी के बदले उन्हें ज्यादा रुपया मिलेगा. निर्यात के लिए यह तो शुभ होगा, लेकिन आयात के लिए अशुभ, क्योंकि जब आयातक विदेशों से कोई वस्तु आयात करेंगे, तो निर्यातक देश को पहले की तुलना में ज्यादा रुपया चुकाना होगा. ठीक इसके विपरीत स्थिति निर्यात करने पर होगी. रुपये का गिरना तेल, गोल्ड और अन्य वस्तुओं के आयात बिल को भी बढ़ा देगा, जिससे चालू खाते का घाटा और अधिक बढ़ जाएगा. यह अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा. रुपये का गिरना कॉर्पोरेट सेक्टर के बैलेंस शीट को भी बिगाड़ेगा. भारतीय कंपनियों को विदेशों से अधिक ब्याज दर पर लोन मिलेगा, जो उनके लोन चुकाने के इंस्टॉलमेंट दर को बढ़ा देगा.

पिछले दिनों लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान ने अपने अभिनेता पुत्र चिराग पासवान को लोजपा के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया. सूत्र बताते हैं कि पासवान के इस निर्णय से पार्टी के कई युवा कार्यकर्ता नाराज हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष तर्क देते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं की जोरदार मांग के बाद ही मैंने यह निर्णय लिया है.

बिहार की राजनीति में वंशवाद की बेल

बिहार की राजनीति में वंशवादी परंपरा उतनी ही पुरानी है, जितना पुराना बिहार का अस्तित्व. वर्तमान में लालू और रामविलास पासवान सरीखे नेताओं ने भी अपने पुत्रों को राजनीति के अखाड़े में उतार दिया है. हालांकि इनमें से कई नेता पुत्र लोकसभा और विधान मंडल तक तो पहुंचे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए.

शशि सागर

परिवर्तन रैली के बहाने लालू-राबड़ी भी अपने दोनों पुत्र तेजप्रताप और तेजस्वी को राजनीति में ला चुके हैं. तेजस्वी आठ साल की उम्र से ही घर से बाहर रहे हैं, जबकि तेजप्रताप मां और मामा के स्नेह में पले-बढ़े हैं. 1990 के दौरान अणे मार्ग में आए एक अतिथि ने तेजप्रताप से पूछा था कि बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उसी समय लालू ने कहा था कि बड़ा होकर बिहार का सीएम बनेगा और क्या. तेजप्रताप ने तो कई सालों तक दिल्ली में रह कर किसी परीक्षा की तैयारी भी की है.

पटना में बातचीत के दौरान एक साथी वाकया सुनाते हैं. कहते हैं कि जिन दिनों राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं, उन्ही दिनों हमारी एक मित्र भी विधायक थीं. एक दिन वे मुख्यमंत्री से मिलने जा रही थीं, तब वे हमें भी साथ ले गईं. वे सीएम के कक्ष में चली गईं. तभी मैंने देखा कि तेजस्वी बैटिंग कर रहा है और कुछ अधिकारी–पदाधिकारी फिल्डिंग और बॉलिंग. कुछ देर बाद तेजस्वी दौड़ता हुआ ऊपर चला गया. मैंने वहां मौजूद फिल्डरों से पूछा, क्या जी क्रिकेट बंद हो गया, तो एक अधिकारी ने जवाब दिया कि नहीं, साहब गए हैं पानी पीने, फिर खेल होगा. साथी कहते हैं कि पता नहीं क्यों, जिस सुविधा के माहौल में तेजस्वी को क्रिकेट खेलते मैंने देखा, मुझे उसी समय लगा कि यह लड़का कुछ और भले ही बन जाए, लेकिन क्रिकेटर नहीं बनेगा. साथी की सोची हुई बात सही साबित हुई. तेजस्वी क्रिकेटर तो नहीं बन पाए, लेकिन अब पिता की विरासत संभालने, उन्हें भंवर जाल से उबारने राजनीति में जरूर आ चुके हैं.

हाल के दिनों में तेजप्रताप, तेजस्वी और चिराग अपने पिता के खेवनहार बनकर उन्हें पार लगाने आए हैं, बिहार की वंशवादी परंपरा उतनी ही पुरानी है, जितनी पुरानी बिहार का अस्तित्व. कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें, तो यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह के समय से ही चलता आ रहा है. उस समय ही 1950 में उप मुख्यमंत्री रहे एएन सिन्हा ने अपने बेटे एसएन सिन्हा को राजनीति में ला दिया था. आठ बार औरंगाबाद लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले एसएन सिन्हा 1980 के दशक में मुख्यमंत्री भी बने. श्रीकृष्ण सिंह के भाई बंदी शंकर सिंह भी कैबिनेट मिनिस्टर थे. अभी एस एन सिन्हा के परिवार के कई लोग सत्ता में सक्रिय हैं. फिलहाल तीसरी पीढ़ी के निखिल कुमार केरल के राज्यपाल हैं.

बहरहाल, गत दिनों लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान ने अपने अभिनेता पुत्र चिराग पासवान को लोजपा के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है. सूत्र बताते हैं कि पासवान के इस निर्णय से पार्टी के कई युवा कार्यकर्ता नाराज हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष तर्क देते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं के जोरदार मांग के बाद ही मैंने यह निर्णय लिया है. ज्ञात हो कि रामविलास पासवान इससे पहले भी अपने परिवार और संबंधियों को राजनीति में ला चुके हैं. बावजूद इसके, लोजपा का कोई प्रतिनिधित्व कर सके, इसे मजबूत कर सके, ऐसा नहीं हुआ. पासवान को अब अपने अभिनेता पुत्र से ही उम्मीद बची है. चिराग का प्रयोग कहां तक सफल होगा. इसके जवाब में पार्टी के महासचिव रोहित सिंह कहते हैं कि चिराग ने अगर कड़ी मेहनत न की होती, तो प्रभुनाथ सिंह की जीत का अंतर इतना बड़ा नहीं होता. रोहित सिंह उन लोगों को भी खारिज करते हैं, जो चिराग को लोजपा में ऊपर से थोपा गया नेता मानते हैं. चिराग का अचानक से राजनीति में प्रवेश नहीं हुआ है. इससे पहले भी वे 2009 में पिता के लिए वोट मांगते हुए वह देखे गए हैं.

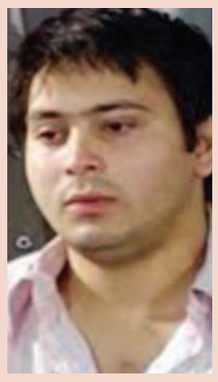

परिवर्तन रैली के बहाने लालू–राबड़ी भी अपने दोनों पुत्र तेजप्रताप और तेजस्वी को राजनीति में ला चुके हैं. तेजस्वी आठ साल की उम्र से ही घर से बाहर रहे हैं, जबकि तेजप्रताप मां और मामा के स्नेह में पले–बढ़े हैं. 1990 के दौरान अणे मार्ग में आए एक अतिथि ने तेजप्रताप से पूछा था कि बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उसी समय लालू ने कहा था कि बड़ा होकर बिहार का सीएम बनेगा और क्या. तेजप्रताप ने तो कई सालों तक दिल्ली में रह कर किसी परीक्षा की तैयारी भी की है. उसके बाद ही तेज का नामांकन बीएन कॉलेज, पटना में बतौर पॉलीटिकल साइंस के छात्र के रूप में करवाया गया. तेजप्रताप अपने फर्स्ट ईयर की परीक्षा को भी पास नहीं कर पाए. इसके बाद पिता ने उन्हीं के नेतृत्व में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़वाया. उसमें भी तेज असफल ही रहे. पांच सालों तक दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के सदस्य रहे तेजस्वी कभी क्रिकेट नहीं खेल सके. यह भी सच है कि कम से कम तेजस्वी और चिराग ने कभी राजनीति को करियर बनाने का नहीं सोचा था. दोनों ने ग्लैमर को करियर के रूप में अपनाया. वहां उनका सिक्का चला नहीं, अब ये राजनीति में भाग्य आजमा रहे हैं. सवाल यह उठता है कि क्या ये अपने पिता की डूबती नैया को पार लगा पाएंगे?

वैसे पुत्र के मोहपाश में फंस कर निर्णय लेने वाले लालू और पासवान ही नहीं हैं. ऐसे नेताओं की बिहार में लंबी फेहरिस्त है. कांग्रेसी दलित नेता जगजीवन राम पहले ऐसे नेता हुए, जिन्होंने अपने बेटे को 1969 में ही कैबिनेट मिनिस्टर का पद दिलवा दिया था. फिलहाल उनकी पुत्री मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष पद की शोभा बढ़ा रही हैं. ऐसे कई और नेता पुत्र हुए, जो लोकसभा और विधान मंडल तक तो पहुंचे, लेकिन कुछ खास कर नहीं कर पाए. पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर भी मंत्री बने, पर अपनी पहचान नहीं बना पाए. इसी तरह ललित नारायण मिश्र के बेटे विजय शंकर मिश्र भी कई बार विधायक तो बने, लेकिन अपनी कोई छाप नहीं छोड़ सके.

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीपी ठाकुर ने आखिर अपने बेटे विवेक को विधान परिषद पहुंचा ही दिया. कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्रा तमाम आदर्शों और नैतिकताओं को ताक पर रखकर बेटे को जदयू में मंत्री बनवाने में सफल रहे. सूबे के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के दो बेटे अभय प्रताप सिंह और सुमित सिंह भी सदन की शोभा बढ़ा रहे हैं.

सुमित जेएनयू से पढ़े–लिखे हैं और जेएमएम की टिकट से चकाई से विधायक हैं. सुमित अपने क्षेत्र में युवाओं के लिए किए गए कामों को गिनाते हुए कहते हैं कि हम अपने दादा जी के सपने को पूरा करने के लिए राजनीति में आए हैं.

feedback@chauthiduniya.com

न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड

अन्ना हजारे का संबोधन

इस परेड ने सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, भारत के भी हर नागरिक के दिल में हमारे देश के लिए प्रेम जगाने का प्रयास किया है. हमारा यह तिरंगा हमें प्राणों से प्रिय है. हम कहते हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा और इस परेड ने पूरे विश्व में हमारे तिरंगे को और ऊंचा किया है. जो लोग इस परेड में शामिल हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि हमें अभी भारत देश के लिए बहुत काम करना है. भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण कैसे हो और देश तरक्की कैसे करे, इन दो बातों पर सबको मिलकर विचार करना है. 16 अगस्त, 2011 को भारत में जो आंदोलन हुआ, उसमें करोड़ लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन किसी ने हाथ में एक पत्थर तक नहीं उठाया. भारत में ऐसी क्रांति पहली बार हुई. आप और हम मिलकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करेंगे. जनलोकपाल कानून संसद में प्रस्तावित है. अगर जनलोकपाल आया तो अधिकांश भ्रष्टाचारी जेल में होंगे. हम और आप मिलकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है.

भारत माता की जय

शिक्षा को लेकर एक बड़ा मशहूर जुमला है कि शिक्षे तेरा नाश हो जो तू नौकरी के हित बनी. भारतीय शिक्षा व्यवस्था के भीतर बुनियादी मुश्किलें यहीं से शुरू हुईं जब शिक्षा और नौकरी दोनों को एक दूसरे के पूरक के तौर पर देखा जाने लगा. शिक्षण संस्थाएं केवल डिग्रीधारक पैदा करने की मशीन हो गईं और नौकरी पाने की शैक्षणिक योग्यता तय कर दी गई.

शिक्षक दिवस पर विशेष

अब शिक्षा में भी क्रांति की दरकार...

शिक्षण संस्थाएं केवल डिग्रीधारक पैदा करने की मशीन हो गईं और नौकरी पाने की शैक्षणिक योग्यता तय कर दी गई. आप ग्रेजुएट हैं, तभी यह फॉर्म भर सकते हैं और और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तभी इस पद के योग्य हैं. शैक्षणिक योग्यता शब्द ने जो प्रतिस्पर्धा खड़ी की, उसकी वजह से शिक्षा के बुनियादी तत्व खतरे में पढ़ गए. इस बात का क्या प्रमाण कि आपके पास यह डिग्री है तो आप इस पद के लिए योग्य ही हैं.

नीरज सिंह

21वीं में दाखिल होते–होते एक तरह से समूचा विश्व उत्तर आधुनिकता के दरवाजे पर खड़ा हो गया था. 17वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक बदलावों की परिभाषा के शब्द क्रांतियों के माध्यम से लिए जा रहे थे और यह महसूस किया जाने लगा था कि जड़ता को मिटाने के लिए बौद्धिक एकजुटता की जरूरत है. इसी बौद्धिक एकजुटता ने पुरानी और रूढ़ पढ़ चुकी व्यवस्था को हटाने के लिए दुनिया में क्रांतियों को जन्म दिया, लेकिन जब गुबार थमा तो उन क्रांतियों के परिणाम की व्याख्या शुरू हुई और हालात जस के तस दिखे. आधुनिक संदर्भों में धार्मिक क्रांतियों की जो परिणति है, वह सबके सामने है. समूचा विश्व धर्म के नाम पर बंटा हुआ है. राजनीतिक क्रांतियां हुईं, लेकिन भीतर की सत्ताधारी मानसिकता नहीं बदली. एक दल गया, दूसरा आया. वह भी सत्ताधारी सोच का ही पोषक. आर्थिक क्रांतियां हुईं. पूंजीवाद गया, तो प्रबंधकवाद आ गया. उतना ही खतरनाक. नये–नये वर्ग बन गए, लेकिन वर्ग व्यवस्था बनी रही. और वैज्ञानिक क्रांतियों ने तो मानवता को समाप्ति के मुहाने पर ही लाकर खड़ा कर दिया.

इस तरह व्यवस्था में बदलाव के लिए पिछले सैकड़ों वर्षों में जितने प्रयोग हुए हैं, वे अपने उद्देश्य में सफल ही हुए. इसको लेकर संदेह बना हुआ है. इसीलिए पिछले एक दशक से यह आवाज अब जोर पकड़ने लगी है कि वास्तविक रूप में समाज के सभी अंगों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए शिक्षा क्रांति की जरूरत है. हालांकि, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अंग्रेजी शासन के ही दौर से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बदलावों की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन बदलावों को अमली जामा पहनाने के लिए कभी ऐसी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई कि वास्तविक बदलावों के सही रूप सामने आ सकें. हां, यह जरूर किया गया कि शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक रंग देकर उसे दो धाराओं में यानी दक्षिणपंथी व भारतीयता को सही साबित करने वाली व्यवस्था व मैकाले पुत्रों की यानी भारतीयता को खत्म करने वाली व्यवस्था के तौर पर व्याख्यायित कर बांट दिया गया. इसलिए एक बार फिर जब हम तकनीक के माध्यम से शिक्षा में क्रांति लाने की बात कर रहे हैं, हर हाथों में टैबलेट व लैपटॉप देकर डिजिटल शिक्षा की अगली पंक्ति में खड़ा करने की बात कर रहे हैं, तब यह समझने की बेहद जरूरत है कि आखिर हमारे एजुकेशन सिस्टम के वे कौन से लूप होल हैं जो शिक्षा क्रांति की राह में मुश्किल खड़ी कर रहे हैं.

शिक्षा के संदर्भ में भवानी प्रसाद मिश्र की यह पंक्तिया बड़ी प्रभावित करती हैं कि कुछ लिखकर सो कुछ पढ़कर सो, जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़कर सो. लेकिन आधुनिक प्रगतिवादी मान्यताओं में उस जगह से बढ़कर सो–के विचार यानी कर्म प्रधानता को भारतीय शिक्षा के बुनियादी विचार से पूरी तरह अलग कर दिया गया. भारत में शिक्षा के चार स्तर थे–धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. प्राचीन भारत की शिक्षा मोक्ष का मार्ग थी, लेकिन आज की शिक्षा भोग का मार्ग है. भोग का मार्ग बनने में कोई बुराई नहीं है, भोग का मार्ग किस तरह बनाया जा रहा है और किन शर्तों पर, यह सवाल जरूर खड़ा होता. आइए पहले इस सवाल को समझते हैं.

शिक्षा को लेकर एक बड़ा मशहूर जुमला है कि शिक्षे तेरा नाश हो जो तू नौकरी के हित बनी. भारतीय शिक्षा व्यवस्था के भीतर बुनियादी मुश्किलें यहीं से शुरू हुईं जब शिक्षा और नौकरी दोनों को एक दूसरे के पूरक के तौर पर देखा जाने लगा. शिक्षण संस्थाएं केवल डिग्रीधारक पैदा करने की मशीन हो गईं और नौकरी पाने की शैक्षणिक योग्यता तय कर दी गई. आप ग्रेजुएट हैं, तभी यह फॉर्म भर सकते हैं और और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तभी इस पद के योग्य हैं. शैक्षणिक योग्यता शब्द ने जो प्रतिस्पर्धा खड़ी की, उसकी वजह से शिक्षा के बुनियादी तत्व खतरे में पढ़ गए. इस बात का क्या प्रमाण कि आपके पास यह डिग्री है तो आप इस पद के लिए योग्य ही हैं. आतंकवाद की तो कोई डिग्री नहीं होती और न ही कोई पढ़ाई, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों और अपराधियों की बात करें तो उनकी शिक्षा और ज्ञान का स्तर आम शिक्षित लोगों से कहीं ज्यादा रहा है और उन्हें दुनियाभर की मालूमात थी. तो क्या यह माना जाए कि उन्हें जो शिक्षा दी गई वह आतंकवाद की थी. निश्चित तौर पर बुनियादी समझ विकसित करने में कमी रह गई. इसलिए कई बार यह साबित होता है कि शिक्षा की यह पद्धति बच्चों में कहीं से स्वतंत्र चेतना तो पैदा करती ही नहीं, बल्कि भारतीय परिस्थितियों में अभाव के शिकार बचपन, समाज, परंपरा और अपने आसपास के पर्यावरण से अवलोकन कर बच्चा जो कुछ सीखता है, उसका भी गला घोंट देती है.

नील्सन–मैकिन्से का पिछले वर्ष के आखिर में एक सर्वे आया था जिसके मुताबिक भारत के 10 आर्ट्स ग्रेजुएट और और चार इंजीनियरिंग ग्रेजुएट में से एक–एक ही नौकरी के लायक हैं. साफ है, हमारी शिक्षा व्यवस्था रोजगार नहीं, बेरोजगार पैदा कर रही है. एक लंबा वक्त और बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करने के बाद अगर यह शिक्षा व्यवस्था शिक्षित बेरोजगार पैदा कर रही है तो ऐसी निर्गुण शिक्षा के क्या मायने? भारत में हायर एजुकेशन में दाखिले का अनुपात 13 प्रतिशत है और अमेरिका में 83 प्रतिशत. जबकि हम खुद को ज्ञान की अर्थव्यवस्था कह कर अपनी पीठ थपथपाते हैं.

जैसे–जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे ही स्नातक बढ़ते जा रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकॉनोमिक कोऑपरेशन एंड डेवेलपमेंट ऑर्गनाइजेशन की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 तक भारत में ग्रेजुएट्स की संख्या अमेरिका से ज्यादा हो जाएगी और चीन के बाद वह दूसरे नंबर पर आ जाएगा. यह सूचना बड़ी सुखद सी लगती है कि देश में साक्षर लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसी संस्था का सर्वे जब यह भी कहता है कि शिक्षा में गुणवत्ता के लिहाज से हम 73 देशों में 72वें स्थान पर हैं, तो चिंता बढ़ जाती है.

शिक्षा व्यवस्था में क्रांति की दरकार और बढ़ जाती है, जब बात इसके राजनीतिकरण की उठती है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28, 29, 30, 45, 46, 337, 350 ए, 350 बी, और अनुच्छेद 351 में शिक्षा संबंधी प्रावधान हैं. इन सबसे बढ़कर राइट टू एजुकेशन है. लेकिन चूंकि शिक्षा राज्य का भी विषय है, इसलिए सरकारें हर बार यह कह कर पल्ला झाड़ लेती हैं कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकारें कई योजनाएं शुरू कर चुकी हैं, लेकिन राज्य सरकारें इस दिशा में उतनी गंभीर नहीं हैं.

शिक्षा व्यवस्था में क्रांति की दरकार और बढ़ जाती है, जब बात इसके राजनीतिकरण की उठती है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28, 29, 30, 45, 46, 337, 350 ए, 350 बी, और अनुच्छेद 351 में शिक्षा संबंधी प्रावधान हैं. इन सबसे बढ़कर राइट टू एजुकेशन है. लेकिन चूंकि शिक्षा राज्य का भी विषय है, इसलिए सरकारें हर बार यह कह कर पल्ला झाड़ लेती हैं कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकारें कई योजनाएं शुरू कर चुकी हैं, लेकिन राज्य सरकारें इस दिशा में उतनी गंभीर नहीं हैं. एक समारोह में कुछ महीनों पहले कपिल सिब्बल ने एक बयान दिया था कि सकल दाखिला अनुपात को बढ़ाने के लिए मौजूदा 604 विश्वविद्यालय और 31,000 कॉलेज नाकाफी हैं. सिब्बल ने तर्क दिया कि समूची मांग को पूरा करने के लिए केंद्र के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं. जबकि शिक्षा राज्य का भी विषय है, लेकिन ज्यादातर राज्य इस सेक्टर के लिए पर्याप्त पैसा आवंटित नहीं करते. क्या इस तरह की राजनैतिक बयानबाजी के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों पर पर्दा डाला जा सकता है.

इस संदर्भ में सबसे बड़ी मुश्किल है शिक्षकों का अपनी जिम्मेदारी से दूर भागना. हम भले ही हर वर्ष शिक्षक दिवस मना लें, लेकिन अगर सम्मानीय शिक्षक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो शिक्षा क्रांति क्या, शिक्षा विश्व युद्ध से भी कोई तब्दीली नहीं आएगी. देश में 13 लाख स्कूली अध्यापकों के पद खाली हैं. कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में 40 फीसदी पद रिक्त हैं. लेकिन विडंबना तो यह है कि एक तरफ तो शिक्षकों का टोटा है, वहीं देश के तकरीबन हर राज्य में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार की जद में है. हरियाणा, उप्र, बिहार और हिमाचल प्रदेश का नाम तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार में सबसे आगे है. यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय शिक्षा तंत्र में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है. करप्शन इन एजुकेशन नाम की इस स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय स्कूलों के शिक्षक स्कूल से गायब रहने में सबसे आगे हैं. वैश्विक स्तर पर देखें तो युगांडा ही ऐसा देश है, जहां के शिक्षक स्कूल से गायब रहने में हमसे आगे हैं. शायद इस पर भी हम खुद को शाबासी दें जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कई देशों से बेहतर है और जाहिर तौर पर वह नाम होंगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल. दुनिया में 100 में से औसतन बीस शिक्षक ही स्कूल से गायब रहते हैं जबकि, भारत के 100 में 25 शिक्षक स्कूल नहीं आते और इनमें बिहार और यूपी सबसे आगे हैं.

क्या यह वही देश है जहां नालंदा विश्वविद्यालय था, क्या यह वही देश है जिसने हर काल में शिक्षा के संदर्भ में कई प्रतिमान गढ़े. लार्ड मैकाले ने 1834 में ब्रिटिश संसद में दिए गए अपने एक वक्तव्य में कहा था कि मैंने उत्तर से दक्षिण तक सम्पूर्ण भारत का भ्रमण और अध्ययन किया, पर कोई भी गरीब या भिखारी नहीं मिला मुझे, शिक्षा का ऐसा प्रबंध है वहां कि हर कोई अन्वेषण कर सकता है. फिर हम इस हालात पर कैसे पहुंचे, क्योंकि इस क्षेत्र में हमने कभी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं समझी.

इस देश को एमएस स्वामीनाथन मिले, जिन्होंने हरित क्रांति को जन्म दिया. धीरूभाई अंबानी मिले, जिन्होंने एक आम आदमी के सपनों को साकार करने का पाठ पढ़ाया. एपीजे अब्दुल कलाम मिले, जिन्होंने सही मायनों में भारत को शक्ति संपन्न बनाया. इन सभी मामलों में देश आगे बढ़ता गया क्योंकि इनके प्रयासों को सही दिशा में आगे ले जाने के लिए योग्य लोग जुड़ते गए. लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में राधाकृष्णन जी के प्रयासों को सिर्फ शिक्षक दिवस के तमगे तक सीमित कर दिया गया. हम अपनी शिक्षा व्यवस्था का पतन अपनी आंखों के सामने ही होते हुए देखते रहे, उसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी. कभी क्रांति के हालात नहीं पैदा किए. प्रगतिवादी समाज में एक नारा दिया जाता है लड़ो लड़ाई लड़ने को, पढ़ो समाज बदलने को. इस सोच में सुधार की जरूरत है. शिक्षा व्यवस्था को मजूबत बनाना है तो लड़ो लड़ाई पढ़ने को और पढ़ो समाज बदलने को. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

सरकार ग़रीबों के वोटों से चुनी जाती है, लेकिन वह केवल धनी लोगों की सेवा करती है. इस तरह का लोकतंत्र कितने दिनों तक चलेगा. कुछ अन्य देशों की तरह भारत में भी हम लोग उस स्तर पर पहुंच गए हैं, जहां हमारी सारी आज़ादी समाप्त हो गई है.

हमारी आज़ादी समाप्त हो गई है

देश में हुए बदलावों ने एक आधारभूत सवाल पूछने के लिए मजबूर कर दिया है. सवाल है कि आखिर यह देश किसका है? सरकार द्वारा देश के लिए बनाई गई आर्थिक नीतियां और राजनीतिक वातावरण समाज के किस वर्ग के लोगों के फायदे के लिए होना चाहिए? माकूल जवाब होगा कि सरकार को हर वर्ग का ख्याल रखना चाहिए. आज भी देश के साठ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं. मुख्य रूप से सरकारी और निजी क्षेत्र में काम कर रहा असंगठित मज़दूर वर्ग भी महत्वपूर्ण है. दुर्भाग्यवश 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद सरकार का सारा ध्यान कॉरपोरेट सेक्टर, विदेशी कंपनियों और विदेशी निवेश पर केंद्रित हो गया. कृषि क्षेत्र की लगातार उपेक्षा की गई और अगर ऐसा ही आने वाले 20 सालों तक चलता रहा, तो जिस तरह देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए देश में अनाज की भारी कमी हो जाएगी. हो सकता है कि जनसंख्या वृद्धि की दर कम हो, मगर वह बढ़ेगी ही और उसके लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं होगा. जब आप अपने लोगों का पेट नहीं भर सकते हैं, तब कोई भी विकास और कितना भी पैसा किसी देश की मदद नहीं कर सकता है.

जब जवाहर लाल नेहरू जीवित थे, तब कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु में मद्रास के निकट अवाडी में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय नीतियां समाजवाद के सिद्धांत को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए. 1991 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और तब उन्होंने कहा कि इन नीतियों से देश के लोगों का भला नहीं हुआ और उन्होंने सारी नीतियों को उलट दिया. उनका मुख्य तर्क यह था कि लाइसेंस राज के दौरान कुछ लोगों ने सभी लाइसेंस अपनी मुट्ठी में कर लिए और बाद में उन्हें ऊंचे दामों पर दूसरों को बेच दिया, जो अनुचित था. यदि वह लाइसेंस राज खत्म कर देते, तो शायद बहुत सारे लोग कल-कारखाने खोल सकते थे या कुछ और कर सकते थे, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती, कीमतों में कमी आती और लोगों को फायदा होता. पिछले 21 सालों में क्या हुआ है? महंगाई बढ़ गई है, कहीं भी प्रतिस्पर्धा नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक एवं दूरसंचार जैसे जिन क्षेत्रों में काम हुआ है, तकनीकी विकास के कारण हुआ है, न कि सरकारी नीतियों की वजह से. यदि आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, तो उसकी वजह तकनीक और समय में बदलाव था, अमेरिका और भारत में कीमतों का अंतर था. जहां कहीं भी सरकार शामिल थी, वहां कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई.

यह समय कांग्रेस के अवाडी रिज़ॉल्यूशन पर लौटने का है, जिसमें कहा गया है कि हमें समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित समाज का निर्माण करना है, ग़रीबों का ख्याल रखा जाए. किसी ने यह नहीं कहा, अवाडी रिज़ॉल्यूशन में भी नहीं कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर को बंद कर देना चाहिए या निजी क्षेत्र को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए. सभी ने यह कहा है कि ग़रीबों का ख्याल रखा जाना चाहिए, पब्लिक सेक्टर को सुदृढ़ करना चाहिए. यहां निजी क्षेत्र के लिए बहुत से रास्ते खुले हैं, जहां वह अपना पराक्रम दिखा सकता है और अपना काम कर सकता है. सरकार द्वारा मनरेगा को लागू करना एक महत्वपूर्ण क़दम था. ग़रीबों के लिए 100 दिनों के रोजगार की व्यवस्था की गई थी. यह अलग बात है कि योजना को किस तरह क्रियान्वित किया गया और इसमें कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन यह क़दम सही था. मनरेगा में हर साल कितना पैसा खर्च किया जाता है. मान लीजिए 40 हज़ार करोड़, लेकिन यह पैसा कॉरपोरेट सेक्टर से आना चाहिए. धनवान लोगों को ग़रीबों के लिए भुगतान करना चाहिए. सरकार को कॉरपोरेट टैक्स 5 प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए. अमीरों से पैसे लो और ग़रीबों में बांट दो, लेकिन यह सरकार ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि उसे लगता है कि इससे शेयर बाज़ार में गिरावट आएगी. अमेरिका कहेगा कि तुम कॉरपोरेट सेक्टर को क्यों बर्बाद कर रहे हो.

अब क्या पहले देश के ग़रीबों एवं किसानों के हितों का ख्याल रखा जाएगा या फिर अमेरिकी अधिकारियों की खुशी का ख्याल रखा जाएगा? यह विषय आज हमारे सामने है. आपने अमेरिका को खुश करने के लिए न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल पास किया, खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति अमेरिका को खुश करने के लिए दी. इस देश के ग़रीबों का क्या हुआ? उदाहरण के तौर पर यहां लाभ पर कोई टैक्स नहीं है. यदि किसी कंपनी का मालिक लाभ की घोषणा करता है और उसे लाभ स्वरूप पैसे मिले हैं, तो उसे उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. कौन टैक्स देता है? कंपनी टैक्स देती है. एक बराबरी पर लाने के लिए कम से कम यह किया जाना चाहिए कि कंपनी में काम करने वालों को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए. कर्मचारियों का टैक्स जो कुछ भी हो, उसका भुगतान कंपनी को करना चाहिए. यदि कंपनी अपने मालिक के टैक्स का भुगतान कर सकती है, तो वह कर्मचारियों के टैक्स का भुगतान भी कर सकती है. यदि ग़रीब कर्मचारी टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, जिनकी एक नियत आमदनी है, महंगाई बढ़ रही है, उन्हें यह नहीं मालूम है कि इसका समाधान क्या होगा, मालिक को बिना किसी टैक्स का भुगतान किए लाभांश मिल रहा है, तो क्या हम एक साफ़-सुथरे और न्यायपूर्ण समाज में रह रहे हैं? यह आधारभूत सवाल पूछने की ज़रूरत आ पड़ी है. अगले चुनाव इस विषय पर होंगे कि यह देश किसका है? क्या यह देश मुट्ठी भर व्यावसायिक घरानों का है या फिर करोड़ों किसानों एवं मज़दूरों का है, जो खेतों और फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं. यह आज के समय का सबसे बड़ा मुद्दा है. बात एक लाख अस्सी हज़ार करोड़ या एक लाख सत्तर हज़ार करोड़ की नहीं है, बात शासन की ईमानदारी की है, काम करने के सही तरीके की है, पारदर्शिता की है. सरकार ग़रीबों के वोटों से चुनी जाती है, लेकिन वह केवल धनी लोगों की सेवा करती है. इस तरह का लोकतंत्र कितने दिनों तक चलेगा. हमारा लोकतंत्र कुछ देशों की तरह हो गया है, जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, जहां मतदान तो होता है, लेकिन लोगों को आज़ादी नहीं है. भारत में भी हम लोग उस स्तर पर पहुंच गए हैं, जहां हमारी सारी आज़ादी समाप्त हो गई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

आज़ादी के लिए ख़तरे

ठाकुर दास बंग

सन् 1947 को उस ऐतिहासिक आधी रात को जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ, राष्ट्र के सभी शहरों व गांवों में लोग रात्रि-जागरण कर ठीक बारह बजने का इन्तजार कर रहे थे, जबकि सारे देश में खुशी की एक विशाल लहर सी दौड़ गई थी. लोगों के मन में भूख, बीमारी और झगड़ों से रहित एक नई व खुशयों भरी जिन्दगी की कितनी ऊंची आशाएं थी, लेकिन आजादी व पंचवर्षीय योजनाओं के पैंतीस वर्षों ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया.

आज हिन्दुस्तान में गरीबी रेखा के नीचे करीब-करीब उतने ही लोग हैं, जितनी आजादी के समय देश की कुल आबादी थी. देश के लाखों गावों के लोगों में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वे एक भी सूखे या बाढ़ का सामना कर सकें और उन्हें अपनी हालत सुधारने के लिए दान-दया पर निर्भर रहना पड़ता है. उनमें से सैकड़ो भुखमरी के कारण मौत के शिकार होते हैं. अंग्रेजी सरकार द्वारा निर्धारित परम्परा का कड़ाई से पालन करते हुए केन्द्रीय व राज्य सरकारें ऐसी मौतों से साफ इन्कार करती हैं. पिछले तीस वर्षों में भूमिहीन मजदूरों की संख्या करीब 16% प्रतिशत से बढ़ कर 25% से भी अधिक हो गई है, क्योंकि किसानों की और ज्यादा संख्या कंगाल बनी है.

साक्षरता के प्रतिशत से भी बृद्धि हुई है, लेकिन निरक्षरों की कुल संख्या भी बढ़ी है. बेरोजगार लोगों की संख्या भी बढ़ती रही है और अब तो सरकार ने उनके आकड़े भी प्रकाशित करना बन्द कर दिए हैं. हर साल 60 लाख आदमी काम पानेवालों की संख्या में शामिल होते हैं, लेकिन उनमें से उद्योगों में सिर्फ 11 प्रतिशत को काम मिल पाता है. बाकी लोग गैर-रोजगार या अल्प रोजगार वाले लोगो की संख्या में शामिल हो जाते हैं. यह सब इसलिए नहीं हुआ कि पंचवर्षीय योजनाएं ठीक से क्रियान्वित नहीं हुई, बल्कि इसलिए कि हमारे आयोजन का प्रकार ही ऐसा रहा है. हमारी योजनाओं ने उद्योग-धन्धे करने को वरीयता दी. इसके लिए पूंजी कृषि की अर्थव्यवस्था के शोषण से मिल सकती थी. इस उद्देश्य से कृषि-उत्पादनों के दाम कम और औद्योगिक वस्तुओं का दाम ऊंचा रखने की नीति अपनाई गई और इस तरह गांव वाले दोनों तरफ से घाटे में रहे. श्री शरद जोशी ने हिसाब लगाया है कि अपने उत्पादनों का कम मुल्य पाकर देश के किसान हर साल 10,000 करोड़

रुपयों का नुकसान उठा रहे हैं. एशियाई खेलों पर सरकार 1500 करोड़ रुपये खर्च सकती थी, लेकिन पिछले पैंतीस वर्षों में 400-500 करोड़ रुपये उन एक लाख गांवो के लिए नहीं जुटाए जा सके, जिनमें पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है. इन सभी समस्याओं और लोगों की मुसीबतों ने व्यापक असंतोष व क्रोध को जन्म दिया है. हमारे देश में लोकतंत्र है, जिसमें लोगों को सरकार बदल देने का अधिकार है. उन्हें समाचार-पत्रों और सभाओं आदि के द्वारा खुलकर अपनी राय प्रकट करने, नीतियों में परिवर्तन के लिए संगठित होने एवं आन्दोलन करने का भी अधिकार है. हां यह बात जरूर है कि अपने देश में जैसा लोकतंत्र है, उसमें लोगों को कोई सीधे अधिकार नहीं है.

गांधी जी चाहते थे कि प्रत्येक ग्राम-पंचायत को अपना कामकाज चलाने भर के लिए आवश्यक पूरी सत्ता मिले, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को जनता में इतना विश्वास नहीं था और इसीलिए उन्होंने सारी सत्ता केंद्रीय व राज्य सरकारों के हाथ में केंद्रित की. फिर भी, सरकार चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार लोकशक्ति की दिशा में एक बड़ा कदम था और मौलिक अधिकार इसके अनिवार्य अधिकार बने.

लेकिन लोगो के असंतोष के साथ-साथ अन्यायपूर्ण व एकांगी विकास से लाभ उठाने वाले शासक वर्ग में ऐसे किसी भी परिवर्तन को न होने देने की वृत्ति विकसित हुई, जो उनके निहित स्वार्थों को प्रभावित कर सके. इस उद्देश्य से उन्होंने लोगों को दबाने और अपने को सत्ता

आज हिंदुस्तान में गरीबी रेखा के नीचे करीब-करीब उतने ही लोग हैं, जितनी आजादी के समय देश की कुल आबादी थी. देश के लाखों गावों के लोगों में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वे एक भी सूखे या बाढ़ का सामना कर सकें और उन्हें अपनी हालत सुधारने के लिए दान-दया पर निर्भर रहना पड़ता है.

में रखने के लिए सभी तरह के सूक्ष्म व भोंडे तरीकों का इस्तेमाल किया. लोकप्रिय आंदोलनों को दबाने के लिए लाठीचार्ज व गोली का खुलकर इस्तेमाल हुआ. समाचार माध्यमों को भी प्रभावित करने की कोशिश हुई, ताकि सत्ता के विरुद्ध जानेवाली खबरें या तो प्रकाशित न हों या उन्हें हलका कर दिया जाए. मतदाताओं को घूस, झूठे वादों और धमकियों तक से प्रभावित करने की कोशिशें की गईं. चुनावों में तिकड़म का प्रयोग हुआ और मत पत्र-डिब्बों को उठा ले जाया गया. भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ, क्योंकि मंत्री और उनकी तरह के अन्य लोग उसमें लिप्त हुए और उसे बढ़ावा दिया और इस तरह विकास के साधन भ्रष्टाचार की धारा में बह गए.

यह सब आजादी मिलने के समय से ही चलता चला आ रहा था और हर साल बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन 1975 में आपात स्थिति की घोषणा से ये बातें पराकाष्ठा पर पहुंच गईं. यह जयप्रकाश जी के उस आन्दोलन को दबाने के लिए किया गया, जो लोगों को कष्ट देने वाली समस्याओं से संघर्ष के लिए संगठित करना चाहता था. आपातकाल का बहाना देश पर तानाशाही लादने के लिए किया गया था. मिसा (आन्तरिक सुरक्षा कानून) का इस्तेमाल बिना मुकदमा चलाए कम-से-कम तीस हजार लोगों को जेल में बन्द करने के लिए किया गया. इस कानून के अन्तर्गत कोई भी आदमी अपने शेष जीवन भर के लिए जेल में बन्द किया जा सकता था. जब यह कानून पास हुआ, तो सरकार ने लोकसभा को यह विधिवत आश्वासन दिया था कि यह कानून सिर्फ आर्थिक अपराधियों एवं अपराध-तत्वों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए बना था, लेकिन व्यवहार में यह करीब-करीब सिर्फ राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ही प्रयुक्त हुआ. आपातकाल में समाचार-पत्रों एवं पत्र-पत्रिकाओं पर कड़ा सेंसर लगाया गया और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन सिर्फ एक तरफा प्रचार प्रसारित करते थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

आदर्श लोकतंत्र

आदर्श लोकतंत्र की मान्यताएं अलग-अलग तो हो सकती हैं, लेकिन स्वीकार्य वही होगा, जिसके साथ आवाम का बहुमत हो. हमारे राजनीतिक दल बाकी किसी मामले पर एकजुट भले नजर न आएं, आपसी हितों के लिए वे एक सुर में हमेशा बोलते नजर आते हैं. राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के केन्द्रीय सूचना आयोग के फैसले और अपराधियों को चुनावों और संसद के बाहर रखने संबधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रभावहीन करने के लिए इन दिनों सारे दल एकजुट नजर आ रहे हैं. मानसून सत्र में सूचना आयोग के आदेश का असर समाप्त करने की तैयारी संशोधन विधेयक के रूप में तैयार की जा चुकी है. ऐसे भी आरटीआई को नौकरशाहों ने मजाक बना रखा है, लेकिन कम से कम वित्तीय मामलों को लेकर तो सभी राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में आना ही चाहिए, क्योंकि आवाम को राजनीतिक दलों के खर्च का हिसाब जानने का पूरा अधिकार है. राजनीतिक दलों के आपसी हितों के आगे राष्ट्रीय हितों का कोई मायने नहीं है. इससे समय की स्वार्थी राजनीति का चाल-चरित्र और चेहरा उजागर हो रहा है. आदर्श लोकतंत्र परिहास की वस्तु हो गया है. हर तरफ पैसा-पैसा का बोलबाला है, सेवा भावना किसी के अंदर नहीं दिखता. कहा जाता है कि राजनीति पेशा नहीं, सेवा है, पर क्या सचमुच ऐसा है?

-अशोक निर्मोही, दरभंगा

स्वार्थ की राजनीति

124 करोड़ आबादी वाले हमारे देश में भूखमरी और कुपोषण एक बड़ी समस्या है. इसका समाधान जरूरी है, लेकिन जल्दबाजी में और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए. खाद्य सुरक्षा अध्यादेश देश के 67 फीसद आवाम को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराएगा. इस अध्यादेश की कामयाबी के लिए जरूरतमंदों का सही आकलन जरूरी है. देश की कुल पैदावार 25 करोड़ टन है, जबकि खाद्य सुरक्षा के लिए 6 करोड़ टन खाद्यान्न की जरूरत है. अनाज रखने की समस्या ज्यादा है, क्योंकि लाखों टन अनाज प्रति वर्ष सड़ जाता है. भ्रष्टाचार और घोटोलों के चलते यह योजना संदेह के घेरे में है. इसकी सफलता के लिए कारगर नीति एवं कठोर अनुशासन तथा सतत अनुश्रवण की जरूरत है. हमारा देश आज सरकार की निष्क्रियता, शिथिलता तथा अकर्मण्यता से उत्पन्न स्थितयों से जूझ रहा है. सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का यह उत्तरदायित्व सर्वविदित है कि वह जनमत पर लगातार निगाह रखे तथा किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेते समय भी तत्कालीन परिस्थितयों में आवाम की सोच का ध्यान रखे. सरकारी योजना मिड डे मील पर बिहार के छपरा में बच्चों की मौत सुशासन पर एक प्रश्न खड़ा करता है. संकुचित दृष्टि तथा स्वार्थ लिप्त व्यवस्था के प्रशासन तंत्र ने हर सरकारी योजनाओं के सारे मापदंडो को पीछे धकेल दिया. भूख पर विजय प्राप्त कर चुके 38 देशों की सूची में भारत का नाम नहीं है. वोट के भूखे नेता खाद्य सुरक्षा योजना की आंड़ में अपने स्वार्थ की रोटियों से गरीबों की भूख की आड़ में अपनी वोट की भूख मिटाना चाहते हैं.

-भुपेन्द्र, पटना

धोखेबाज पाकिस्तान

मियां नवाज शरीफ इस बार हमारी ईद जरा फीकी रही. हमारा मुल्क अभी गम और गुस्से के दौर से गुजर रहा है. सरहद की निगहबानी करने के दौरान अपने पांच जवानों को खो देने के गम में हम अभी डुबे हैं. उन जवानों के घर पिछले कई दिनों से चुल्हा नहीं जला. अन्न का एक निवाला तक बच्चों ने नहीं खाया. रिश्ते की कीमत भला तुम क्या जानो शरीफ बाबू. तुम्हारा मुल्क तो सिर्फ धोखेबाजी और फरेब की राजनीति करता है. दरअसल, पाकिस्तान की सियासी आबोहवा ही कुछ ऐसी है, जहां अमन की बात करने वाले ईमानदार लोगों के रहने के लिए गुंजाइश कम है, पर हमारा गम जरा जुदा है. हम पाकिस्तान द्वारा बार-बार छले गए एक ऐसे मुल्क के बाशिंदे हैं, जहां के हुक्मरान गन्दी राजनीति में मशगूल हैं. उन्हें यह तक पता नहीं कि एलओसी पर हमला आतंकियों ने किया था या पड़ोसी मुल्क के सैनिकों ने . हमारे सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को वोलना तक नहीं आता. जिनकी मानसिकता यह है कि सैनिक तो होते ही हैं शहीद होने के लिए. ऐसे नेताओं से भला किस प्रकार की उम्मीद की जा सकती है. पाकिस्तान की आदत ही है पीठ में छूरा भोंकना. क्या हमारी सरकार को यह अधिकार है कि बेवजह हमारे जवानों की जान गवां दे? यह सब देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है. सरकार की नाकामी और लचीलेपन के चलते पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों का दुस्साहस बढ़ा है.

-विकास कुमार पाटनी, झुमरी तिलैया

जिम्मेदार कौन

सरकार हो या विपक्ष, दोनों संसद न चलने के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराते हैं. सरकार कहती है कि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि संसद चलने दे और विपक्ष कहता है सरकार की जिम्मेदारी है संसद चलाना. संसद के मानसून सत्र में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार हंगामा जारी है और संसद की कार्यवाही लगातार ठप है. इससे जहां महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पा रहे हैं, वहीं जनता का करोड़ो रुपया बर्बाद हो रहा है. विपक्ष कहता है कि हमारा अधिकार है संसद में सरकार से सवाल पूछना और सरकार को हमारे सवालों का जबाब देना चाहिए, लेकिन सरकार जबाब देने के बजाय सवालों से भागती रहती है. मानसून सत्र में शुरू हुए कुछ दिन हो गए, लेकिन संसद एक भी दिन ठीक से नहीं चली. मानसून सत्र में यूपीए सरकार ने अपनी बहुचर्चित और महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा बिल पास कराने के लिए जी-तोड़ कोशिश की, लेकिन उसकी मंशा धरी की धरी रह गई. कांग्रेस का मकसद केवल खाद्य सुरक्षा बिल पास कराना है. संसद चले या न चले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. गिरती अर्थवयवस्था, कोयला मंत्रालयों से फाइलों का गुम हो जाना, पाकिस्तान द्वारा बार-बार सीजफायर का उल्लंघन करना जैसे मुद्दों पर तो विपक्ष सवाल पुछेगा ही. सरकार का काम है विपक्ष का जवाब देना, लेकिन सरकार के मंत्री जवाब देने के बजाय विपक्ष से खुद सवाल करने लगते हैं. ऐसे में संसद न चलने के लिए कौन जिम्मेदार है?

-रोहित राय, पटना

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें:
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

इस आशा में संभावना भी दिखती है

जब तोप मुक़ाबिल हो

अमेरिका की सड़कों पर 18 अगस्त को एक अजीब नजारा दिखाई दिया. आमतौर पर यहां की सड़कों पर एक लाख के आस-पास लोग होते हैं, लेकिन 18 अगस्त को यहां की सड़कों पर दो लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा थे. दोनों तरफ ठीक वैसी ही भीड़ थी, जैसी दिल्ली में इंडिया गेट पर 26 जनवरी की परेड के दौरान दिखाई देती है. लोग उत्साह से लबरेज थे. झंडे लहरा रहे थे. अवसर था न्यूयार्क में भारतीय स्वतंत्रता दिवस को मनाने का. हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है. न्यूयार्क में अमेरिका में रहने वाले भारतीय इसे इतवार के दिन मनाते हैं, ताकि दूर-दूर से लोग आसानी से इस समारोह में शामिल हो सकें. और सड़कें सचमुच भरी हुई थीं, दूर-दराज से लोग आए हुए थे.

इस परेड में विद्या बालन चल रही थीं और अन्ना हजारे चल रहे थे. विद्या बालन आगे थीं. विद्या बालन को देखकर लोग नारे तो नहीं लगा रहे थे, हाथ जरूर हिला रहे थे और उनके अभिवादन के जवाब में विद्या बालन अपने फिल्मी अंदाज में ही लहराते हुए डांस की मुद्रा में अपने हाव-भाव प्रदर्शित कर रही थीं. अमेरिका के भारतवासी, जो हर साल इस परेड को देखते हैं, मनाते हैं और हर साल कोई न कोई फिल्मी सितारा इस परेड में शामिल होता है. विद्या बालन को भी ठीक वैसा ही रेस्पॉन्स मिल रहा था, जैसा कि पूर्व में आयोजित परेड में शामिल फिल्मी सितारों को मिलता रहा है. पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह भी अपनी पत्नी के साथ इस परेड में शामिल हुए. चूंकि पहले से ही इस परेड का विज्ञापन अमेरिका में टेलीविजन पर प्रसारित हो चुका था, इसलिए काफी लोग जनरल वी के सिंह को पहचान रहे थे और वो लोग उनके अभिवादन में हाथ हिला रहे थे और दौड़कर उनसे हाथ मिला रहे थे और मिलाने की कोशिश कर रहे थे. इस परेड में जो तीसरी शख्सियत थी, वह अन्ना हजारे की थी. अन्ना हजारे इस परेड में शामिल होने के लिए विशेष तौर पर भारत से न्यूयार्क से पहुंचे थे. वे एक खुली कन्वर्टेबल कार में सवार थे. चूंकि अन्ना का कद छोटा है, इसलिए अन्ना खुली कार में सीट के ऊपर बैठ गए. अन्ना को लोगों ने जैसे ही देखा, चारों तरफ से लोगों का हुजूम रेलिंग को तोड़कर अन्ना की तरफ दौड़ पड़ा. अन्ना को छूने का, उनसे हाथ मिलाने का और अन्ना से बात करने का इतना ज्यादा माहौल बन गया कि अन्ना के सुरक्षाकर्मियों को काफी मुश्किलें आईं. अन्ना के लिए सुरक्षाकर्मी इसलिए रखे गए थे, क्योंकि लोगों को अंदाजा था कि भीड़ में आए हुए लोग अन्ना के नजदीक जाने की कोशिश करेंगे. सुरक्षाकर्मियों के लिए मुश्किल का समय था, लेकिन अन्ना ने किसी को भी निराश नहीं किया. उन्होंने हाथ मिलाए, नमस्ते किया और सबके अभिवादन का मुस्करा कर जवाब दिया. इस पूरी परेड में अन्ना हजारे का जिस तरह स्वागत हुआ, वह स्वागत अद्भुत था.

हमारा देश क्यों मर रहा है, इसका कारण कोई हिंदुस्तानी नहीं बता सकता, लेकिन देश मर रहा है, यह सबके मन में है और देश मर रहा है, यह भावना अमेरिकन-इंडियन के मन में होना कुछ दुख भी देता है, लेकिन उनका अन्ना के प्रति आशा रखना संभावना भी दिखाता है.

अमेरिका की सड़कों पर अन्ना हजारे जिंदाबाद, अन्ना आगे बढ़ो, जैसे नारे सुनना एक अलग तरह का अनुभव था. अन्ना हजारे को लोग अमेरिका में पहचानते हैं. नई उमर के लोग हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, या बच्चे हों. अन्ना का चेहरा अमेरिका में भारतीयों के बीच कैसे इतना जाना-पहचाना हो गया, शायद अन्ना भी इसे नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि अन्ना को भी यह अंदाजा नहीं था कि उनका यहां पर इतना स्वागत होगा. अन्ना अपने स्वागत से अभिभूत थे और इस अवस्था में उन्होंने अमेरिका की सड़कों पर वैसे ही नारे लगाए, जैसा कि वे अपनी सभाओं में लगाते हैं. भारत में अपनी सभाओं की शुरुआत में अन्ना खुद ही नारे लगाते हैं. वंदे मातरम्, भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद, यह तीनों नारे अन्ना ने अमेरिका की सड़कों पर लगाए और वहां मौजूद भारतीयों ने इसका जबरदस्त जवाब दिया, जिंदाबाद के रूप में. समूचा मेडिसन स्क्वॉयर, जहां से यह रैली जा रही थी, इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूज गया.

बहुत सारे दृश्य देखने को मिले. लोग दौड़कर बच्चों के सर पर हाथ रखवा रहे थे. औरतें किसी भी तरीके से एक बार अन्ना को छू लेना चाहती थीं और पुरुष अन्ना के साथ चलने, अन्ना से हाथ मिलाने, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए तरह-तरह के रास्ते निकाल रहे थे, क्योंकि अन्ना कहीं रुके नहीं थे. उनकी कार चल रही थी, लेकिन कार के आगे-पीछे, दाएं-बाएं सुरक्षाकर्मियों को धता बता कर, किसी भी तरीके से एक फोटो अन्ना के साथ हो जाए, इसको लेकर वैसा ही क्रेज अमेरिका में दिखाई दिया, जैसा क्रेज हम हिंदुस्तान में देखते हैं. हिंदुस्तान में भी हवाई अड्डा हो, बाजार हो, सभा हो, हर जगह अन्ना का पैर छूने की और उनके साथ फोटो खिंचाने की होड़ मची रहती है. जिस तरह हिंदुस्तान में अन्ना की बात सुनना दूसरी प्राथमिकता बन जाती है और उनके साथ फोटो खिंचवाना पहली प्राथमिकता बन जाती है. ऐसा ही माहौल यहां अमेरिका में दिखाई दिया.

लोग दौड़कर आते और कहते अन्ना! हिंदुस्तान को बचा लो. अन्ना! हिंदुस्तान आपके सहारे है. अन्ना! हम आपके साथ हैं, आप हमें आदेश दीजिए कि हम क्या करें. इन सारी बातों को सुनकर अन्ना मुस्कराते हुए अपना हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन कर रहे थे. अन्ना की इस शख्सियत का गवाह अमेरिका का मेडिसन स्क्वॉयर बना. अन्ना के स्वागत का गवाह अमेरिका का आकाश बना. अमेरिका में जो पुलिस वाले ड्यूटी पर थे, उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि एक शख्स जिसका न कोई व्यक्तित्व है और सामान्य-सी वेश-भूषा धोती-कुर्ता-टोपी और एक सदरी में है, ऐसी शख्सियत को देखकर उन्हें लगता कि इस आदमी को देखकर लोग क्यों इतना उत्साहित हो रहे हैं. स्वागत कर रहे हैं. लोग अन्ना-अन्ना क्यों चिल्ला रहे हैं? अन्ना भला कौन हैं? अमेरिका के पुलिसकर्मियों का यह आश्चर्य शायद बहुत सारे अमेरिकियों के लिए भी आश्चर्य था. अन्ना इस आश्चर्य के बीच में से गुजर रहे थे और अमेरिका अन्ना की वह यात्रा देख रहा था, जिस यात्रा को भारत के प्रधानमंत्री तक तरसते हैं. निकलते हुए लोगों का हृदय से स्वागत भारत में प्रधानमंत्रियों का पिछले हाल के वर्षों में कम होता हुआ देखा गया. अमेरिका में अन्ना प्रधानमंत्री तो नहीं थे, जो नजारा उनके स्वागत में दिखाई दे रहा था, उससे यह जरूर लग रहा था कि अन्ना यहां पर लोगों के दिलों के राजा हैं.

जहां से परेड गुजर रही थी, उसके सामने ही मंच लगा था, जिस पर विद्या बालन थीं और वे उसी फिल्मी अंदाज, लटके-झटके और नृत्य की मुद्रा में लोगों का अभिवादन कर रही थीं, जो देखकर मुझे कम से कम ऐसा लगा कि भारत की आजादी की परेड के नाम पर फिल्म स्टार शालीनता से लोगों का अभिवादन करें, अपनी नृत्य की मुद्रा न दिखाएं, जो कि छिछोरी लगती है, तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन विद्या बालन ने ऐसा किया. मंच से जनरल वी के सिंह ने भाषण दिया. जनरल वी के सिंह से कुछ सवाल सेना को लेकर, चीन को लेकर पूछे गए और जनरल ने उनके जवाब दिए, लेकिन जब अन्ना मंच पर पहुंचे, तो बस अन्ना ही अन्ना थे और ऐसा लगा कि इस पूरी भीड़ में जो आजादी का जश्न मनाने आई थी, वह अन्नामय हो गई थी और बस अन्ना-अन्ना के नारे लगा रही थी और एक, जो जबरदस्त नजारा दिखाई दिया कि हजारों लोग मैं अन्ना हूं, की टोपी पहने सड़कों पर मार्च कर रहे थे. मैं इस पूरी मार्च में एक दर्शक के तौर पर था, लेकिन एक समर्थक दौड़कर आया और उसने मुझे मैं अन्ना हूं, कि गांधी टोपी पहना दी. मेरे लिए उस दर्शक का, जो कहीं बाहर से आया हुआ था, टोपी पहनाना अभिभूत कर गया. अमेरिका की सड़कों पर हजारों लोग मैं अन्ना हूं, लिखी गांधी टोपी लगाए मार्च कर रहे थे. यह अद्भुत दृश्य था. अन्ना जब मंच पर गए, तो उन्होंने वहां पर छोटा-सा भाषण दिया. भाषण देकर जब नीचे उतर कर कार की तरफ जा रहे थे, तो एक कार वहां से गुजरी, जिसमें एक दंपत्ति जा रहा था. अचानक कार बीच सड़क पर रुकी और वह दंपत्ति कार से भागते हुए अन्ना के पास आए और कहा कि अन्ना! भारत को केवल आप ही बचा सकते हो. उन्होंने कहा कि हमारा देश मर रहा है, बर्बाद हो रहा है और हमारे देश को केवल आप ही बचा सकते हो और हाथ जोड़कर वहीं रोने लगे. यह दृश्य इतिहास में कहीं नहीं लिखा जाएगा, लेकिन यह दृश्य, जिसने भी देखा उनके जीवन के इतिहास का एक अमिट पन्ना बन गया.

अन्ना हजारे के साथ आशाएं क्यों जुड़ जाती हैं, पता नहीं. अन्ना हजारे को लोग भारत का भाग्य विधाता या भारत को दुर्भाग्य से बचाने वाला क्यों मान रहे हैं, पता नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञ तो अन्ना को कहीं गिनते ही नहीं हैं, लेकिन जिस तरह हिंदुस्तान में अन्ना से लोग प्यार करते हैं और अन्ना में एक संभावना देख रहे हैं, वैसा ही अमेरिका की सड़कों पर मुझे देखने को मिला कि लोग अन्ना में एक संभावना देख रहे हैं, अन्ना से आशा करते हैं. अन्ना से आग्रह कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान को बचाने के लिए कोई मजबूत कदम उठाएं. पता नहीं, अन्ना क्या कदम उठाएं, लेकिन लोग तो कम से कम चाहते ही हैं कि अन्ना कोई सख्त कदम उठाएं, ताकि हमारा देश बच सके. हमारा देश क्यों मर रहा है, इसका कारण कोई हिंदुस्तानी नहीं बता सका, लेकिन देश मर रहा है, यह सबके मन में है. और देश मर रहा है यह भावना अमेरिकन-इंडियन के मन में होना कुछ दुख भी देता है, लेकिन उनका अन्ना के प्रति आशा रखना संभावना भी दिखाता है. ■

editor@chauthiduniya.com

कश्मीरी झेल रहे हैं विभाजन का दंश

मेघनाद देसाई

जवाहर लाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक भारत के सभी प्रधानमंत्री आपसी विवादों को हल कर पाकिस्तान से अच्छे संबंध चाहते हैं. कश्मीर मसले पर दोनों ही देश आमने-सामने हैं. दोनों ही देश समझते हैं कि विभाजन गलत था और कश्मीरी उस गलती की सजा भुगत रहे हैं. यह मसला अभी जारी रहेगा.

सीमाओं पर देश दूसरी तरफ से पैदा की गई मुश्किलों से दो-चार हो रहा है, तो देश के आंतरिक हिस्से सांप्रदायिक दंगों की चपेट में हैं. अभी तक हल न हो सकने वाले इन सभी मसलों का दंश विभाजन और आजादी के दौर से ही हम झेल रहे हैं. और स्वतंत्रता की 66वीं वर्षगांठ तक यह समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं.

लगता है भारत के लिए दो समस्याएं चिरस्थाई हो गई हैं. पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर. दोनों आपस में एक दूसरे से गुंथी हुई हैं. दूसरी समस्या को हल किए बिना पहली समस्या से निपटा नहीं जा सकता और दोनों ही समस्याएं तभी हल की जा सकती हैं, जब तक विभाजन से पैदा हुई मुश्किलें हल न हो जाएं और इन मुश्किलों को एक-दूसरे पर हमला करके कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता. हां, बातचीत से इस मसले को हल किया जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस ओर कभी कोशिश ही नहीं की गई. हमें यह समझना होगा कि केवल बातचीत ही वह जरिया है, जो इन मुश्किलों को हल कर सकता है, लेकिन हो रहा है इसके विपरीत और दोनों ही देशों ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर इसे जीवित कर रखा है. इसकी परिणति यह है कि दोनों ही देश भय और आतंक के साये में जी रहे हैं.

मेरा एक दार्शनिक दोस्त है, जो भारतीय मूल का है. उसके नाम का मैं खुलासा नहीं करना चाहता. उसने मुझे सुझाव देते हुए कहा कि भारत को चाहिए कि वह कश्मीर पाकिस्तान को सौंप दे. उसका तर्क था कि पाकिस्तान के भीतर जो एकजुटता और एकमत है, वह केवल इस बात को लेकर है कि कश्मीर को भारत से हासिल ही करना है और अगर भारत पाकिस्तान को कश्मीर दे दे, तो उसके भीतर की यह एकजुटता खत्म हो जाएगी. हालांकि मैं इस मत का पक्षधर नहीं हूं. हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन अगर आजाद कश्मीर को लेकर पाकिस्तान भी ऐसी ही सोच रखता हो, तो क्या होगा? भारत इस मसले को कैसे संभालेगा.

तब क्या भला इतनी बड़ी सेना को लगाने की जरूरत वहां होगी. नहीं. मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की जरूरत होगी. नहीं, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि दोनों आजाद कश्मीर मिलकर एक हो जाएं और एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग करने लगें. तब तो भारत एक बार फिर कश्मीर पर हमला करके उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा.

जवाहर लाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह, भारत के सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने भाषणों में यह कहा कि वे पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं तथा सभी विवादों को हल करना चाहते हैं. हो सकता है कि जो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बनें, वे भी इसी राग में शामिल हो जाएं. तीन प्रधानमंत्रियों लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा और जीते. यद्यपि इन तीनों ही युद्धों के बाद पाकिस्तान को यह सबक नहीं सिखाया जा सका कि वह इस गलती को न दोहराए. इसलिए यह तो तय है कि युद्ध इन दोनों देशों के बीच की समस्या का हल नहीं हो सकता.

हालांकि हमें यह रास्ता भी नहीं मिल पाया है कि जम्मू-कश्मीर पर शांतिपूर्वक शासन कैसे किया जाए. हालांकि इसमें बड़ा दोष पाकिस्तान का भी है. पाकिस्तान आजाद कश्मीर के लिए लड़ रहा है. जो उन्हें मिला है, वे इस बात में संतोष कर सकते हैं. हम अगर कश्मीर को अपने देश का अंग मानते हैं, तो हमें उन्हें तवज्जो भी देनी होगी. क्या देश के अन्य हिस्सों में भी उतनी ही सेना है. नहीं. तो क्या देश के अन्य हिस्से देश का अंग नहीं हैं. हमें कश्मीर तक रेल सेवा बहाल करने में 66 साल लग गए, जबकि चीन ने बलिस्तिस्तान से अरब सागर के किनारे तक रेल लिंक बना लिया, जबकि वह उनकी सीमा में भी नहीं आता. कश्मीर के किसी युवा को भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ने में 66 साल लग गए. अब तक हमें यह भी नहीं पता था कि वे क्रिकेट भी खेलते हैं. किसी भी कश्मीरी को आईपीएल में कोई फ्रेंचाइजी नहीं मिली है.

अगर वहां पर बेरोजगारी है, तो किसी युवा को क्या फर्क पड़ता है. इसके लिए कई सारी कमेटियां गठित की गईं, लेकिन उन कमेटियों ने क्या संस्तुतियां दीं, इस बारे में आज तक किसी को कोई जानकारी नहीं. कश्मीरी तब तक वीजा नहीं हासिल कर सकते, जब तक वे यह स्पष्ट न कर दें कि उनका संबंध किसी आतंकवादी संगठन से नहीं है. हालांकि यह स्पष्ट करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि अगर किसी का संबंध आतंकवादी संगठन से है ही नहीं, तो फिर वहां सेना क्या कर रही है.

भारत कश्मीर के लिए उतना ही प्रतिबद्ध है, जितना कि पाकिस्तान. दोनों ही देश घाटी पर कब्जा करना चाहते हैं बिना यह समझे हुए कि वहां की जनता क्या चाहती है. जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो लेजिस्लेटर से केवल पंजाब और बंगाल के संदर्भ में सलाह ली गई. प्रिंसली स्टेट का मामला अलग था. कश्मीर के मसले पर दोनों ही देश आमने-सामने हैं. दोनों ही देश समझते हैं कि विभाजन गलत था और कश्मीरी उस गलती की सजा भुगत रहे हैं. यह मसला अभी जारी रहेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

भारत कश्मीर के लिए उतना ही प्रतिबद्ध है, जितना कि पाकिस्तान. दोनों ही देश घाटी पर कब्जा करना चाहते हैं बिना यह समझे हुए कि वहां की जनता क्या चाहती है. जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो लेजिस्लेटर से केवल पंजाब और बंगाल के संदर्भ में सलाह ली गई. प्रिंसली स्टेट का मामला अलग था. कश्मीर के मसले पर दोनों ही देश आमने-सामने हैं.

पंचायत की भूमि और पट्टे की जानकारी

चौथी दुनिया ब्यूरो

भारत की लगभग 67 फीसद जनसंख्या गांवों में ही रहती है. ग्रामीण भारत के लिए मुख्य संसाधन भूमि है. ऐसे में ग्राम पंचायत की ज़मीन का काफ़ी महत्व है. ग्राम पंचायत की ज़मीन अक्सर कई कामों के लिए पट्टे पर दी जाती है. जैसे भूमिहीनों को आवास के लिए, कृषि, खनन या वनीकरण के लिए. ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि वास्तव में कितनी ज़मीन किसे और कब तक के लिए पट्टे पर दी गई है. वास्तव में पंचायत के पास कितनी ज़मीन है. कहीं उसके वितरण (पट्टे देने) में कोई गड़बड़ी तो नहीं है. इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपके पास सूचना का अधिकार क़ानून है, जिसके तहत आप एक आवेदन देकर उक्त सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं. अपने आवेदन में आप यह पूछ सकते हैं कि पंचायत के पास अलग-अलग तरह की कितनी ज़मीन है. मसलन कृषि योग्य ज़मीन, बंजर ज़मीन, चारागाह की ज़मीन, ग्रामसभा की ज़मीन इत्यादि. इसके अलावा आप यह जानकारी भी मांग सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में किन परिवारों को किस कार्य के लिए और कितनी ज़मीन पट्टे पर दी गई. कितनी ज़मीन ऐसी है, जिसका अब तक कोई उपयोग नहीं हो सका. इस अंक में हम एक ऐसा ही आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप उक्त सूचनाएं मांग सकते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है:

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301 ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(भूमि और पट्टे से संबंधित जानकारी)

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी

(विभाग का नाम)

(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

.....में भूमि संबंधी निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. उपरोक्त ग्राम पंचायत की भूमि के संबंध में निम्न विवरण मानचित्र के साथ उपलब्ध कराएं:

(क) कितनी भूमि कृषि योग्य है (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित).

(ख) कितनी भूमि बंजर है (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित).

(ग) चारागाह की भूमि कितनी है (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित).

(घ) ग्राम समाज की भूमि कितनी है (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित).

(च) मरघट की भूमि कितनी है (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित).

(छ) तालाब की भूमि कितनी है (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित)

2. विगत 25 वर्षों में उपरोक्त ग्राम पंचायत के कितने परिवारों को निम्नलिखित से संबंधित पट्टे दिए गए? विवरण मानचित्र के साथ उपलब्ध कराएं:

(क) कृषि योग्य पट्टे (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित).

(ख) आवासीय पट्टे (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित).

(ग) खनन योग्य पट्टे (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित).

(घ) वनीकरण पट्टे (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित).

(ज) अन्य कोई पट्टे (रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित).

3. वर्ष.....से.....के दौरान उपरोक्त ग्राम पंचायत के कितने भूमिहीन परिवारों को पट्टे दिए गए? इसकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं, जिसमें रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल मानचित्र सहित शामिल हो:

क. पट्टाधारक का नाम.

ख. पट्टाधारक के पिता का नाम.

ग. पट्टाधारक का पता.

घ. पट्टा दिए जाने की तारीख़.

4. वर्ष.....से.....के दौरान उपरोक्त ग्राम पंचायत के कितने परिवारों को कृषि योग्य भूमि के पट्टे दिए गए? इसकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं, जिसमें रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल मानचित्र सहित शामिल हो:

क. पट्टाधारक का नाम.

ख. पट्टाधारक के पिता का नाम.

ग. पट्टाधारक का पता.

घ. पट्टा दिए जाने की तारीख़.

5. वर्ष.....से.....के दौरान उपरोक्त ग्राम पंचायत के कितने परिवारों को आवासीय पट्टे दिए गए? इसकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं, जिसमें रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल मानचित्र सहित शामिल हो:

क. पट्टाधारक का नाम.

ख. पट्टाधारक के पिता का नाम.

ग. पट्टाधारक का पता.

घ. पट्टा दिए जाने की तारीख़.

6. वर्ष.....से.....के दौरान उपरोक्त ग्राम पंचायत के कितने परिवारों को खनन योग्य भूमि के पट्टे दिए गए? इसकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं, जिसमें रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल मानचित्र सहित शामिल हो:

क. पट्टाधारक का नाम.

ख. पट्टाधारक के पिता का नाम.

ग. पट्टाधारक का पता.

घ. पट्टा दिए जाने की तारीख़.

7. वर्ष.....से..... के दौरान उपरोक्त ग्राम पंचायत के कितने परिवारों को वनीकरण पट्टे दिए गए? इसकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं, जिसमें रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल मानचित्र सहित शामिल हो:

क. पट्टाधारक का नाम.

ख. पट्टाधारक के पिता का नाम.

ग. पट्टाधारक का पता.

घ. पट्टा दिए जाने की तारीख.

8. वर्तमान में ग्राम पंचायत में ग्राम समाज की ऐसी कितनी भूमि शेष है, जिसका अभी तक किसी पट्टे के लिए उपयोग नहीं किया गया है? रकबा नंबर एवं क्षेत्रफल मानचित्र सहित उपलब्ध कराएं.

9. ग्राम पंचायत में भूमिहीन परिवारों को पट्टा देने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं? इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पद एवं पता बताएं. इससे संबंधित सभी शासनादेशों एवं निर्देशों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....

पता.....

फोन नंबर.....

संलग्नक.....

(यदि कुछ हो तो)

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)

इस सप्ताह अपने कमाये धन का सदुपयोग करेंगे और आमतौर पर खुश और उत्साहित रहेंगे. पारिवारिक सुख उत्तम रहेगा. व्यापारी अपने व्यापार में थोड़ा उतार-चढ़ाव महसूस करेंगे. पारिवारिक या मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकता है. वाहन सावधानी से चलाएं. व्यर्थ का भाग-दौड़ करने से बचें. कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)

इस सप्ताह सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. इस सप्ताह आपके आय के स्रोत्र बढ़ेंगे. आपके संपर्क उच्च प्रतिष्ठित और संपन्न लोगों के साथ बढ़ेगा और आप लाभान्वित होंगे. कुछ अच्छे कार्य होने की भी पूर्ण संभावना बनेगी. संपत्ति और वाहन आदि का क्रय संभव है. माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है.

मिथुन (21 मई से 20 जून)

इस सप्ताह कानूनी दांव-पेंच से बच कर चलें. किसी भी कानूनी दस्तावेज को जांच-परख कर हस्ताक्षर करें. इस सप्ताह आप अपनी व्यक्तिगत छवि में निखार लाने की सोचेंगे. इस सप्ताह आप सामाजिक और धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे. आप प्रगति की राह पर चलेंगे और बहुत सारे कार्य संपन्न होंगे. स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)

इस सप्ताह नौकरी-पेशा लोग अपनी कार्य कुशलता के वजह से सम्मान प्राप्त करेंगे. इस सप्ताह आप किसी नये उद्यम लगाने की सोचेंगे. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और संतान सुख भी प्राप्त होगा. इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. इस सप्ताह आप कल्पना में खोने से बचें और अपनी कार्य शैली का प्रदर्शन करें.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)

इस सप्ताह आप लम्बे भाग-दौड़ के लिए तैयार रहें. किसी के विरोधाभासी स्वर से विचलित न हों. अपने भावना का सम्मान करें और परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह अच्छे से करें. इस सप्ताह आप सामाजिक और सामूहिक उत्सव में हिस्सा लेंगे. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खास कर मौसमी बीमारी परेशानी का कारण बन सकती है.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)

इस सप्ताह आपके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आएगा. संतान सुख उत्तम रहेगा. इस सप्ताह पारिवारिक सदस्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त रहेगा और आप उर्जा से लबरेज रहेंगे. निवेश करने से पहले जरूर सोच-विचार कर लें. व्यापारी वर्ग थोड़े उतार-चढ़ाव से विचलित न हों. नौकरी-पेशा लोग प्रगति की राह पर रहेंगे.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)

इस सप्ताह जोखिम वाले बाज़ार से बचें. इस सप्ताह आप कर्म को प्रधानता देंगे और बहुत मेहनत करेंगे. इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास भी चरम पर होगा. आपके विरोधी उभरने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने पराक्रम से अपने विरोधियों का दमन कर देंगे. आप इस सप्ताह फिजूल के विवाद से बचें. संपत्ति क्रय में थोड़ा सावधानी से काम लें.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)

इस सप्ताह पैसे से ज्यादा आप अपनी प्रतिष्ठा पर ध्यान देंगे और मान-सम्मान भी बढ़ेगा. आपके संपर्क के लोग ही आपके फायदे का कारण बनेंगे. दांपत्य जीवन और संतान सुख अच्छा रहेगा. व्यापारी और नौकरी-पेशा दोनों वर्ग सुख का अनुभव करेंगे. उत्तेजना में कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)

इस सप्ताह कोई नई संपत्ति लेने का विचार बनेगा और उसके लिए थोड़ा कर्ज लेने की जरूरत भी हो सकती है. वाहन सावधानी से चलाएं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है. जोखिखम भरे व्यापार से बचें. कोई अगर बेवजह आपका दुरुपयोग करना चाह रहा है, तो आप उससे बचें. आप तनाव और झगड़े-झंझट से बचें.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)

इस सप्ताह नियमित आय के अलावा आप दूसरे स्रोतों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे और इसमें सफलता भी मिलेगी. किसी भी संपत्ति की खरीद में कानूनी दस्तावेज को जांच-परख कर खरीदें. व्यावसायिक साझेदारी में थोड़ा ध्यान रखें और संभल कर चलें. नौकरी-पेशा लोग अपने कार्य स्थल पर विवाद न बढ़ने दें.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)

इस सप्ताह पारिवारिक और सामाजिक कार्य पर धन व्यय होगा. सामाजिक कार्य में लिप्त होने के बावजूद लोग आपकी शिकायत कर सकते हैं. आप विचलित न हों. परिवार के ही किसी बुजुर्ग का सहयोग मिलेगा और आप संतुष्ट रहेंगे. आप अपनी संयम और संतुलन को न खोएं. लम्बी यात्रा की योजना बनेगी और आप फायदे में रहेंगे.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)

इस सप्ताह आप अपने करियर की उन्नति से संबंधित उत्साहजनक प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी हाथ लगेगी. व्यावसायी थोड़े उतार-चढ़ाव महसूस करेंगे. अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. पुराने प्रयासों में सफलता मिलेगी. धार्मिक कार्यों और दान धर्म पर विश्वास बढ़ेगा और आपका इसमें कुछ समय भी व्यतीत होगा. परिवार में ग़लतफहमी न बढ़ने दें.

ज़रा हट के

जब भौंकने लगा शेर

आज तक आपने कुत्ते को भौंकते हुए सुना होगा, लेकिन जब आपको शेर भौंकता हुआ नजर आए, तो आप क्या करेंगे. यह मजेदार वाकया हुआ चीन के चिड़ियाघर में, जहां तिब्बती नस्ल के एक कुत्ते को शेर बताकर दर्शकों के सामने पेश कर दिया गया. जिस कुत्ते को शेर बनाकर पेश किया गया, उसके बाल बढ़े-बढ़े थे. चिड़ियाघर प्रशासन ने इसी बात का फायदा उठाया और उसे अफ्रीकी शेर बता दिया. अब पोल खुलने के बाद चिड़ियाघर प्रशासन सफाई देता फिर रहा है. चीनी मीडिया के मुताबिक, हेनान प्रांत के एक चिड़ियाघर में कुत्ते को शेर के तौर पर पेश किया जा रहा था. वहीं सांप के बिल में चूहे, तेंदुए की मांद में सफेद लोमड़ी और भेड़िये के बाड़े में कुत्ते रखकर दर्शकों को धोखा दिया जा रहा था. वो भी तब, जब चिड़ियाघर में प्रवेश के लिए भारी-भरकम टिकट की व्यवस्था थी.■

बोल उठा मुर्दा

कितना आश्चर्य होगा, जब आपको यह पता चलेगा कि कोई मृत व्यक्ति फिर से जी उठा. अगर सचमुच ऐसा हो जाए, तो डरना स्वाभाविक है. भले ही हमारी बातों पर आपको यकीन न हो, लेकिन चीन में कुछ ऐसा ही हुआ. चीन में एक आदमी को सुरक्षाकर्मियों ने इस कदर पीटा कि वह मरणासन्न हो गया. उसके साथी उसे पीटने वालों से हर्जाना वसूलने ही वाले थे कि वह अचानक उठ बैठा और बोला, काफी गर्मी है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता.

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाले हान को शहरी सुरक्षाकर्मियों ने पीटा था. हान को उसके 10 साथी स्ट्रेचर पर रखकर उसे पीटने वाले के पास ले गए और मृत बताकर मुआवजे की मांग करने लगे. इस शोर-शराबे के बीच करीब 80 पुलिस अधिकारी और तीन सौ अन्य लोग उन्हें घेर कर जमा हो गए, जिससे गर्मी काफी बढ़ गई. आखिरकार हान उठकर खड़ा हो गया और कहा कि काफी गर्मी है. मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता. मुझे पीने के लिए पानी दो. ■

सड़कों को रोशन करेंगे पेड़

कैसा नजारा होगा, जब पेड़ अंधेरे को दूर भगाने का काम करने लगेंगे. जी हां, अब सड़कों पर अंधेरा गुजरे जमाने की बात हो जाएगी. अब रात में रोशनी के लिए स्ट्रीटलाइटों का नहीं, बल्कि वृक्षों का इस्तेमाल किया जाएगा. इससे न सिर्फ बिजली उत्पादन में खर्च हो रहे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी, बल्कि शहरों में वृक्षारोपण को भी बढ़ावा मिलेगा. अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर के वैज्ञानिक और उद्योगपति ओमरी अमिराव ड्रोरी की मानें, तो जीन संशोधन के जरिये ऐसे छोटे वृक्षों का विकास किया जा सकता है, जिनसे जुगनू के समान प्रकाश फैलाने वाले प्रोटीन का रिसाव होता रहे. ड्रोरी ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, जब इस तरह के पौधे रोड लैंपों की जगह लें लेंगे. ■

चुने हुए राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को अपदस्थ कर सैनिक शासन लगाए जाने के बाद मोर्सी समर्थक और उनके विरोधी सड़क पर हैं और टकराव के बीच सेना की दमनात्मक कार्रवाई जारी है. मुस्लिम ब्रदरहुड के मुताबिक, अब तक 2200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. यह कत्लेआम लोकतंत्र और इस्लामिक कट्टरवाद के बीच सत्ता पर काबिज होने के लिए हो रहे संघर्ष का परिणाम है.

अराजकता की भेंट चढ़ती क्रांति

कृष्णकांत

मिस्र में अधिनायकवाद के खिलाफ आम जनता के उठ खड़े होने के बाद 25 जनवरी, 2011 को लोकतंत्र के लिए क्रांति की जो पटकथा लिखी गई थी, वह एक बार फिर अधिनायकवाद की चपेट में आने से रक्तरंजित हो गई है. 60 साल की तानाशाही के बाद उभरे जनाक्रोश ने मिस्र को एक सुनहरा अवसर दिया था कि वह लोकतंत्र का सुगम रास्ता पकड़ सके, लेकिन तीन जुलाई को चुनी हुई सरकार के तख्तापलट के साथ मिस्र ने यह अवसर खो दिया. सेना ने तख्तापलट के पीछे तर्क दिया कि देश की जनता मोहम्मद मोर्सी सरकार से असंतुष्ट है और सड़कों पर उतर आई है. हालांकि, तख्तापलट के बाद तहरीर चौक पर क्रांति की आकांक्षा रखने वाली जनता फिर से सड़क पर उतर पड़ी है, परंतु तानाशाही अपने नये रूप में दमन चक्र चला रही है. सात अगस्त को मिस्र की राजधानी काहिरा में 620 लोगों का कत्लेआम हुआ. कुछ लोगों का दावा है कि इस दिन करीब एक हजार लोग मारे गए हैं. नौ अगस्त को भी करीब 180 लोग मारे गए. हर दिन हिंसक प्रदर्शनों और संघर्ष के चलते बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं. मुस्लिम ब्रदरहुड का दावा है कि मोर्सी को हटाए जाने के बाद अब तक संघर्ष में 2200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. लगातार हिंसा के बाद स्थिति इतनी जटिल हो गई है कि अब मिस्र में कोई शांतिपूर्ण समाधान निकालना बेहद कठिन हो गया है. बढ़ती हिंसा और कत्लेआम से परेशान उपराष्ट्रपति मोहम्मद अलबरदेई ने इस्तीफा दे दिया है. 14 अगस्त से देश में आपात स्थिति की घोषणा हो गई है. चुने हुए राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को अपदस्थ कर सैनिक शासन लगाए जाने के बाद मोर्सी समर्थक और उनके विरोधी सड़क पर हैं और टकराव के बीच सेना की दमनात्मक कार्रवाई जारी है. हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं. यह कत्लेआम लोकतंत्र और इस्लामिक कट्टरवाद के बीच सत्ता पर काबिज होने के लिए जारी संघर्ष का नतीजा है.

जो लोग वास्तविक क्रांति के लिए सड़क पर उतरे थे, उन्होंने राष्ट्रपति मोर्सी और मुस्लिम ब्रदरहुड के देश पर इस्लामिक मूल्यों को थोपने के प्रयासों को कबूल नहीं किया और लोकतंत्र के नाम पर मिस्र को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत लोग अपनी हार मानने को तैयार नहीं हैं. फरवरी, 2011 में 30 सालों से मिस्र की सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने जनता के व्यापक विरोध के बाद पद छोड़ा और सेना को सत्ता सौंपी. 2012 में मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता मोहम्मद मोर्सी को राष्ट्रपति चुना गया. लोकतांत्रिक ढंग से राष्ट्रपति चुने जाने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि मिस्र की क्रांति जिस उद्देश्य से अमल में लाई गई थी, वह पूरा हुआ, लेकिन उन उम्मीदों पर तब पानी फिर गया, जब मोर्सी ने एक आदेश पारित कर न्यायपालिका के उस अधिकार को खत्म कर दिया, जिसके तहत न्यायपालिका राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती दे सकती थी. हालांकि, उनके इस फैसले का व्यापक विरोध हुआ और उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन सत्ता के इस्लामीकरण की कोशिशें यहीं नहीं थमीं. दिसंबर 2012 में इस्लामी प्रभुत्व वाली संवैधानिक परिषद ने नये संविधान के मसौदे को मंजूरी दी, जिसमें इस्लामिक कानून को खास तवज्जो दी गई. बोलने की आजादी पर पाबंदी लगा दी गई. विपक्षी नेताओं ने इस पर जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें तमाम अन्य संगठनों ने भी हिस्सा लिया.

राष्ट्रपति मोर्सी ने लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस्लाम को मजबूत करने की कोशिश की. जनवरी में एक राजनीतिक प्रदर्शनों में 50 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सेना की ओर से चेतावनी दी गई कि राजनीतिक तनाव के चलते देश टूटने के कगार पर पहुंच गया है. जून, 2013 में उन्होंने 27 गर्वनरों में से 13 इस्लामी सहयोगी नियुक्त कर दिए. सबसे विवादित नियुक्ति रही पूर्व हथियारबंद इस्लामिक गुट के एक सदस्य की, जिनका नाम लक्जर में पर्यटकों की हत्या के मामले में आया था. इसके बाद फिर प्रदर्शन शुरू हो गए. देशव्यापी प्रदर्शनों के बाद सेना ने पूरे काहिरा को अपने कब्जे में लेकर तोपें तैनात कर दीं और मोर्सी को पद से हटा दिया. हजारों की संख्या में विपक्षी सड़क पर उतरे, तो दूसरी ओर मोर्सी समर्थक भी बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए. सेना प्रमुख जनरल अल सीसी ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अदली मंसूर को नया अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया और देश के संविधान को अपदस्थ करते हुए घोषणा की कि फिर से चुनाव होने तक मंसूर राष्ट्रपति बने रहेंगे. मंसूर ने जो नये चुनाव की योजना पेश की, उसे मोर्सी समर्थकों ने खारिज कर दिया और लगातार प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों की सेना के साथ झड़पें शुरू हो गईं. अगस्त में मोर्सी समर्थकों ने काहिरा में कैंप बनाया और प्रदर्शन शुरू किया. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए. लगातार काहिरा में प्रदर्शन, हिंसा और टकराव जारी है. लगातार हत्याओं से मिस्र की सड़कें खून से नहाई हुई हैं. 19 अगस्त को मिस्र की एक अदालत ने होस्नी मुबारक की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन अब मुबारक मिस्र के राजनीतिक फ्रेम से बाहर हो चुके हैं. फिलहाल कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है. लगातार हो रही हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ गंभीर चिंता तो जताई है, लेकिन फिलहाल कोई मध्यस्थता या हस्तक्षेप जैसी स्थिति नहीं है.

मिस्र का संकट यह है कि मुबारक की तानाशाही के खात्मे के बाद राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोर्सी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस्लामिक रंग देना शुरू कर दिया, तो विपक्षी पार्टियों ने अपनी हार के बाद मोर्सी का खेल बिगाड़ने का काम शुरू कर दिया. सभी विपक्षी पार्टियां नेशनल साल्वेशन फ्रंट के तहत इकट्ठा हो गईं और तख्तापलट को समर्थन दिया. इस अस्थिरता को कहीं न कहीं अमेरिका और ब्रिटेन का भी मौन समर्थन हासिल रहा. अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि तानाशाही से मुक्त हुआ मिस्र सैन्य शासन के चंगुल में फंस गया है. हालांकि, बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग संघर्षरत हैं, जो मिस्र में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की आशा अभी भी पाले हुए हैं. ■

मिस्र का संकट यह है कि होस्नी मुबारक की तानाशाही के खात्मे के बाद राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोर्सी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस्लामिक रंग में रंगने की कोशिश शुरू कर दी, तो विपक्षी पार्टियों ने अपनी हार के बाद मोर्सी का खेल बिगाड़ने का काम शुरू कर दिया.

क्या है क्रांतियों की कमज़ोर नब्ज़

मिस्र और कुछ अन्य देशों, जहां पर क्रांतियां या विद्रोह हुए, उन पर गौर करने के बाद मन में सहज सवाल उठ सकता है कि क्या कारण है कि ज्यादातर बदलाव की आकांक्षा से हुए विद्रोह के बाद जनता को अराजकता ही नसीब होती है? सीरिया में 21 अगस्त को हुए रासायनिक हमले में 1300 से अधिक लोग मारे गए. वहां विद्रोह उठने के बाद से अब तक एक लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं. मिश्र में हर दिन नरसंहार जैसी स्थिति है. यमन, ट्यूनीशिया, लीबिया आदि देशों में भी क्रांति का ज्वार उठने के बाद अस्थिरता बनी हुई है. अरब देशों में हमेशा क्रांतियों का अंजाम वही हुआ है, जो आज मिस्र, लीबिया या अन्य देशों का हुआ. अगस्त 1970 में पत्रकार राजेंद्र माथुर ने अपने एक लेख में लिखा था कि क्रांतियां अरब देशों में इस तरह होती हैं, जैसे कस्बे के सिनेमा में नई स्टंट पिक्चर लगी हो. 1948 से 1969 के बीच इन देशों में 25 सफल क्रांतियां हुईं और कम से कम 38 असफल रहीं. अरब मुल्कों की ज्यादातर क्रांतियां फौज ने की हैं. इससे जाहिर है कि वहां की बहुतेरी राजनीति फौजी छावनियों में चलती है. फौज में ही राजनीतिक पार्टियां हैं और फौज में ही गुट हैं. फौजी राजनीति शायद मुस्लिम देशों का आवश्यक अंग है.

इतिहास गवाह है कि दुनिया में जिन-जिन देशों में क्रांतियां हुई हैं, वहां-वहां निर्माण से ज्यादा विध्वंस हुआ है. पिछली तीन-चार सदियों में कुछ ही देश ऐसे हैं, जहां पर लोकतंत्र की स्थापना टिकाऊ साबित हुई. हालांकि, क्रांतियों के कुछ-एक सुखद उदाहरण भी हैं, जहां जनता ने क्रांति का झंडा बुलंद किया और नई व्यवस्था का सूत्रपात हुआ. क्रांतियों में आमतौर पर दो तरह की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं. एक तो यह कि बदलाव की सोची-समझी रणनीति के तहत लंबे समय तक संघर्ष कर के क्रांति आई और वह पूर्णतः या आंशिक तौर पर सफल रही. दूसरी यह कि अचानक एक ज्वार उठा, तख्ता पलट हुआ, लेकिन नई सत्ता का नजरिया नई व्यवस्था को दिशा दे पाने को लेकर स्पष्ट नहीं रहा और अंजाम के तौर पर क्रांति अपने उद्देश्यों से दूर ही रह गई. उदाहरण के तौर पर भारत में 1857 की क्रांति का यही हश्र हुआ, जब अचानक सैनिकों ने विद्रोह किया, लेकिन ब्रिटिश शासन ने उसे बेरहमी से कुचल दिया. पाकिस्तान में उसके जन्म के बाद से कई बार तख्ता पलट हुए, लेकिन आज भी पाकिस्तान अस्थिर बना हुआ है. 1979 में ईरानी क्रांति का नतीजा हुआ कि ईरान कट्टर इस्लामी राष्ट्र ही रह गया.

फ्रांस, रूस, क्यूबा, चीन, वियतनाम आदि देश क्रांतियों के माध्यम से नई व्यवस्था के सूत्रपात की कहानी कहते हैं. 19वीं सदी में मार्क्स और एंगेल्स ने क्रांति का जो विचार प्रस्तुत किया था, वह 20वीं सदी को विरासत में मिला. बीसवीं सदी क्रांतियों की सदी रही है. दुनिया भर में तमाम देशों की जनता को पुरानी व्यवस्थाओं को उलट कर नई व्यवस्था स्थापित की, लेकिन ज्यादातर जगहों पर उनकी सफलता पर ग्रहण लग गया. सोवियत रूस के ढहने के बाद समाजवादी देशों की क्रांतियों पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया, जिसने दुनिया को दो ध्रुवों में बांट दिया था. ज्यादातर क्रांतियों के बारे में आप पाएंगे कि वे शुरू हुईं किसी और मकसद के साथ, पहुंच गईं कहीं और उनका अंत कहीं और जाकर हुआ. ज्यादातर क्रांतियों के बाद निरंकुश शासन की स्थापना हुई. आखिरकार आप यह कह सकते हैं कि बदलाव के लिए सिर्फ आक्रोश ही काफी नहीं है. उसे एक निश्चित राजनीतिक दिशा दिए बिना किसी क्रांति का कोई अर्थ नहीं. वैसे भी क्रांतियां तुरंत नहीं हो जातीं. यह पीढ़ियों के संघर्ष का परिणाम है. फ्रांस, रूस और चीन की क्रांति इसका उदाहरण है, जहां पर बदलाव के लिए दशकों तक संघर्ष चलता रहा. ■

फेसबुक से उठी क्रांति पर भी सवाल

फेसबुक पर आह्वान के बाद काहिरा के तहरीर चौक पर उमड़े जन समुदाय के बाद भारत समेत कई देशों में ऐसी घटनाएं हुईं, जब लगा कि क्रांति के रास्ते में फेसबुक अथवा सोशल मीडिया बहुत निर्णायक भूमिका निभाने वाला है. यह सवाल उठे कि क्या दुनिया की अगली क्रांति की पटकथा फेसबुक, ट्विटर और मोबाइल फोन के जरिये लिखी जाएगी? अरब देशों में हुई क्रांति फेसबुक के इस्तेमाल की अनोखी मिसाल रही. भारत में अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी फेसबुक के जरिये काफी प्रसारित हुआ. इन हालातों को देखते हुए सोशल साइट्स का क्रांति के लिए कैसे इस्तेमाल करें, इसकी पढ़ाई के लिए इटली में एक केंद्र खोला गया है, लेकिन अरब जगत के हालात और भारत में अन्ना आंदोलन यह सबक देते हैं कि फेसबुक जन संवेदनाओं के उभार में मदद करने वाला एक माध्यम तो हो सकता है, लेकिन उससे संपूर्ण क्रांति नहीं हो सकती. क्रांति के लिए स्पष्ट नेतृत्व, व्यापक रणनीति और उसे दिशा देने का कौशल होना चाहिए. हालांकि, इसमें कोई दो राय नहीं कि फेसबुक या सोशल मीडिया के अन्य मंच क्रांति में मदद के लिए बेहतर माध्यम हो सकते हैं. ■

साई

साई बाबा का कहना था कि सबका मालिक एक है. इसी सूत्र के कारण सभी धर्मों के लोग साई बाबा के प्रति अटूट आस्था और विश्वास रखते हैं. शिरडी के साई बाबा के भक्त भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में हैं. उनके फकीर स्वभाव और चमत्कारों की कई कथांए हैं. बाबा के सभी भक्त उनकी चित्र और मूर्ति अपने घरों में अवश्य रखते हैं. साई बाबा ने अपना पूरा जीवन जन सेवा में ही व्यतीत किया.

आस्था

गुरुवार को साई की करें विशेष पूजा

चौथी दुनिया ब्यूरो

गुरुवार का दिन साई बाबा के आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है. साई मंदिर में गुरुवार को काफी भीड़ होती है. शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुवार गुरु की पूजा करने का दिन है और लोग साई को अपना गुरु मानते हैं. गुरुवार का दिन साई के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है. साई बाबा ने अपना पूरा जीवन लोगों की परेशानियों, कष्टों को दूर करने और सभी की मनोकामनाओं को पूरा करने में ही बिताया है. बाबा आज भी अपनों के सभी कष्टों और दुखों को दूर करते हैं और मनोकामनाओं को पूरा करते हैं. अगर गुरुवार को व्रत रखते हैं, तो सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर घर या नजदीकी साई मंदिर में जाकर पूजा करें. साई बाबा के पूजा में पीला कुमकुम या चन्दन, अक्षत, फल, फूल, माला, मिठाई इत्यादि चढ़ाएं. साई को गुलाब का फूल चढ़ाने का विशेष महत्व है. साई बाबा में गहरी आस्था रखने वाले गुरुवार को व्रत रख सकते हैं. साई को फल और मिठाइयां अर्पित करना चाहिए. पूजा करने के बाद प्रसाद सबको देना चाहिए. कहा जाता है कि प्रसाद बांटने से भक्तों के सब कष्ट दूर होते हैं और वह रोगों से मुक्त होकर, सदैव प्रसन्न रहता है.

साई बाबा का कहना था कि सबका मालिक एक है. इसी सूत्र के कारण सभी धर्मों के लोग साई बाबा के प्रति अटूट आस्था और विश्वास रखते हैं. शिरडी के साई बाबा के भक्त भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में हैं. उनके फकीर स्वभाव और चमत्कारों की कई कथाएं हैं. बाबा के सभी भक्त उनकी चित्र और मुर्ति अपने घरों में अवश्य रखते हैं. साई बाबा ने अपना पूरा जीवन जन सेवा में ही व्यतीत किया. वह प्रत्येक समय दूसरों के दुख–दर्द दूर करते रहे हैं. बाबा के जन्म के बारे में कोई सटीक उल्लेख नहीं मिलता है. बाबा के चमत्कारों का रहस्य उनके सिद्धान्तों से ही मिलता है. उन्होंने कुछ ऐसे सुत्र दिए हैं, जिन्हें मुनष्य अपने जीवन में उसका पालन करके सफल हो सकता है. हमें साई द्वारा दिए सूत्रों को समझना होगा. साई बाबा के पूरे जीवन काल पर हम नजर डालें, तो पता चलता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था. उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और लोगों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए. खुद साई शक्ति सम्पन्न होते हुए भी कभी उन्होंने अपने लिए शक्ति का उपयोग नहीं किया. वह हमेशा सादा जीवन जीते रहे. साई ने यही शिक्षा पूरे संसार को दी है. साई शिरडी में एक आम आदमी की तरह ही रहते थे. उनका पूरा जीवन हमारे लिए आदर्श है. उन्होंने जो शिक्षा दिया है, उसे हम अपने जीवन में उपयोग कर समाज में एकरूपता और शांति प्राप्त कर सकते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301

साई बाबा के अनमोल वचन

- आने वाला जीवन तभी शानदार हो सकता है, जब तुम ईश्वर के साथ पूर्ण सद्भाव में सीख जाओगे.
- मनुष्य अपने स्वाद की तृप्ति के लिए प्रकृति में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में बदलाव चाहता है, जिससे उसमें निहित जीवन के सार का अंत हो जाता है.
- तुम्हें एक कमल की तरह होना चाहिए, जो सूर्य प्रकाश में अपनी पंखुड़ियों को खोल देता है. कीचड़ में जन्म लेने या अपने अन्दर जल की उपस्थिति से अप्रभावित, जो इसे जीवित रखता है.
- मनुष्य अनुभव के माध्यम से सीखता है और आध्यात्मिक पथ विभिन्न प्रकार के अनुभवों से भरा है. उसे कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना होगा और वे सारे अनुभव, जो उसे प्रोत्साहित करने और सफाई की प्रक्रिया पूरा करने के लिए जरूरी है.
- सभी कार्य विचारों के परिणाम होते हैं, इसलिए विचार के मायने रखते हैं.
- मनुष्य खो गया है और एक जंगल में भटक रहा है. जहां वास्तविक मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है. वास्तविक मूल्यों का मनुष्य के लिए तभी अर्थ हो सकता है, जब वह आध्यात्मिक पथ पर कदम बढ़ाए. यह एक ऐसा पथ है, जहां नकारात्मक भावनाओं का कोई उपयोग नहीं.
- तुम्हें अपने दिनों को गीतों में बिताना चाहिए. तुम्हारा संपूर्ण जीवन एक गीत की तरह हो.
- यह दुनिया प्यार के प्रवाह से शुद्ध हो. तब आदमी, उथल–पुथल की स्थिति, जो उसने अपने जीवन के पिछले तरीकों के द्वारा, उन सभी सामग्री, हितों और सांसारिक महत्वाकांक्षा के साथ बनाया है, के बजाय शांति से रह सके.
- ब्रह्ममांड की तरफ देखो और ईश्वर की महिमा का मनन करो. सितारों को देखो. उनमें से लाखों, रात को आसमान में चमकते, सब एकता के संदेश के साथ, ईश्वर के स्वभाव के अंग हैं.
- आप अपने चारों ओर देखते हो, इससे गुमराह मत हो या आप जो भी देखते हो, उससे प्रभावित होते हो. आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, जो गलत रास्ते, झूठे मुल्यों और झूठे आदर्शों से भरा भ्रम का एक खेल का मैदान है, लेकिन आप उस दुनिया का हिस्सा नहीं हो.
- एक घर ठोस नींव पर बनाया जाना चाहिए. यदि इसे टिकाऊ बनाना है. यही सिद्धांत आदमी पर लागू भी होता है. अन्यथा वह भी नरम जमीन में वापस धस जाएगा और भ्रम की दुनिया द्वारा निगल लिया जाएगा.
- दुनिया में क्या नया है? कुछ भी नहीं. दुनिया में क्या पुराना है? कुछ भी नहीं. सब कुछ हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा.
- जीवन एक गीत है–इसे गाओ. जीवन एक खेल है–इसे खेलो. जीवन एक चुनौती है–इसका सामना करो. जीवन एक सपना है–इसे अनुभव करो. जीवन एक यज्ञ है–इसे पेश करो. जीवन प्यार है–इसका आनंद लो.
- एक दूसरे से प्रेम करो और उच्च स्तर तक जाने के लिए दूसरों की मदद करो, सिर्फ प्यार देकर. प्रेम संक्रामक और घावों को भरनेवाली सबसे बड़ी उर्जा है.
- वर्तमान में जीना सबसे ज्यादा मायने रखता है. इस क्षण को जियो, हर पल अभी है. यह इस क्षण के तुम्हारे विचार और कर्म हैं, जो तुम्हारे भविष्य को बनाते हैं, तुम अपने अतीत से जो पैटर्न बनाते हो, वही तुम्हारे भविष्य के मार्ग की रूपरेखा बनाते हैं. ■

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, सांई से आप कब और कैसे जुड़े. सांई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. सांई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

आस्था

शक्ति स्वरुपा ज्वालामुखी देवी

धर्मेन्द्र कुमार सिंह

ज्वालामुखी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी से 30 किमी दक्षिण में स्थित है. ज्वालामुखी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है. इस मंदिर को जोता वाली और नगरकोट के नाम से भी जाना जाता है. कहा जाता है कि पवित्र ज्वालामुखी मंदिर की खोज पांडवों ने की थी. इस स्थान पर माता शती की जीभ गिरी थी और यहां मंदिर में माता के दर्शन ज्योति के रूप में होते हैं. मंदिर के गुम्बद पर सोने का चादर लगा हुआ है. इस मंदिर का निर्माण पहले राजा भूमि चन्द ने करवाया था. उसके बाद महराजा रणजीत सिंह और राजा संसारचन्द ने 1835 में इस मंदिर का पुर्ण निर्माण कराया. मंदिर का मुख्य द्वार बहुत सुन्दर एवं भव्य है. ज्वालामुखी मंदिर के अन्दर नौ ज्योतियां हैं, जिन्हें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजीद देवी के नाम से जाना जाता है.

ज्वालामुखी मंदिर का इतिहास काफी पुराना है. ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान को पहली बार एक गाय पालक ने देखा था. वह अपनी गाय का पीछा करते समय यहां तक पहुंचा. उसके पीछे का यह कारण था कि उसकी गाय दूध नहीं दे रही थी. गाय अपना सारा दूध पवित्र ज्वालामुखी नामक स्थान में एक दिव्य कन्या को पिला देती थी. उसने यह दृश्य अपनी आंखो से देखा और वह यह सब वहां के राजा को बताया. राजा ने सत्य जानने लिए अपने सिपाहियों को वहां भेजा. उन्होंने भी यह चमत्कार देखा और सिपाहियों ने पूरी बात राजा को बताई. राजा ने सत्य जानने के बाद वहां पर मंदिर का निर्माण कराया.

ज्वालामुखी मंदिर में सालों से ज्योति जलती आ रही है. यह 51 शक्ति पीठों में से एक है. यहां माता शती की जीभ गिरी थी. ज्वाला जी का मात्र एक बार दर्शन करने से ही मनुष्य के सारे कष्ट दुर हो जाते हैं. अकबर भी माता की शक्ति को मान चुका था. उसके बार–बार माता की ज्योति को बुझाने की कोशिश के बावजूद माता की ज्योति आज भी प्रज्ज्वलित है.

दर्शनीय स्थल

ज्वाला मुखी मंदिर के आस–पास भी बहुत से दर्शनीय मंदिर और स्थल हैं. अकबर नहर, गोरखनाथ मंदिर, ज्वाला मंदिर से 4.5 किमी के दूरी पर नगिनी माता का मंदिर है और 5 किमी की दूरी पर रघुनाथ जी का मंदिर है. ज्वाला मंदिर से 30 किमी की दुरी पर स्थित ब्रजेश्वरी देवी मंदिर है. यदि आप ज्वालामुखी मंदिर जाते हैं, तो यहां आकर दर्शन करना न भूलें.

अकबर नहर

मंदिर में प्रवेश द्वार के बाईं तरफ अकबर नहर है. अकबर ने माता के मंदिर में प्रज्ज्वलित ज्योति को बार–बार बुझाने की कोशिश किया, लेकिन माता की ज्योति बुझा नहीं पाया. तब एक बार अकबर ने माता की ज्योति को बुझाने के लिए वहां नहर का निर्माण कराया, लेकिन फिर भी माता की ज्योति नहीं बुझी. ऐसा माना जाता है कि ज्वाला जी कि ज्योति सालों से जलते आ रही है. यह माता की शक्ति का ही प्रभाव है कि ज्योति आज तक वैसे ही प्रज्ज्वलित है. उसके आगे मंदिर का गर्भ द्वार है, जिसके अन्दर माता ज्योति के रूप में विराजमान हैं.

गोरखनाथ मंदिर

ज्वालामुखी मंदिर के थोड़ा ऊपर जाने पर गोरखनाथ का मंदिर है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से भी जाना जाता है. मान्यता है कि बाबा गोरखनाथ इसी स्थान पर माता की तपस्या किया करते थे. यहां पर पानी का एक कुंड है, जो देखने में खौलता हुआ लगता है, लेकिन वास्तव पानी गरम नहीं है. यहां पर आने से लोगों की सारी मन्नतें पूरी होती हैं. यहां देश–विदेश से लोग आते हैं.

बृजेश्वरी देवी मंदिर

बृजेश्वरी देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में एक है. इस मंदिर में माता तीन पिंडियों के रूप में विराजमान हैं. यह मंदिर इस क्षेत्र का लोकप्रिय मंदिर है. यहां पर माता सती का स्तन गिरा था. इस मंदिर और शहर को बहुत बार विदेशियों और महमूद गजनवी ने 1009 ई. में को लूटा और मंदर को नष्ट कर दिया था. यहां दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं. यहां देश और विदेश से पूरे वर्ष लोग आते रहते हैं. नवरात्रों में यहां काफी भीड़ होती और मेला लगता है.

प्रमुख त्योहार

ज्वाला जी में नवरात्रि में बहुत विशाल मेले का आयोजन होता है. वर्ष के दोनों नवरात्र यहां बहुत धुम–धाम से मनाए जाते हैं. नवरात्रि में यहां भक्तों की संख्या दो–गुनी हो जाती है. नवरात्रि में यहां विशेष पूजा–अर्चना की जाती है और अखंड देवी पाठ रखे जाते हैं. साथ ही मंत्रोच्चारण के साथ हवन किया जाता है. नवरात्रि पर यहां देश–विदेश से भक्त माता की कृपा प्राप्त करने के लिए आते हैं. भक्त देवी को चढ़ाने के लिए लाल रंग का ध्वज भी लेकर आते हैं.

आरती

यहां की आरती मुख्य आकर्षण का केन्द्र है. मंदिर में आरती के समय अद्भुत और मनमोहक दृश्य होता है. एक आरती मंदिर का कपाट खुलने के समय सुर्योदय के वक्त की जाती है. दूसरी आरती दोपहर को होती है और आरती के समय ही माता को भोग भी लगाया जाता है. शाम को संध्या आरती होती है, उसके बाद रात्रि आरती होती है. उसके बाद देवी की शयन–शय्या को तैयार करके, उसे फूलों और सुगंधित सामग्रियों से सजाया जाता है. फिर देवी की शयन आरती की जाती है, जिसमें बहुत संख्या में भक्त शामिल होते हैं. आरती का समय है सुबह 5 बजे, दोपहर की आरती 12.00 बजे, संध्या आरती 7.00 बजे, शयन आरती 10.00 बजे.....

कहां ठहरें

मंदिर के पास कांगड़ा और पालमपुर शहर है, जहां पर बहुत सारे होटल हैं. सस्ते धर्मशालाओं की भी वहां कोई कमी नहीं है. आज चाहें, तो वहां भी रुक सकते हैं.

कैसे जाएं

यहां वायु, रेल और सड़क तीनों मार्ग से जा सकते हैं. अगर आप वायु मार्ग से जाते हैं, तो ज्वाला जी से 46 किमी की गगल हवाई अड्डा स्थित है. यहां कार और बस दोनों माध्यमों से आप जा सकते हैं. अगर आप रेल द्वारा जाते हैं, तो किसी भी शहर से पहले पठानकोट पहुंचें. वहां से स्पेशल ट्रेन से पालमपुर जा सकते हैं. सड़क मार्ग से जाने के लिए दिल्ली, शिमला, पठानकोट से आप यहां आ सकते सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

बढ़ई का लोभ

किसी गांव में एक आदमी बढ़ई का काम करता था. उसकी कमाई से उसकी पत्नी और बच्चे संतुष्ट रहते थे, पर स्वयं बढ़ई के मन में असंतोष रहता था. वह स्वयं से कहता रहता था कि मैं बहुत गरीब हूं और अपने परिवार को खुश नहीं रख पाता. अगर मेरे पास कुछ सोना आ जाए, तो मैं और मेरा परिवार बहुत सुख से रहेंगे. एक दिन वह बाज़ार से गुज़र रहा था. एक सुनार की दुकान पर उसने बिक्री के लिए रखे गए सोने के जेवर देखे. वह उन्हें बड़ी लालसा से देखता रहा और अचानक ही उसने एक जेवर उठा लिया और उसे ले भागा. दुकानदार यह देखकर चिल्लाया और आस–पास खड़े लोग बढ़ई के पीछे भागने लगे. शोर सुनकर कुछ सिपाही भी वहां आ पहुंचे और सभी ने बढ़ई को घेर कर पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया. जब उससे पूछ–ताछ हुई, तो बढ़ई बोला–उस समय मुझे सोने के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. इस पूरे मामले को एक दूसरा व्यक्ति संजय देख रहा था. संजय सुनार के पास गया और उससे बोला–जिस व्यक्ति ने तुम्हारा जेवर चुराया, वह स्वभाव से बुरा आदमी नहीं है. उसके लोभ ने उसे अंधा बना दिया. मैं चाहता हूं कि तुम उसे जेल से मुक्त करवा दो. सुनार इसके लिए सहमत हो गया. बढ़ई को रिहा कर दिया गया. संजय एक महीने तक हर दिन उसके पास जाकर उसे जो मिले, उसी में संतुष्ट रहने का ज्ञान देता था. अब बढ़ई को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा.

शिक्षा : लालच बुरी बला है.

साहित्य

> देह मुक्ति का नारा लगाते–लगाते महिला लेखन कब विरोध की आग में झुलसकर बदसूरत हो गया है, उसका पता न तो लेखिकाओं को चल पाया और न ही स्त्री विमर्श के झंडाबरदारों को. कई लेखिकाओं को लगता है कि गाली–गलौज वाले लेखन से उनको प्रसिद्धि मिल जाएगी. कइयों को मिली भी, लेकिन यह प्रसिद्धि लंबे वक्त तक कायम नहीं रह सकती है.

बीस की कहानी

जिस तरह से आग लगती है, तो वह झुलसाने में कोई भेद-भाव नहीं बरतती, उसी तरह से पुरुष विरोध की आग में हो रहा लेखन किसी को भी बख्शने को तैयार नहीं है. महिला लेखन की इस आग के पीछे स्त्रियों की दशा बदलने की मंशा कम, प्रचार पाने की चाहत ज्यादा है. स्त्री-विमर्श के कोलाहल के बीच कई लेखिकाएं ऐसी भी हैं, जो इन दंद-फंद से दूर रहकर गंभीर लेखन कर रही हैं और नये-नये विषयों को छूने का साहस जुटाकर साहित्य को समृद्ध करने में लगी हैं.

अनंत विजय

समकालीन साहित्यिक परिदृश्य में स्त्री–विमर्श के नाम पर लेखिकाओं की एक ऐसी फौज खड़ी हो गई है, जो प्रसिद्धि के लिए तमाम तरह के दंद–फंद से भी नहीं हिचक रही है. उन्हें हर कीमत पर सिर्फ और सिर्फ प्रसिद्धि चाहिए और वह भी इंस्टेंट. पुरुष मानसिकता, पितृसत्तात्मक समाज, महिलाओं के हालात, उनके हर तरह के शोषण, पुरुषों से आजादी, बंधनों से मुक्ति, सेक्स संबंधों की स्वतंत्रता, शादी नाम की संस्था से बगावत आदि–आदि ऐसे कई जुमले हैं, जो समकालीन क्रांतिकारी महिला लेखन में आग के गोले की तरह से धधकते हैं. लेखन ऐसा कि पढ़ने वाला झुलस जाए और अगर बच गया, तो आग की तपिश लंबे समय तक महसूस करता हुआ घूमता रहेगा. महिला लेखन की इस आग की लालसा समाज के सारे पुरुषों को जलाकर राख कर देने की है. जिस तरह से आग अगर लगती है, तो वह किसी को नहीं छोड़ती या कह सकते हैं कि वह झुलसाने में कोई भेद–भाव नहीं बरतती, उसी तरह से पुरुष विरोध की आग में हो रहा लेखन किसी को भी बख्शने को तैयार नहीं है. महिला लेखन की इस आग के पीछे बहुधा समाज में स्त्रियों की दशा बदलने की मंशा कम, प्रचार पाने की चाहत ज्यादा है. उनको लगता है कि सेक्स प्रसंगों के बारे में खुलकर बात करने, उससे आजादी की बात करने से देश में क्रांति हो जाएगी, महिलाओं को आजादी मिल जाएगी, उनका हर तरह का शोषण खत्म हो जाएगा. देह मुक्ति का नारा लगाते–लगाते महिला लेखन कब विरोध की आग में झुलस कर बदसूरत हो गया है, उसका पता न तो लेखिकाओं को चल पाया और न ही स्त्री–विमर्श के झंडाबरदारों को. कई लेखिकाओं को लगता है कि गाली–गलौज वाले लेखन से उनको प्रसिद्धि मिल जाएगी. कइयों को मिली भी, लेकिन यह प्रसिद्धि लंबे वक्त तक कायम नहीं रह सकती है. यह तथ्य है कि भारतीय समाज प्राचीन काल से ही पुरुषों के पक्ष में झुका रहा है. इससे किसी को भी इन्कार नहीं है. महिलाओं पर बहुत अत्याचार हुए. उनका दैहिक और मानसिक दोनों तरह का शोषण किया गया और कई जगहों पर अब भी यह बदस्तूर जारी है, लेकिन यह भी तथ्य है कि पिछले कई दशकों में हालात बहुत बदले हैं. हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आने लगीं. पुरुषों ने भी महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर जतन किए. इसलिए एक ही लाठी से सबको हांकने की महिला लेखन की प्रवृत्ति बेहद खतरनाक है और वह उसको किसी मुकाम तक ले जा पाएगी, इसमें मुझे संदेह है.

मैं हमेशा से यह बात कहता रहा हूं कि कुछ स्त्रीवादी लेखिकाएं हाथ में एके–47 लेकर घूम रही हैं और वे अपने लेखन रूपी अस्त्र से सबको ध्वस्त करने की ख्वाहिश भी पाले बैठी हैं, लेकिन सपने बहुधा सच नहीं होते और खासकर तब तो बिल्कुल भी नहीं, जबकि सपनों के पीछे की मंशा संदेह के घेरे में हो या फिर मंशा लक्ष्य हासिल करना न हो, बल्कि खुद को आगे बढ़ाने की हो. स्त्री–विमर्श के कोलाहल के बीच कई लेखिकाएं ऐसी भी हैं, जो इन दंद–फंद से दूर रहकर गंभीर लेखन कर रही हैं, नये–नये विषयों को छूने का

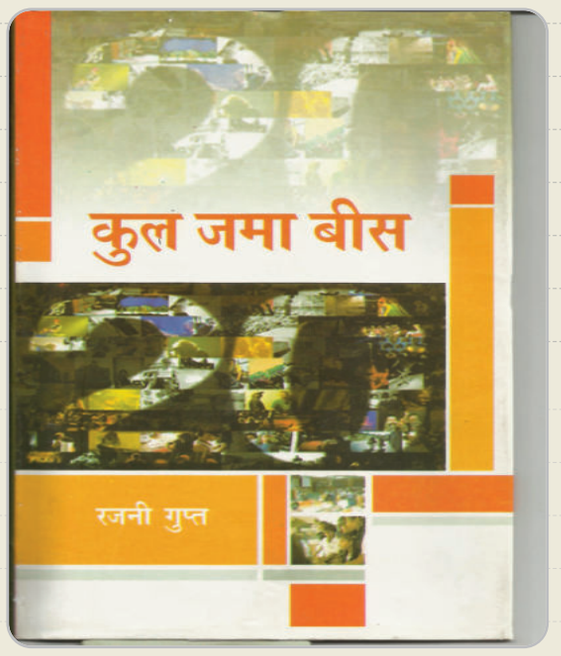

साहस जुटा कर साहित्य को समृद्ध करने में लगी हैं. देह मुक्ति के छद्म आंदोलन से अलग रहकर, बगैर प्रसिद्धि की चाहत में गंभीर रचनाकर्म में लगी हैं. इस बात का खतरा उठाते हुए भी कि महिला लेखन की महंथाइनें उन्हें हाशिये पर डालने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी. समकालीन साहित्यक परिदृश्य में रजनी गुप्त एक ऐसी ही लेखिका हैं. रजनी गुप्त के तीन उपन्यास–कहीं कुछ और, किशोरी का आसमां और एक न एक दिन प्रकाशित हो चुके हैं. इन उपन्यासों ने अपने विषय से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था. उनकी कहानियां भी लागातर प्रकाशित होकर पाठकों को सोचने पर विवश करती रही हैं. उसके अलावा स्त्री विमर्श पर आधारित दो पुस्तकों–आजाद औरत, कितनी आजाद और मुस्कुराती औरतों का भी वे संपादन कर चुकी हैं. अभी–अभी उनका नया उपन्यास–कुल जमा बीस–प्रकाशित हुआ है. इस उपन्यास के केंद्र में यौवन की दहलीज पर कदम रख रहा ऐसा किशोर है, जो अपने करियर को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है. क्या करे कि न करे की मानसिकता से ग्रस्त है. उसका बचपन डिस्टर्बड रहा है. उसने पिता की मौत के बाद अपनी मां को पर पुरुष की बाहों में देखा है. यह दृश्य उसे बार–बार हॉन्ट करता है. दादी के साथ रहता है. साथियों के साथ मौज–मस्ती करता है. दादी उसकी मानसिकता को समझ कर उसकी हर छोटी–बड़ी जायज–नाजायज मांग पूरी करती है. दरअसल, इस उपन्यास के पात्र के बहाने रजनी गुप्त ने आज की इंटरनेट पीढ़ी की पूरी मानसिकता को सामने लाने की कोशिश की है. ऐसी पीढ़ी की मानसिकता, जिसके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, वर्जनाओं की उन्हें परवाह नहीं, कपड़ों की तरह साथी भी बदलने में उन्हें कोई हिचक नहीं. सबकुछ इंस्टेंट चाहिए–दोस्ती से लेकर शारीरिक संबंध तक. प्यार–व्यार क्या होता है, यह वे जानते नहीं और उसके चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहते. उनके लिए दैहिक रिश्ते सिर्फ अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने भर का जरिया मात्र हैं. चाहे वह लड़की हो या लड़का, समाज, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सभी को वह इसी मानक पर तौलता है और उसी हिसाब से अपनी जिंदगी के बारे में फैसले लेता है. अपने फैसलों में उसको किसी का दखल भी मंजूर नहीं होता है, लेकिन तन्हाई के क्षणों में वह मां के बिछोह में तड़पता भी है और तब उसको अपने दिवंगत पापा की याद भी आती है. पापा की याद में तड़पता किशोर अपने किसी साथी में सुकून भी तलाशता है. यहीं से चाहत होती है, किसी कंधे की, जो उसे कहीं और ले जाता है.

रजनी गुप्त के इस उपन्यास की भाषा उसके पात्रों के हिसाब से गढ़ी गई है. उसमें लेखिका पर्याप्त रूप से सफल भी रही हैं. हिंदी–अंग्रेजी की मिली–जुली जिस तरह की बोली–वाणी यह पीढ़ी अपने उपयोग में लाती है, वही भाषा रजनी ने अपनाई है. इसमें लेखिका बहुत हद तक कामयाब भी रही हैं. उस उपन्यास में मुझे कई जगह एक हिचक दिखाई देती है. जैसे जब भी कोई सेक्स प्रसंग आता है, तो लेखिका नैतिकता और यथार्थ के द्वंद्व भी फंसी नजर आती है. जैसे, जब आशु अपनी मां को उसके साथी के साथ देखता है, तो लेखिका की हिचक वहां दिखाई देती है और लगता है कि वह जल्द इस प्रसंग को खत्म कर आगे बढ़ जाना चाहती हैं. इस तरह के प्रसंग जब भी जहां आते हैं, वहां यह हिचक यह साफ तौर पर परिलक्षित होती है. कुल मिलाकर रजनी गुप्त ने एक ऐसे विषय को चुना है, जिस पर हिंदी लेखकों का ध्यान कम जा रहा है. वह तो यथार्थ की जमीन तोड़ने में लगे हैं. जमाने की रफ्तार के साथ रजनी ने विषय को पकड़ा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि पाठकों को रजनी गुप्त का यह उपन्यास काफी पसंद आएगा. एक बात और कहना चाहूंगा कि रजनी ने जिस तरह से उपन्यास की भाषा को नई पीढ़ी के हिसाब से रखा है, वही सतर्कता उनको उपन्यास के शीर्षक में भी बरतनी चाहिए थी. ऐसा करने से युवा पीढ़ी को बेहतर तरीके से उपन्यास की ओर आकृष्ट किया जा सकता था. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं.)

anant.ibn@gmail.com

कविता

कविता

मैं हर जगह था वैसा ही

अशोक कुमार पाण्डेय

मैं बंबई में था
तलवारों और लाठियों से बचता-बचाता
भागता-चीखता
जानवरों की तरह पिटा और उन्हीं की तरह ट्रेन के
डब्बों में लदा-फंदा
सन साठ में मद्रासी था, नब्बे में मुसलमान
और उसके बाद से बिहारी हुआ

मैं कश्मीर में था
कोड़ों के निशान लिए अपनी पीठ पर
बेघर, बेआसरा, मज़बूर, मज़लूम
सन तीस में मुसलमान था
नब्बे में हिंदू हुआ

मैं दिल्ली में था
भालों से गुदा, आग में भुना, अपने ही लहू से
धोता हुआ अपना चेहरा
सैंतालीस में मुसलमान था
चौरासी में सिख हुआ

मैं भागलपुर में था
मैं बड़ौदा में था
मैं नरोदा पाटिया में था
मैं फिलिस्तीन में था, अब तक हूं वहीं
अपनी कब्र में सांसें गिनता
मैं ग्वाटेमाला में हूं
मैं ईराक में हूं
पाकिस्तान पहुंचा, तो हिंदू हुआ

जगहें बदलती हैं
वजूहात बदल जाते हैं
और मज़हब भी, मैं वही का वही!

किताब मिली

पुस्तक	लेखक
भीगा हुआ सच	अर्चना राजहंस मधुकर
प्रकाशक	**मूल्य**
कश्यप पब्लिकेशन	150 रुपए

यह कविता संग्रह काफी रुचिकर है. अन्य कविता संग्रह से हट कर इस संग्रह में कहीं भी एकरसता देखने को नहीं मिलती. इसलिए इस पुस्तक की कविताओं को विशुद्ध कविता की कोटि में रखा जा सकता है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई–मेल: feedback@chauthiduniya.com

बहस-तलब

वैसी चीखती कविता बनाने में लजाता हूं...

अवधेश त्रिपाठी

हिंदी कविता के पिछले 25 वर्ष के बारे में चर्चा के कार्यक्रम में इंडिया हैबिटेट सेंटर में शरीक होना, कविता के बारे में कई तरह की चिंताओं से अवगत होने जैसा था. पिछले 25 सालों में बदली हुई परिस्थितियों में कविता में आई तब्दीलियों और इसके साथ ही कविता की भूमिका में आई तब्दीलियों के बारे में चर्चा हुई. लगभग सारे वक्ताओं ने माना कि इन वर्षों में महान कविता नहीं लिखी गई है. कुछ ने और आगे बढ़कर कहा कि कविता को विचारधारा का जो आश्रय प्राप्त था, वह समाप्त हुआ, तो उसमें जीवन ज्यादा आ सका. स्त्री और दलितों के साहित्य में हस्तक्षेप पर बातें हुईं, नक्सलबाड़ी आंदोलन और हिंदी साहित्य पर उसके प्रभाव की बातें हुईं, देश में सांप्रदायिक उभार की बातें भी हुईं, लेकिन सब कुछ इतना थका हुआ सा था कि हिंदी कविता से ज्यादा आलोचना का संकट दिखाई पड़ रहा था. सत्र के संयोजक आशुतोष कुमार बार–बार बातों को पटरी पर लाने की कोशिश करते रहे और बातें (लीक छोड़ि तीनों चलें शायर, सिंह, सपूत) वाले अंदाज में बहकती रहीं.

केदार नाथ सिंह ने जब कहा कि उत्तर–पूर्व में अच्छी कविता लिखी जा रही है, तो भी वे उस कविता के स्रोत की ओर इशारा करने से चूक गए, जो उत्तर–पूर्व भारत की सेनाओं के युद्ध का सतत् सामना कर रहा है, वहां से कविता नहीं पैदा होगी, तो कहां से होगी. दरअसल, आलोचना का इतना ही संकट नहीं है कि उसके पास कविता के विश्लेषण के औजार नहीं हैं, उससे भी अधिक ईमानदार प्रयासों का अभाव है. जब आलोचना पीआर बन जाती है, जब आलोचना वाक्चातुर्य बन जाती है, तब गुरु गंभीर मुद्रा में अर्थहीन और हजार बार दोहराई जा चुकी बातों को कुछ यूं पेश किया जाता है, मानों वे अत्यंत नवीन, मौलिक और सुविचारित हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वे कितनी हास्यास्पद होती हैं, इसका अंदाजा इन मौलिक विचारकों को नहीं होता. साठ के दशक की कविता को बीती आधी शताब्दी हो चुकी, लेकिन पिछले 25 वर्षों की कविता के बारे में बात करते हुए राजेश जोशी ने अकवितावाद की अराजकता और साठोत्तरी कविता की भूमिका को कुछ इस अंदाज में पेश किया कि वे पहली बार कही जा रही हों.

एक विद्वान आलोचक ने यह सूत्रीकरण किया कि पहले की कविता को विचारधारा का आश्रय प्राप्त था, लेकिन उसमें जीवन का अभाव

> **दरअसल, आलोचना का इतना ही संकट नहीं है कि उसके पास कविता के विश्लेषण के औजार नहीं हैं, उससे भी अधिक ईमानदार प्रयासों का अभाव है. जब आलोचना पीआर बन जाती है, जब आलोचना वाक्चातुर्य बन जाती है, तब गुरु गंभीर मुद्रा में अर्थहीन और हजार बार दोहराई जा चुकी बातों को कुछ यूं पेश किया जाता है, मानो वे अत्यंत नवीन, मौलिक और सुविचारित हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वे कितनी हास्यास्पद होती हैं, इसका अंदाजा इन मौलिक विचारकों को नहीं होता.**

था, बाद की कविता ने राजनीतिक रूप से गलत होने का जोखिम उठाया है, जिससे उसमें जीवन अधिक आया है. यह सूत्रीकरण निर्मल वर्मा आदि के पुराने विचारों का पिष्टपेषण मात्र है, जो अपने लिए नये शब्द भी नहीं ढूंढ़ पाया. विचारधारा के अभाव की बात करने वालों की एक मजबूत विचारधारा हमेशा रही है और जब राजनीतिक रूप से गलत होने का जोखिम उठाने की बात कही जाती है, तो राजनीति को जीवन से अलग और न बदलने वाली कोई पत्थर की लकीर मान लिया जाता है. यह एक भ्रामक धारणा है. कविता में विचारधारा का जितना अभाव होगा, उसमें उतना ही जीवन आ सकेगा–का सिद्धांत किन तथ्यों के आधार पर खड़ा किया गया, यह हम जैसे साहित्य के सामान्य पाठकों के लिए रहस्य ही है.

हिंदी कविता के 25 वर्षों पर चर्चा में कविता के पश्चिम से मुक्त होकर अधिक भारतीय होने को रेखांकित किया गया. फिर राष्ट्र और राष्ट्र पर दावेदारी, राष्ट्र में भागीदारी आदि के बारे में भी चर्चा हुई, लेकिन क्या यह कोई अजूबी घटना है? क्या आजादी के पहले से ही राष्ट्र के निर्माण और उसमें भागीदारी को लेकर बहस नहीं चल रही थी? क्या निराला आजादी के पहले ही नहीं लिख रहे थे कि खुला भेद विजयी कहाए हुए जो/लहू दूसरों का पिये जा रहे हैं? प्रगतिशीलों की पूरी जमात क्या देश में मौजूद विभिन्न राष्ट्रों के बीच के संघर्षों और द्वंद्वों को दर्ज नहीं कर रही थी? इसमें जो नया घटित हुआ है, वह यह कि दलितों और स्त्रियों ने कविता में भी अपने राष्ट्र की दावेदारी पेश की है. सवाल तब और भी पेचीदा हो जाता है, जब इन अस्मिताओं के भीतर राष्ट्र के बारे में परस्पर विरोधी रुख दिखाई पड़ते हैं. मृत्युंजय ने इस प्रश्न की जटिलता की ओर संकेत किया और 90 के दशक में सांप्रदायिकता के उभार और हिंदी कविता की उस पर प्रतिक्रिया के बारे में बात की. यह सांप्रदायिकता पुराने किस्म के हिंदू–मुसलिम दंगों से अलहदा थी. पूंजीवाद के नये दौर में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा एक तरफ अमेरिका के आगे घुटने टेक रही थी, तो दूसरी ओर राष्ट्र और धर्म के नाम पर जनसंहार कर रही थी. इस पूरे दौर की कविता को जनता के प्रतिरोध और सत्ता द्वारा उसके दमन की कविता के रूप में देखना कहीं अधिक सार्थक और समझ में आने वाला प्रस्ताव लगता है. बहरहाल, ऐसे आयोजनों की सबसे बड़ी सार्थकता यह है कि ये हिंदी की आलोचना की मौजूदा स्थिति से हमें अवगत कराते हैं, हमें आईना दिखाते हैं. ■

वैगन-आर स्टिंग्रे का फ्रंट पार्ट स्लिम और काफी चमकीला है. लार्ज एयर डैम और फॉग लैंप को री-डिजाइन किया गया है. हेडलाइट आधुनिक तकनीक से युक्त है. गाड़ी का पिछला पार्ट स्पोर्टी है. पीछे से देखने पर यह एक बड़ी खूबसूरत मछली की तरह लगती है.

सस्ते में स्मार्ट का जमाना

मोबाइल कंपनियों में आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण कम से कम दाम में ज्यादा खूबियों वाला मोबाइल फोन देने की होड़ मची है. इसका फायदा उपभोक्ता को हो रहा है. हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे मोबाइल फोन्स के बारे में, जो ज्यादा महंगे तो नहीं हैं, लेकिन इनके फीचर्स किसी महंगे मोबाइल फोन से कम भी नहीं हैं. आइए जानते हैं, वे कौन से फोन हैं...

माइक्रोमैक्स कैनवस 4 फीचर्स

- वेट- 158.00 ग्राम
- बैटरी-2000एमएएच
- स्क्रीन साइज- 5.00 इंच
- रिजोल्यूशन- 720-1280 पिक्सल
- कलर- ग्रे एंड व्हाइट
- प्रोसेसर-1.2 जीएचजेड ड्यूअल कोर
- रैम-1 जीबी
- इंटरनल स्टोरेज-16 जीबी
- रियर कैमरा-13 मेगापिक्सल
- फ्रंट कैमरा-5 मेगापिक्सल
- ऑपरेटिंग सिस्टम-एंड्रॉयड 4.2.1
- कीमत-17000 रुपये

माइक्रोमैक्स कैनवस 4

इस फोन की खास बात यह है कि इस पर ग्लव्स पहनकर भी काम किया जा सकता है. इसमें ब्लो-टु-अनलॉक फीचर भी है, जिससे इसे एक फूंक मारकर अनलॉक किया जा सकता है. बर्स्ट मोड में केवल एक क्लिक से कैमरा 15 सेकेंड में 99 फोटो खींच सकता है. इसमें वीडियो पिंड फीचर है, जिससे इस फोन पर वीडियो देखते हुए मैसेज या ईमेल किया जा सकता है. एक वीडियो देखते हुए दूसरे वीडियो का प्रिव्यू देखा जा सकता है. स्क्रीन पर स्वाइप करके वॉल्यूम घटाया-बढ़ाया भी जा सकता है. वीडियो देखते हुए अगर कोई मोबाइल को छोड़कर किसी और तरफ देखने लगेगा, तो वीडियो वहीं रुक जाएगा. 720 पिक्सल रिजोल्यूशन वाली 5 इंच की ट्रू-एचडी आईपीएस स्क्रीन है, लेकिन यह फुल एचडी नहीं है. डिस्प्ले में 293 पीपीआई (पिक्सल पर इंच) पिक्सल डेंसिटी है. यह फोन 2 रंगों- काले और सफेद में उपलब्ध है. इसमें एलईडी फ्लैश के साथ पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल और आगे की तरफ़ 5 मेगापिक्सल कैमरा है. साथ ही इसमें 1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जा सकता है. 16 जीबी इन-बिल्ट स्टोरेज और 32 जीबी तक मेमरी कार्ड लगाया जा सकता है. इसकी बैटरी 2000 एमएच की है. 220 घंटे का स्टैंड बाई टाइम और 8 घंटे का टॉक टाइम है. ■

माइक्रोमैक्स ए 240

इसका स्क्रीन 5.7 इंच का है. इसमें 12 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा लिड लाइट के साथ लगा हुआ है. इसके शानदार फीसर्च को देखते हुए कहा जा रहा है कि यह सैमसंग गैलेक्सी मेगा को कड़ी टक्कर देगा. इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, ड्युल सिम के साथ 1 जीबी की रैम और 16 जीबी इंटरनल मेमोरी दी गई है. इसके अलावा, बेहतर बैटरी बैकअप के लिए इसमें 2,600 एमएएच बैटरी इनबिल्डो है. वीडियो पिनिंग, होम स्क्रीन सपोर्ट फ्लिप म्यूट और स्मार्ट पॉज जैसे सॉफ्टवेयर भी इसमें दिए गए हैं. माइक्रोमैक्स न सिर्फ फीचर्स के मामले में सैमसंग मेगा को टक्कर देगा, बल्कि कम कीमत भी इसकी खासियत होगी. जीहां ढेर सारी खुबियों के साथ इसकी कीमत मात्र 18,000 रुपए है, जो सैमसंग गैलेक्सी मेगा 5.8 के मुकाबले काफी कम है. ■

एलजी ऑप्टीमस एल 1

एलजी ने ऑप्टीमस सीरीज के तहत नया एल 1 स्मार्टफोन लांच किया है. एलजी का यह स्मार्टफोन बजट स्मार्टफोन्स की रेंज में बड़े हैंडसेट्स को कड़ी टक्कर दे सकता है. इसमें 3 इंच की क्यू वीजिए स्क्रीन दी गई है जो 240 -320 रिजोल्यूशन को सपोर्ट करती है. देखने में यह भले ही छोटा लगे, लेकिन इसमें 1 गीगाहर्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 512 एमबी की रैम दी गई है. वहीं 4 जीबी की इंटरनल मैमोरी को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 32 जीबी तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं. फोन में 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है और फ्रंट कैमरा वीजिए है. कनेक्टीविटी फीचर्स के तहत इसमें 3जी नेटवर्क सपोर्ट के साथ ऐज, ब्लूटूथ, वाईफाई, माइक्रोयूएसबी और जीपीएस की सुविधा भी दी गई है. सिंगल सिम द्वारा एक ही नेटवर्क इसमें प्रयोग किया जा सकता है. अच्छी बैटरी बैकअप के लिए इसमें 1540 एमएएच बैटरी लगी हुई है. इस फोन से पहले एलजी जी 2 मात्र एक ऐसा मोबाइल फोन था, जिसमें 5.2 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है. ■

एलजी ऑप्टीमस एल 1 फीचर्स

- 3 इंच क्यूवीजी डिस्प्ले
- एंन्ड्रॉएड 4.1.2 जेलीबीन
- 1 जीएचजेड क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर
- 4 जीबी इंटरनल मेमोरी
- 2 मेगापिक्सल रियर कैमरा, वीजीए फ्रंट कैमरा
- 512 एमबीआर एम2
- 4 जीबी इंटरनल स्टोरेज
- 1540 एमएच बैटरी
- कीमत- 5999 रुपये

कार्बन ए आई

कार्बन का यह स्मार्टफोन ड्यूअल सिम सपोर्ट करता है. इसका डिस्प्ले 3.5 इंच का है. यह 2.3 जिंजरब्रेड ओएस पर काम करता है. इसमें 1 गीगाहर्ट प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है. इसकी मेमोरी को 32 जीबी तक एक्सपेंड किया जा सकता है. सबसे बढ़िया फीचर इसमें ड्यूअल कैमरा सपोर्ट है. इसका फ्रंट कैमरा वीजीए और रियर कैमरा 3 मेगा पिक्सल का है. कनेक्टिविटी के मामले में यह फोन 3जी और वाईफाई सपोर्ट करता है. इसकी बैटरी 1100 एमएएच की है, जो 4.5 घंटे का टॉक टाइम देती है. इस फोन की कीमत है 3660 रुपये. ■

लावा आइरिस 351

यह फोन ड्यूअल सिम वाला है. 1 गीगाहर्ट प्रोसेसर वाला यह फोन पूरी तरह से टचस्क्रीन है. इसका डिस्प्ले 3.5 इंच और रेजोल्यूशन 320- 480 पिक्सल का है. यह 2.3.5 जिंजर ब्रेड एंड्रॉयड पर चलता है. इसका कैमरा 2 मेगा पिक्सल का है. इस स्मार्टफोन की इंटरनल मेमोरी मात्र 110 एमबी है, लेकिन इसे माइक्रो कार्ड के जरिए 16 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. इसमें रेडियो और रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स हैं. इस फोन की कीमत है 3899 रुपये. ■

इंको मिरर ए3

यह फोन 2.3 एंड्रॉयड ओएस पर काम करता है. ड्यूअल सिम वाले इस फोन की मेमोरी को 16 जीबी तक एक्सपेंड किया जा सकता है. इसका कैमरा 2 मेगा पिक्सल का है. यह वाई-फाई, ब्लूटूथ और जीपीआरएस के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है. इसमें नोकिया 5 एफ 1000 एमएएच बैटरी का इस्तेमाल किया गया है. इसके साथ ही एमपी 4, एमपी 3 और एफएम रेडियो जैसे फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं. कंपनी ने इसकी कीमत 2499 रुपये रखी है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नए स्पोर्टी लुक में वैगन-आर स्टिंग्रे

मारुति सुजुकी इंडिया ने हैचबैक सेगमेंट में वैगन-आर स्टिंग्रे लॉन्च किया है. वैगन-आर स्टिंग्रे को तीन अलग-अलग वेरियंट्स एलएक्सआई, वीएक्सआई, वीएक्सआई (जे) में लॉन्च किया गया है. इनकी कीमत क्रमशः 4.10 लाख, 4.38 लाख और 4.67 लाख रुपए रखी गई है. कार का इंजन 1000 सीसी का है. कंपनी का दावा है कि वैगन-आर स्टिंग्रे 20.51 किलोमीटर प्रति घंटे की माइलेज देगी. इस कार का फ्रंट पार्ट स्लिम और काफी चमकीला है. इसके साथ ही लार्ज एयर डैम और फॉग लैंप को री-डिजाइन किया गया है. हेडलाइट आधुनिक तकनीक से युक्त है. गाड़ी का पिछला पार्ट स्पोर्टी है. पीछे से देखने पर वैगन-आर स्टिंग्रे एक बड़ी और खूबसूरत मछली की तरह लगती है. वैगन-आर मारुति सुजुकी की सबसे सफल सीरीज रही है. इंडियन मार्केट में वैगन-आर मिडल क्लास के बीच खास पहचान बनाने में कामयाब रही है. इसी के मद्देनजर कंपनी ने वैगन-आर की सारी खूबियों को समटते हुए नए रूप में वैगन-आर स्टिंग्रे पेश करने की कोशिश की है. वैगन-आर स्टिंग्रे में और कई तरह के फीचर शामिल किए गए हैं. वैगन-आर स्टिंग्रे लॉन्च कर कंपनी इस सीरीज को हर हाल में लोगों के बीच कायम रखना चाहती है. वैगन-आर कुछ साल पहले तक देश में दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी, लेकिन फाइनांशियल इयर 2013 में यह चौथे नंबर पर आ गई. इस सीरीज की बिक्री में आई कमी से मारुति सुजुकी का बिजनेस बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. मारुति को देश में ह्युंदै, रेनॉ और फोर्ड से कड़ी चुनौती मिल रही है. मारुति की प्रतिद्वंद्वी कंपनी ह्युंदै 15.25 पर्सेंट मार्केट शेयर बढ़ाने में लगी हुई है. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

क्रिकेट की सुर्ख़ियों में पहली बार शिखर धवन का नाम 2003–04 में बांग्लादेश में खेले गए अंडर–19 विश्व कप के दौरान आया था. उस विश्व कप में शिखर ने धुआंधार तीन शतकीय पारियों की मदद से 505 रन बनाए थे और अंत में मैन ऑफ द सीरीज चुने गए थे.

शिखर धवन

देर आए दुरुस्त आए

आज कल भारतीय और विश्व क्रिकेट जगत में शिखर धवन उर्फ गब्बर की धूम मची हुई है. दिल्ली के इस बाएं हाथ के खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसी धमाकेदार वापसी की है, जिसका जवाब बड़े-बड़े धुरंधरों के पास नहीं है. अंडर-19 क्रिकेट से विश्व क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने वाले शिखर धवन को भारतीय टीम में वापसी करने में भले ही लंबा वक्त लगा हो, लेकिन इस बार उन्होंने टीम में अपनी जगह पक्की करने में ज्यादा वक्त नहीं लिया. टी-20, वन-डे और टेस्ट, तीनों फॉर्मेट में शिखर धवन सफलता के झंडे गाड़ते जा रहे हैं. उनकी सफलता नज़फगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है.

नवीन चौहान

शिखर धवन की सफलता की कहानी एक परिकथा जैसी है. शिखर ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर का आगाज शून्य से किया. जिस क्रिकेटर को टेस्ट कैप पहनने के लिए 9 साल तक इंतजार करना पड़ा हो और वह खिलाड़ी अपने करियर के पहले ही टेस्ट में शतक ठोंक दे और वह भी रिकॉर्ड के साथ, तो ऐसे प्रदर्शन को चमत्कारिक ही कहा जाएगा. सब्र का फल कितना मीठा होता है, यह शिखर से बेहतर कोई और नहीं जानता. शिखर धवन धीरे-धीरे भारतीय क्रिकेट की नई धुरी बनते जा रहे हैं. आए दिन वह अपने बल्ले से ऐसा हल्ला बोलते हैं, जिससे अच्छे-अच्छे धुरंधर अपने दांतो तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं. उन्होंने हालिया धमाका दक्षिण अफ्रीका में ए टीम के सदस्य के रूप में किया है. धवन ने कुछ दिनों पहले भारत की ए टीम की ओर से खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका की ए टीम के खिलाफ एकदिवसीय मैच में 248 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. धवन की यह पारी प्रथम श्रेणी के लिहाज से एक दिवसीय मैचों में किसी भारतीय द्वारा खेली गई सबसे लंबी पारी है. उन्होंने अपनी इस ताबड़तोड़ पारी की बदौलत वीरेंद्र सहवाग और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों को मात दी थी, जिन्होंने एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में क्रमशः 219 और 200 की पारी खेली थी.

क्रिकेट की दुनिया की सुर्खियों में पहली बार शिखर धवन का नाम 2003–04 में बांग्लादेश में खेले गए अंडर–19 विश्व कप के दौरान आया था. उस विश्व कप में शिखर ने तीन धुआंधार शतकीय पारियों की मदद से 505 रन बनाए थे और अंत में मैन ऑफ द सीरीज चुने गए थे. इसके बाद 2004 के रणजी सीजन में उन्हें दिल्ली की टीम में जगह मिली और उन्होंने अपना पहला रणजी मैच खेला. वह दौर सचिन, सौरव और सहवाग का था. उस समय भारतीय टीम में बतौर प्रारंभिक बल्लेबाज जगह बनाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन धवन ने हार नहीं मानी और लगातार घरेलू क्रिकेट खेलते रहे और रन बनाते रहे. देखते-देखते 6 साल गुजर गए. धवन को अक्टूबर 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय मैचों के लिए टीम में जगह दी गई. अपने पहले अंतरराष्ट्रीय मैच में वह अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे. इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उन्हें टीम से बाहर जाना पड़ा. तीन साल बाद जब शिखर को भारतीय टेस्ट टीम में जगह दी गई, तब तक उनके खाते में 81 घरेलू मैचों का अनुभव आ चुका था. जिनमें वह 17 शतक और 24 अर्धशतकों की मदद से पांच हजार से ज्यादा रन बना चुके थे.

वर्ष 2013 में ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे के दौरान भारत के 277 वें खिलाड़ी के तौर पर धवन ने टेस्ट कैप पहनी थी. उन्हें खराब फॉर्म से जूझ रहे वीरेंद्र सहवाग के स्थान पर पारी की शुरुआत करने का मौका मिला था. लंबे समय बाद हाथ आए इस मौके को धवन ने खाली नहीं जाने दिया और सफलता की ऐसी इबारत लिखकर शिखर पर जा बैठे. अपने करियर के पहले ही टेस्ट मैच में शिखर धवन ने 85 गेंदों में धुआंधार शतक जड़ डाला, वह पदार्पण टेस्ट में शतक बनाने वाले 13 वें भारतीय खिलाड़ी बने. पदार्पण मैच में लगाया गया उनका शतक कोई मामूली शतक नहीं था. इस पारी के साथ ही वह पदार्पण टेस्ट मैच में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने थे. 187 रन की पारी खेलने के बाद वह पदार्पण मैच में सबसे लंबी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बने थे. मैदान पर धवन के लिए इस तरह की पारी खेलना कोई नई बात नहीं थी. वह पहले भी इस तरह के कई कारनामे घरेलू क्रिकेट में कर चुके थे. घरेलू क्रिकेट के उन्हीं धमाकों और कारनामों की बदौलत ही उन्हें टेस्ट टीम में जगह मिली थी.

निःसंदेह शिखर को बल्लेबाजी करते देखना एक शानदार अनुभव है. शिखर धवन की बल्लेबाजी शैली वीरेंद्र सहवाग से मिलती-जुलती है. फर्क सिर्फ इतना है कि वह बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और अपना विकेट आसानी से नहीं गंवाते हैं. धवन सीधे बल्ले से खेलते हैं और वह गेंद पर अंधाधुन तरीके से प्रहार नहीं करते हैं. वह जिस सहजता और आक्रामकता से गेंद पर प्रहार करते हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि उनके पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का बरसों का अनुभव है. वह गेंदबाजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं और कमजोर गेंद मिलते ही उसे सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देते हैं. लंबी मूंछे रखने वाले शिखर मैदान में अपनी कड़क मूछों पर ताव देते नज़र आते हैं. यह उनके आत्मविश्वास को दिखाता है. उनका बेहतरीन खेल

ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे के दौरान भारत के 277वें खिलाड़ी के तौर पर धवन ने टेस्ट कैप पहनी थी. उन्हें खराब फॉर्म से जूझ रहे वीरेंद्र सहवाग के स्थान पर पारी की शुरुआत करने का मौका मिला था. लंबे समय बाद हाथ आए इस मौके को धवन ने खाली नहीं जाने दिया और सफलता की ऐसी इबारत लिखकर शिखर पर जा बैठे. अपने करियर के पहले ही टेस्ट मैच में शिखर धवन ने 85 गेंदों में धुआंधार शतक जड़ डाला, वह पदार्पण टेस्ट में शतक बनाने वाले 13 वें भारतीय खिलाड़ी बने.

और बढ़ता आत्मविश्वास वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है. यदि धवन आगे भी ऐसा लाजवाब प्रदर्शन करते रहे, तो सहवाग के लिए टीम में वापसी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा. इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि धवन अपने आक्रामक खेल की बदौलत प्रशंसकों को सहवाग की कमी खलने नहीं दे रहे हैं. उनकी यही आक्रामक शैली लगातार उनके प्रशंसकों की संख्या में इज़ाफा करवा रही है. जून में इंग्लैंड में हुई चैंपियंस ट्रॉफी में शिखर धवन ने 5 मैंचों में 90.75 की औसत से 363 रन बनाए थे. उन्होंने भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की थी. उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज का गोल्डन बैट पुरस्कार मिला था. इसके बाद जिम्बाब्वे दौरे पर भी उनका बेहतरीन फॉर्म जारी रहा. वहां भी उनके बल्ले ने आग उगली और सीरीज में वह सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे. 2013 में खेले 12 एकदिवसीय मैचों में धवन 57.36 की औसत से 631 रन बना चुके हैं, जिनमें तीन शानदार शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. वह इस साल एकदिवसीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में पहले नंबर पर हैं. जिस आक्रामक अंदाज और कंसिसटेंसी के साथ वह घरेलू और विदेशी धरती पर रन बना रहे हैं, उससे तो यह लगता है कि 2015 के विश्व कप में वह टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे और भारतीय टीम के खिताब बचाने के अभियान में मुख्य भूमिका निभाएंगे. यह निश्चित है कि देर से शुरू होने वाला उनका अंतरराष्ट्रीय करियर बहुत बड़ा नहीं होगा, इसलिए धवन अपने छोटे से अंतरराष्ट्रीय करियर को उपलब्धियों से भर लेना चाहेंगे. इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद विश्व कप विजय ही उनका लक्ष्य होगा और इसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहेंगे.

कभी-कभी किसी खिलाड़ी को बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है. कई बार किसी खिलाड़ी को वह सम्मान नहीं मिल पाता है, जिसका वह हकदार है और जिस सम्मान और जगह को पाने के लिए सालों तक उसने दिन-रात मेहनत की है. शायद इसके पीछे सिर्फ एक वजह है उस मंच का न मिल पाना, जहां से वह अपनी प्रतिभा से लोगों को रू-ब-रू करा सके. भारतीय क्रिकेट के नये सितारे शिखर धवन के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि जिन्हें अपने को साबित करने में लगभग एक दशक का वक्त लगा, वह 19 साल से 29 साल के हो गए. अगर चयनकर्ताओं ने उन्हें सही समय में टीम में जगह और मौके दिए होते, तो शायद धवन आज कई रिकॉर्ड्स के शिखर पर बैठे होते, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में तो उनके बारे में कहा जा सकता है कि देर आए, दुरुस्त आए. ■

navinchauhan@chauthiduniya.com

वाडा की जमैका को चेतावनी

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) ने जमैका को चेतावनी दी है कि वह अपने एंटी डोपिंग के कार्यक्रम की खामियों को दूर करे, अन्यथा उसे 2015 में होने वाले ओलंपिक और अन्य प्रमुख प्रतियोगिताओं से बर्खास्त कर दिया जाएगा. जमैका डोपिंग निरोधी आयोग (जेएडीसीओ) के एक पूर्व अधिकारी ने आयोग के काम करने के तरीके में कई खामियों को रेखांकित किया है. अधिकारी के अनुसार, जेएडीसीओ द्वारा डोपिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा जांच कार्यक्रम अनुपयुक्त है. गौरतलब है कि पिछले महीने अमेरिका के धावक टायसन गे के डोपिंग के आरोप में पकड़े जाने के बाद वाडा और ज्यादा मुस्तैदी दिखा रही है. खासकर जमैका जैसे देश में उसकी मुस्तैदी इसलिए जरूरी है, क्योंकि यह विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट का देश है. पिछले कुछ वर्षों से जमैका दौड़ में दुनिया का सिरमौर बना हुआ है.

WORLD ANTI-DOPING AGENCY
play true

बीसीसीआई हुआ मालामाल

दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को कारोबारी साल 2012-13 में 350 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है, जबकि इस दौरान उसकी कुल कमाई 950 करोड़ रुपये रही. पिछले साल (2011-12) में बोर्ड को 382.36 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फायदा हुआ था. बीसीसीआई की कमाई बढ़ने में आईपीएल का प्रमुख योगदान रहा है. आईपीएल से बोर्ड की कमाई 237 करोड़ रुपये हो गई है. आने वाले समय में प्रसारण अधिकार से होने वाली आमदनी में गिरावट आएगी, क्योंकि अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे के बाद लंबे समय तक बीसीसीआई को मैचों की मेजबानी नहीं करनी है.

BOARD OF CONTROL FOR CRICKET IN INDIA

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

आजकल फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स ख़रीदने के लिए भी चैनलों में काफ़ी होड़ रहती है, हालांकि फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स ख़रीदने वाले चैनल्स ज़्यादा तो नहीं हैं, लेकिन उनमें मांग ज़्यादा है. चैनल्स अपनी लाइब्रेरी के लिए ऊंची क़ीमतों पर फिल्मों के अधिकार ख़रीद कर जमा कर लेते हैं.

बॉलीवुड फिल्में

कमाई के लिए सिर्फ़ बॉक्स ऑफिस की मोहताज नहीं

प्रियंका तिवारी

एक समय था जब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाती थीं, तो फिल्मकार को काफ़ी नुक़सान सहना पड़ता था. गुरूदत्त को काग़ज़ के फूल और शो मैन राजकपुर को मेरा नाम जोकर के फ्लॉप के बाद काफ़ी नुक़सान हुआ था, उन्हें इस नुक़सान से उबरने में काफ़ी वक्त लगा. लेकिन पिछले कुछ सालों से न्यू मीडिया ने फिल्मकारों को काफ़ी राहत दी है और उनके लिए कमाई के नए द्वार खोल दिया है. अब की फिल्मों की रिवेन्यू बॉक्स ऑफिस के अलावा अन्य माध्यमों से भी जेनरेट होती हैं. माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में किसी फिल्म का 50 परसेंट रिवेन्यू न्यू मीडिया जैसे इंटरनेट, डीटीएच और मोबाइल फोन्स के ज़रिए जेनरेट होगा.

आजकल फिल्में बॉक्स ऑफिस चले या ना चले, लेकिन फिर भी वह अच्छी ख़ासी कमाई कर ही लेती हैं. पिछले कुछ सालों से 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर लेना किसी फिल्म के लिए कोई बड़ी बात नहीं है. औसतन सभी फिल्में सौ करोड़ का आकड़ा छु ही लेती हैं. इसकी शुरुआत संजय दत्त स्टारर फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से हुई थी. गजनी, रोबोट और थ्री इडियट्स जैसी फिल्मों ने इसे और बढ़ाया. हालांकि वर्ष 2009 तक कुछ फिल्में ही सौ करोड़ का आकड़ा छु पाती थी, लेकिन आजकल सौ करोड़ का आकड़ा पार करने वाली फिल्मों की भरमार है.

दरअसल, अब बॉक्स ऑफिस पर फिल्में लंबे समय तक नहीं चल पातीं. एकाध सप्ताह ही वह थियटरों में दर्शकों का मनोरंजन कर पाती हैं और फिल्मकारों को फिल्म का बजट वसूलने के साथ ही प्रौफिट भी कमाना होता है. ऐसे में प्रोड्यूसर सिर्फ बॉक्स ऑफिस के सहारे नहीं रहता. बॉक्स ऑफिस कमाई का एक बड़ा ज़रिया ज़रूर है, लेकिन फिल्मकार कमाई के अन्य दुसरे तरीक़े भी अपनाने लगे हैं. आज के समय में फिल्में रीलिज से पहले ही अपनी लागत से अधिक कमाई कर लेती हैं. फिल्मों के संगीत, सैटेलाइट राइट, डीवीडी, टिकट बिक्री, इंटरनेट वगैरह माध्यम फिल्म की कमाई का एक बड़ा स्त्रोत बन गए हैं. मोबाइल में बजने वाले रिंगटोंन्स, यूट्यूब पर चलने वाली फिल्म्स और गाने से लेकर रेडियो पर चलने वाले गाने भी पेड होते हैं.

एकता कपूर ने 28 करोड़ रुपये की लागत से डर्टी पिक्चर बनाया. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही और अन्य माध्यमों से भी एकता ने अच्छी ख़ासी कमाई की. इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स भी एकता ने मुहमांगी रक़म में बेची. इसके अलावा, फ्लॉप फिल्मों की बात करें तो वे भी अपनी लागत से कई गुना ज़्यादा कमाई कर लेती हैं. शाहरुख ख़ान की सुपर फ्लॉप रावन, रोहित धवन की देसी ब्वॉयज या फिर आमिर की तलाश, सैटेलाइट अधिकारों के अलावा विदेशी सरकारों से मिलने वाले सब्सिडी ने फ्लॉप के बावजूद फिल्मों को घाटे में नहीं जाने दिया, बल्कि उन्होंने काफ़ी कमाई की. लगभग सभी देश अपने यहां शूटिंग करने के लिए आने वाले फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी देने के लिए तैयार रहते हैं. रावन को ब्रिटेन सरकार से 25 करोड़ की सब्सिडी हासिल हुई, वहीं देसी ब्वॉयज को भी 15 करोड़ रुपये मिले. अन्य देशों की सरकारें भी फिल्मों की शूटिंग अपने देश में करने पर सब्सिडी देती हैं. इसके अलावा, ब्राजिल, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया जैसे कुछ देशों में बॉलीवुड फिल्मों के दर्शक बढ़े हैं, वहां के थियेटरों में हिंदी फिल्में रीलिज हो रही हैं.

आज कल फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स ख़रीदने के लिए भी चैनलों में काफ़ी होड़ होता है, हालांकि फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स ख़रीदने वाले चैनल्स बहुत नहीं हैं, लेकिन उनमें मांग ज़्यादा है. चैनल्स अपनी लाइब्रेरी के लिए ऊंची क़ीमतों पर फिल्मों के अधिकार ख़रीद कर जमा कर लेते हैं. अब तो फिल्म प्रोडक्शन के दौरान ही फिल्मों के सैटेलाइट अधिकार बिक जाते हैं. दिनों दिन बढ़ते चैनल्स के आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण भी सैटेलाइट मार्केट का प्रभाव बढ़ रहा है. फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए भी इनमें आपस में काफ़ी स्पर्धा होती है, इसका फ़ायदा फिल्मकार उठाते हैं और फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स उच्च क़ीमतों पर बेचते हैं. सलमान की फिल्म दबंग 2 ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की और इसके सैटेलाइट राइट्स भी स्टार नेटवर्क ने 50 करोड़ रुपये में ख़रीदे. जहां रावन के सैटेलाइट अधिकार 30 करोड़ से ज़्यादा में बिके थे, वहीं देसी ब्वॉयज के 27 करोड़ में बिके थे. प्रोड्यूसर कुमार मंगत ने 6 करोड़ की लागत से नए कलाकारों को लेकर वेडिंग प्लानिंग पर आधारित फिल्म बिट्टू बॉस नाम से फिल्म बनाई. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन इसके सैटेलाइट, म्यूजिक और दूसरे अधिकार बेचकर फिल्म ने रीलिज से पहले ही 8 करोड़ रुपये कमा लिए.

इसके अलावा, फिल्मकारों का ब्रांड्स के साथ भी टाईअप होता है. अपनी फिल्मों में वे ब्रांड्स का विज्ञापन भी करते हैं और इससे उनकी अच्छी ख़ासी कमाई हो जाती है. हालिया रिलीज फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का टाईअप नोकिया के साथ था. वहीं फिल्म गुरू में हीरो साइकिल, डॉन में मोटोरोला, गार्नियर, सिटी बैंक, लुइस फिलिप, धूम 2 में कोक, पेप, सोनी, डीजनी चैनल, मैक्डी, क्रिश में सिंगापोर टूरिज्म बोर्ड, सोनी, जॉन प्लेयर, बॉर्नवीटा, टाइड, हीरो होंडा, बोरोप्लस, लाइफ ब्वॉय, एचपी पॉवर, रंग दे बसंती में कोका कोला एयरटेल, एलजी, बर्जर और प्रोवोग का विज्ञापन दिखा था. बॉलीवुड में यह कोई नया ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है. राजकपुर की फिल्म बॉबी में भी राजदूत मोटरसाइकिल, फिल्म हीरो में यामाहा 350, यादें में पास–पास, हीरो साइकिल और कोक जैसे ब्रांड्स दिखे थे. ■

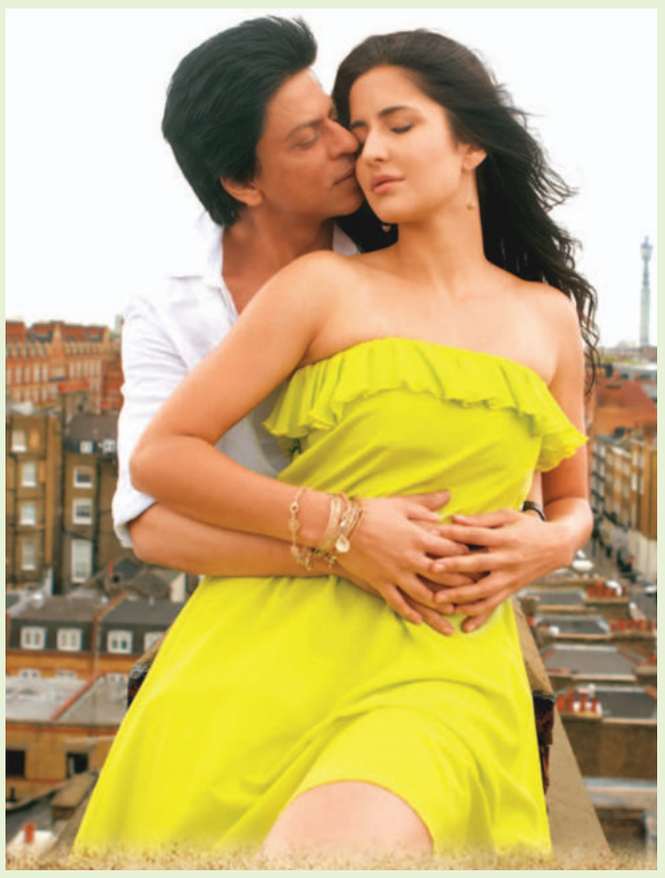

बॉक्स ऑफिस कमाई का एक बड़ा ज़रिया ज़रूर है, लेकिन फिल्मकार कमाई के अन्य तरीक़ों को भी आजकल अपनाने लगे हैं. अब फिल्में रिलीज से पहले ही अपनी लागत से अधिक कमाई कर लेती हैं. सैटेलाइट राइट्स, डीवीडी और इंटरनेट वगैरह माध्यम कमाई का एक बड़ा स्त्रोत बन गए हैं.

कम लागत में ज़्यादा कमाई करती हैं फिल्में

फिल्म	बजट
रावन	150 करोड़
रावन डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स	77 करोड़
सैटेलाइट राइट्स	35 करोड़
म्यूजिक राइट्स	15 करोड़
टेलीकास्ट राइट्स	10 करोड़
(राइ फॉर म्युजिक लॉन्च)	
गेमिंग एंड ब्रैंडिंग	55 करोड़
जब तक है जान	60 करोड़
सैटेलाइट राइट्स	40 करोड़
म्यूजिक	10 करोड़
सब्सिडी (यूके सरकार)	20 करोड़
विदेशी सिनेमा हॉल	35-40 करोड़
होम विडियो	2 करोड़
भारत के सिनेमा हॉल	60-65 करोड़
टोटल	165-177 करोड़
डॉन 2	75 करोड़
डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स	80 करोड़
सैटेलाइट राइट्स	37 करोड़
म्यूजिक राइट्स	10 करोड़
तलाश	40 करोड़
डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स	90 करोड़
सैटेलाइट राइट्स	40 करोड़

जंजीर 2

यह फिल्म 1973 में बनी जंजीर फिल्म की रीमेक है. अपूर्व लखिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म में साउथ के अभिनेता रामचरण तेजा मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है. अभिनेता रामचरन (अमिताभ बच्चन) एसीपी विजय के रोल में नजर आएंगे, जबकि अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा (जया बच्चन) माला के रूप में नजर आएंगी. संजय दत्त शेर खान और श्री हरि तेलगू संस्करण में शेर खान के रोल में नजर आएंगे. प्रकाश राज (तेजा), माही गिल (मोना डार्लिंग), अतूल कुलकर्णी (जयदेव) के रूप में इस फिल्म में नजर आएंगे. इस फिल्म को काफी बड़े बजट में बनाया जा रहा है. फिल्म के एक सीन पर 2 करोड़ रुपये ख़र्च हुए हैं. सीन का सेट इतना बड़ा है कि सात कैमरों की जरुरत पड़ी. सेट पर 200 झुग्गियों और कई कारों को सेट पर बनाया गया है. इस फिल्म का बजट 75 करोड़ रुपये हैं. संजय दत्त इस फिल्म में मॉडर्न पठान के रूप में नजर आएंगे, वहीं देव डी, पान सिंह तोमर, साहब बीवी और गैंगस्टर जैसी फिल्मों में पारंपरिक और देशी भूमिकाओं में दिख चुकी माही गिल इस फिल्म में मोना डार्लिंग की आधुनिक अवतार में काफी खूबसूरत लगीं हैं. इस किरदार को पुराने जंजीर में बिंदू ने निभाया था. प्रियंका चोपड़ा शूटआउट एट वडाला में बबली बदमाश...के बाद इस फिल्म में भी आइटम करती नजर आएंगी.

डाइरेक्टर	:	अपूर्व लखिया
प्रोड्यूसर	:	अमित मेहरा
स्क्रीन प्ले	:	सुरेश नायर
स्टोरी	:	सलीम-जावेद
स्टार कास्ट	:	राम चरण तेजा, प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन रामपाल, प्रकाश राज, माही गिल
म्यूजिक	:	देवी श्री प्रसाद
सिनेमेटोग्राफी	:	चिंटू सिंह
डिस्ट्रीब्यूशन	:	रिलायंस एंड इरोज
भाषा	:	हिंदी और तेलगू
रिलीज डेट	:	6 सितंबर, 2013

बेहतरीन फिल्म है मद्रास कैफे

तमाम विरोधों के बाद भी अभिनेता जॉन अब्राहम की फिल्म मद्रास कैफे बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई. इस फिल्म में लिट्टे का कथित तौर पर नकारात्मक छवि पेश की गई है, जिसके ख़िलाफ़ तमिल समर्थक समूह, छात्रों और राजनीतिक दलों ने काफी विरोध किया. यह फिल्म 23 अगस्त, 2013 को तमिलनाडु में रीलिज होनी थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन के कारण यह फिल्म वहां रीलिज नहीं हुई. इस फिल्म में लिट्टे को आतंकवादी संगठन के रूप में दिखाए जाने पर राजनीति भी हो रही है. आरोप लग रहे हैं कि यह फिल्म तमिल विरोधी है. जॉन की होम प्रोडक्शन की इस फिल्म को निर्देशन किया है शूजित सरकार ने. जॉन और नरगिस फाखरी इस फिल्म में लीड रोल में हैं. इस फिल्म को चार स्टार मिले हैं. यह फिल्म तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश में रिलीज हुई. मद्रास कैफे एक एक्शन-थ्रिलर मूवी है. यह फिल्म 80 और 90 के दशक में भारत और श्रीलंका के संबंधों पर आधारित है. फिल्म में रिसर्च एंड एनालिसिस(रॉ) और श्रीलंकाई संगठन लिट्टे की गतिविधियों को एक खुफिया एजेंट की तरह दिखाया गया है. जॉन ने इस फिल्म में खुफिया एजेंट के रूप में काम किया है. कहा जा रहा है कि यह फिल्म जॉन की अब तक की फिल्मों में सबसे बेहतरीन है. जॉन अब्राहम ने कुछ दृश्यों को फिल्म से हटाने के लिए साफ मना कर दिया. वैसे तो इस फिल्म में जॉन और नरगिस पर कोई गाना नहीं फिल्माया गया है, लेकिन बैकग्राउंड में बजता शांतनू मोइत्रा का म्यूजिक काफी शानदार है.■

चौथी दुनिया

02 सितंबर-08 सितंबर 2013

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार - झारखंड

हर दल में माथापच्ची, चालीस सीटों पर किसे मिलेगा

दिल्ली का टिकट

अनिल सुलभ

चिराग पासवान

दामोदर रावत

देवेश चंद्र ठाकुर

दिलीप जायसवाल

गिरिराज सिंह

लोकसभा चुनाव का बिगुल तो अभी नहीं बजा है, लेकिन लगता है बिहार में सभी दल इसकी आहट साफ- साफ सुन रहे हैं. सभी दलों में इन दिनों लोकसभा चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशियों के नाम को लेकर माथापच्ची शुरू है...

लवली आनंद

मीसा भारती

नागमणि

नरेंद्र सिंह(कृषि मंत्री)

पप्पू यादव

समीर महासेठ

सम्राट चौधरी

सतीश कुमार राघव

सुनील कुमार पिंटू

तस्लीमुद्दीन

विजय कृष्णा

विनोद चौधरी

सरोज सिंह

आगामी चुनाव में जिन नेताओं ने मैदान में उतरने की चाहत पाल रखी है, उनकी चहलक़दमी पार्टी मुख्यालय और पार्टी सुप्रीमो के नजदीक तेज हो गई है. इनमें तो कुछ ऐसे हैं, जिन्हें पूरा भरोसा है कि उनका टिकट कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि उनसे बेहतर उम्मीदवार पार्टी में हैं ही नहीं. इस श्रेणी में सीटिंग सांसदों की संख्या ज़्यादा है. हां नेगेटिव रिपोर्टिंग के कारण कुछ सीटिंग सांसदों की सांसें ज़रूर फूल रही हैं. सबसे ज़्यादा सक्रिय ऐसे नेता हैं, जो पहली बार दिल्ली जाने के लिए कमर कस रहे हैं. भाजपा व जदयू गठबंधन टूटने के बाद उनके लिए स्कोप काफ़ी बढ़ गया है. राजद व जदयू में भी कुछ प्रत्याशियों को बदलने पर विचार हो रहा है, इसलिए नए लोगों की यहां भी काफ़ी गुंजाइश बन रही है. कांग्रेस के लिए तो पूरा मैदान ही खुला है. संभावित उम्मीदवारों को अगर कोई एक बात परेशान कर रही है, तो वह है गठबंधन का गणित. सूबे में कुछ नए राजनीतिक गठबंधन बनने के आसार भी जताए जा रहे हैं. किन दलों में गठबंधन होगा और किन शर्तों पर होगा, यह चिंता चुनाव लड़ने वाले नेताओं को खाए जा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि गठबंधन की आग में कहीं उनकी उम्मीदवारी जल कर राख न हो जाए. इसके बावजूद नेताओं ने दावा मजबूत करने का अपना अभियान जारी रखा है. इसकी शुरुआत वाल्मिकी नगर सीट से करते हैं. जदयू के सीटिंग सांसद बैद्यनाथ महतो के यहां से लड़ने के पूरे आसार दिख रहे हैं. भाजपा यहां से चंद्रमोहन राय को मैदान में उतार सकती है.

हालांकि गोपालगंज से जदयू सांसद पूर्णमासी राम भाजपा या फिर राजद के टिकट से यहां से भाग्य आजमाना चाहते हैं. इस सिलसिले में दिल्ली में कई बार भाजपा व राजद नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई है. राजद इस बार एक नया चेहरा भी यहां उतार सकती है. पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले फकुर्रद्दीन पर राजद दांव लगा सकती है. कांग्रेस से राघव शरण पांडेय के नाम की चर्चा भी है. मोतिहारी से बीजेपी के मौजूदा सांसद राधामोहन सिंह का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि जदयू यहां लोजपा के महेश्वर सिंह को अपना टिकट दे सकती है. सूत्र बताते हैं कि महेश्वर सिंह जल्द ही लोजपा का दामन छोड़ जदयू के पाले में जा सकते हैं. अगर कांग्रेस व राजद का गठबंधन हुआ तो अखिलेश सिंह का यहां से प्रत्याशी बनना तय है. बेतिया में भाजपा के मौजूदा सांसद संजय जायसवाल और जदयू के जिलाध्यक्ष डॉ. एनएन शाही का आमना सामना होना तय माना जा रहा है. बेतिया में राजद सीताराम सिंह को चुनाव लड़वाना चाहती है, लेकिन सिंह इसके लिए तैयार नहीं हैं. ऐसी स्थिति में अनवारुल हक़ भी यहां लालटेन का दामन थाम सकते हैं. शिवहर और सीतामढ़ी में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले नेताओं की सूची कुछ ज़्यादा ही बड़ी है. शिवहर से भाजपा की मौजूदा सांसद रमा देवी को टिकट के लिए विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद और तालमेल की स्थिति में लवली आनंद से मुक़ाबला करना पड़ सकता है. राजद से रघुनाथ झा, सीताराम सिंह, अनवारुल हक़ और अंगेश कुमार सिंह का नाम भी चर्चा में है, जबकि जदयू से पूर्व मंत्री हरिकिशोर सिंह, विधायक सुनीता सिंह चौहान के पति राणा रणधीर सिंह चौहान टिकट की दौड़ में शामिल हैं. तालमेल न होने पर लोजपा से नगीना देवी यहां से चुनाव लड़ सकती हैं. कांग्रेस से यहां अनिल सुलभ के चुनाव लड़ने के प्रबल आसार हैं. बताया जा रहा है पार्टी हाईकमान सुलभ को शिवहर के अलावा पटना के किसी भी सीट से चुनाव लड़वाने का मन बना रही है. इसी तरह सीतामढ़ी में भी उम्मीदवारों को लेकर काफ़ी मथापच्ची है. जदयू से यहां अर्जुन राय, नवल किशोर राय, देवेश चंद्र ठाकुर, शाहिद अली खान तथा राजेश चौधरी के नाम की चर्चा है. वहीं भाजपा से सुनील पिंटू व रामनरेश यादव में से किसी को टिकट मिल सकता है. राजद से टिकट के लिए सीताराम यादव, सूर्यदेव राय, जयनंदन यादव व रामश्रेष्ठ खिरहर लगे हुए हैं.

कांग्रेस से समीर महासेठ को टिकट मिलना तय माना जा रहा है, लेकिन विमल शुक्ला भी हाथ पैर मारते नज़र आ रहे हैं. मुजफ्फरपुर से जदयू के मौजूदा सांसद जयनारायण निषाद भाजपा के टिकट पर भाग्य आजमा सकते हैं. गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके दिल्ली स्थित आवास पर यज्ञ भी किया गया था. राजद की ओर से पार्टी अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, वीणा शाही और डॉ. हरेंद्र कुमार में से कोई एक टिकट पा सकता है. जदयू से यहां दिनेश सिंह या फिर उनकी पत्नी के चुनाव मैदान में उतरने के आसार हैं. चर्चा है कि जदयू किसी साहनी उम्मीदवार पर भी यहां से दांव लगाने की जुगत में है. महाचंद्र सिंह का नाम भी यहां से उछाला जा रहा है. हाजीपुर की विरासत रामविलास पासवान अपने पुत्र चिराग पासवान को सौंपने का मन बना चुके हैं. चिराग की सक्रियता बताती है कि वह अपने पिता को निराश नहीं करेंगे. जदयू से यहां रामसुंदर दास के बड़े बेटे मृत्युंजय कुमार चुनावी अखाड़े में उतर सकते हैं. फिलहाल वह अभी बिहार सरकार की नौकरी में हैं. वैसे यहां के लिए रमई राम भी दबाव बना रहे हैं. रमई राम को जदयू का टिकट नहीं मिला, तो वह यहां से दूसरे दल से भी भाग्य आजमा सकते हैं. वहीं दसई चौधरी ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर यहां अटकलों का बाज़ार गर्म कर दिया है. हो सकता है कि भाजपा यहां उन्हें अपना उम्मीदवार बना दे. छपरा में लालू प्रसाद का मुक़ाबला राजीव प्रताप रूडी से ही होना तय है.

जदयू यहां से सलीम परवेज को उम्मीदवार बना सकती है. सीवान में भाजपा इस बार ओमप्रकाश यादव पर दांव खेल सकती है. वैसे यादव भाजपा और कांग्रेस दोनों के संपर्क में हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वह भाजपा से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं. यहां से जदयू से अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिल सकता है, लेकिन इसके लिए वृषण पटेल की सहमति जरूरी है. वैसे राजद से शहाबुद्दीन की पत्नी का भी यहां से लड़ना तय है. गोपालगंज से पूर्णमासी राम व रमई राम दोनों चुनाव लड़ना चाहते हैं. पार्टी कोई भी हो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां जदयू का एक खेमा अनिल कुमार को चाहता है. उजियारपुर से राजद के आलोक मेहता और जदयू से अश्वमेघ देवी का लड़ना भी तय माना जा रहा है. यहां से एनसीपी से नागमणि की पत्नी सुचित्रा सिन्हा भी भाग्य आजमाने जा रही हैं. नागमणि चतरा से चुनाव लड़ने वाले हैं. रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा का भी यहां से लड़ना तय है. बताया जा रहा है कि भाजपा यहां उनका समर्थन करेगी. बेगूसराय से सीपीआई से राजेंद्र प्रसाद सिंह, लोजपा से सूरजभान के क़रीबी अनिल चौधरी और जदयू से मोनाजिर हसन या फिर परवीन अमानुल्ला का नाम सामने आ रहा है. भाजपा यहां से भोला सिंह या फिर बोगो सिंह को प्रत्याशी बना सकती है. राजद से यहां से रामजीवन सिंह का नाम भी उछाला जा रहा है. बताया जाता है कि लालू प्रसाद से रामजीवन बाबू की एक दो दफा बात भी हो चुकी है. खगड़िया से राजद इस बार सम्राट चौधरी को मैदान में उतार सकता है. चौधरी की इस इलाक़े में मजबूती ने लालू प्रसाद को भी प्रभावित किया है.

- शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

» एक नज़र «

किसानों के लिए वरदान

सीआरआई पंप की बिहार व झारखंड में बहुत मांग है. झारखंड किसानों के लिए यह पंप वरदान साबित हो रहा है. यह पंप कम वोल्टेज पर भी अपना काम करते हैं और ऊर्जा की बचत करते हैं. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस कंपनी के एमडी को सम्मानित भी किया है. बिहार के सभी ज़िले में कंपनी की डीलर एवं सर्विस सुविधा उपलब्ध है. कंपनी के उत्पाद आईएसआई मान्यता प्राप्त हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि किसानों को पंप पर [illegible] मिल जाते हैं और इसमें मेंटेनेंस का भी झंझट नहीं है.

मुनाफ़े में सेंट्रल बैंक

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि बैंक ने कुल कारोबार में 15.42 फ़ीसदी की वृद्धि दर्ज की है. जून 2013 में बैंक का कुल कारोबार 4,05,383 करोड़ रुपए हो गया, ठीक एक साल पहले जून में यह 3,51,221 करोड़ रुपए था. उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में बैंक को 22 करोड़ रुपए का मुनाफ़ा हुआ है, साथ ही इस अवधि में कृषि क्षेत्र में 20.60 की वृद्धि दर्ज की गई है. पिछले वर्ष यह राशि 19,782 करोड़ थी, जो इस साल बढ़कर 25,452 करोड़ रुपए हो गई है. उन्होंने बताया कि शिक्षा क्षेत्र में भी 18 फ़ीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है. आंचलिक प्रबंधक ने जानकारी दी कि ग्राहकों की सुविधा के लिए [illegible] बचत स्कीम भी शुरू की गई है. इसमें ग्राहकों को कई सुविधाओं के साथ ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा मिलेगी. – शिवानी

रेल कर्मचारियों की बैठक

खगड़िया रेलवे कॉलोनी में चोरी की घटना पर विराम लगेगी. पुलिस अब कॉलोनी में रात में गश्त करेगी. उक्त बातें रेल थानाध्यक्ष ने रेलवे कॉलोनी में हुई रेल कर्मचारियों की बैठक में कही. ज्ञात हो कि बीती रात उत्तरी रेलवे कॉलोनी में रेलकर्मी राजेश कुमार सिंह के घर में हुई चोरी की घटना के बाद कर्मचारियों ने बैठक कर सुरक्षा की मांग की. बैठक की अध्यक्षता [illegible] रेल कर्मचारी यूनियन के शाखा मंत्री अरुण कुमार झा ने कहा कि समय रहते चोरी के मामले की बरामदगी नहीं होने पर काला बिल्ला लगाकर काम किया जाएगा. बैठक में उत्तरी एवं दक्षिणी रेलवे कॉलोनी की सुरक्षा, बिजली और पर्याप्त मात्रा में पानी सहित चारदिवारी की मरम्मत कराने के लिए भी संबंधित विभाग को पत्र भेजने का भी निर्णय लिया गया. मौक़े पर जीआरपी थानाध्यक्ष केडी सिंह, टीसीआई नील रतन, राजेश कुमार सिंह, परशुराम शर्मा, नरेश यादव, रामविलास सिंह, रामश्रेष्ठ शुक्ला, प्रमोद यादव, मोहन मुखर्जी, बाबूलाल मुरमुर, श्रीलाल, विवेका सिंह, शांतिप्रिय घोष, आई डब्लू के मणिकांत एवं रमेश यादव आदि लोगों का कहना था कि अगर एक माह के अंदर आवास की मरम्मत नहीं की गई तो कर्मचारी मकान खाली कर देंगे.

– नंदकिशोर शर्मा

चंपारण

कब दूर होगा अंधेरा?

राज्य में बिजली व्यवस्था ठीक करने के कितने भी दावे सरकार कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि स्थिति सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ती ही जा रही है.

प्रो. अरविंद नाथ तिवारी

चंपारण में राजीव गांधी विद्युत परियोजना के तहत बिजली का तार यहां के सभी गांवों में पहुंचाने के सरकारी दावे के बावजूद बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही है. यहां तार तो लगाये गए, लेकिन ये बिजली की आपूर्ति के अभाव में बेकार पड़े हैं. जहां पर आपूर्ति की गई है, वहां तार और ट्रांसफॉर्मर काफ़ी घटिया क्वालिटी के थे, जो कुछ दिनों में ही जल गए. उनका अभी मरम्मत कराया जाना बाक़ी है. ज़िला के बेतिया, बगहा, रामनगर, नरकटियागंज जैसे प्रमुख शहरों में भी तार जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं और ट्रासफॉर्मर जल गए हैं. यहां कुछ घंटों में ट्रांसफॉर्मर बदलने और तार मरम्मत किए जाने के सरकारी आदेश का भी कोई प्रभाव नहीं दिखा.

पश्चिमी चंपारण ज़िले को कम से कम पचास से साठ मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, लेकिन ज़िले के कार्यपालक अभियंता आशुतोष कुमार के मुताबिक़ अभी सिर्फ़ पच्चीस से तीस मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है. आपूर्ति बीच में कब ठप्प पड़ जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है. सूत्र बताते हैं कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत ग्यारह सौ, तीस गांवों तक बिजली की तार बिछाई गई. बयालीस हज़ार बीपीएल परिवारों को भी बिजली दी गई. एनएचपीसी ने अपना रिपोर्ट भी फाइनल कर समेट लिया, लेकिन हक़ीक़त यह है कि लगभग दो सौ गावों में ट्रांसफॉर्मर उनके लगाने के बाद जल गए. एनएचपीसी के पदाधिकारियों का कहना है कि मेंटेनेंस करना हमारा काम नहीं है. हमने अपना काम कर के विभाग को सौंप दिया है. यह विभाग की ज़िम्मेदारी बनती है कि वह रिपेयरिंग करवाए. बैरिया, ठकराहा, मधुबनी, पीपरासी जैसे प्रखंड़ के सैकडों गांवों के लोग आज़ादी के बाद से ही बिजली का इंतज़ार कर रहे हैं. यही नहीं शहरों के कई वार्ड ऐसे हैं, जिन्हें अब तक बिजली नसीब नहीं हुआ. पुअर हाउस, रतनमाला, बनकटवा के बाड़ीपट्टी मुहल्ला के लोगों के लिए बिजली एक सपना ही है. जिन गांवों में बिजली है, वहां मेंटनेंस का अभाव है. इस वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं. पिछले साल ही शिकारपुर स्थित मधुबनी सरेह में धान की रोपनी के वक्त हाई टेंशन तार टूटकर खेत में ही गिर गया था, जिससे छह ग्रामीण बुरी तरह जल गए थे. बेतिया जोगापट्टी गांव में अस्सी के दशक में बिजली आख़िरी बार जली थी. बिजली व्यवस्था की हालत जर्जर होने के साथ बिजली का संचालन करने वाला कंट्रोल रूम, ज़िला कार्यालय से लेकर अनुमंडल कार्यालय तक जर्जर है. ■

feedback@chauthiduniya.com

बेगूसराय

लोकसभा चुनाव में किसकी गलेगी दाल

जदयू-भाजपा में फाड़ के बाद राज्य का राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया है. रिश्ते टूटने से दोनों दलों के नेता एवं कार्यकर्ता ख़ुश हैं और वे नफ़ा-नुक़सान की गणित में उलझे हुए हैं. इससे बेगूसराय भी अछूता नहीं है.

सुरेश चौहान

सात विधान सभा वाले बेगूसराय में तेघड़ा, बेगूसराय एवं बखरी (सु.) भाजपा के क़ब्ज़े में है, जबकि मटिहानी, साहेबपुरकमाल एवं चेरियाबरियारपुर जदयू के पास है. बछवाड़ा विधान सभा सीट भाकपा की झोली में है. ज़िले के एकमात्र संसदीय सीट पर जदयू काबिज है. भाजपा-जदयू के अलग होने से ज़िले का राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है और अगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का परिणाम नया गुल खिला सकता है. [illegible]

[illegible] रामलखन सिंह भाजपा के समर्पित एवं बेदाग़ नेता हैं. भाजपा को शहर की सड़कों से गांवों की गलियों तक पहुंचाने का श्रेय उन्हें ही जाता है. युवाओं में उनके प्रति गजब का उत्साह देखा जा रहा है. चर्चा है कि तीनों नेताओं में से कोई भी लोस प्रत्याशी बनाया जा सकता है. हालांकि पूर्वमंत्री गिरीराज भी ताक-झांक कर रहे हैं. दूसरी ओर बेगूसराय को वामपंथ को लेनिनग्राद भी कहा जाता है. पिछले लोस चुनाव में राजग के सम्मिलित जनाधार के सामने उसके प्रत्याशी नहीं टिक पाए, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और अगामी लोस चुनाव में राजग के बिखरे जनाधार का लाभ उठाने में वामपंथ ज़रा भी चूक करने की मूड में नहीं दिख रही है. भाकपा के पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह एवं पार्टी के प्रदेश सचिव राजेंद्र प्रसाद सिंह में से कोई भी पार्टी प्रत्याशी बनाया जा सकता है. [illegible]

[illegible] आसार है, लेकिन यह सब निर्भर करेगा कि किस दल का किसके साथ चुनावी गठजोड़ होगा और किस दल के कार्यकर्ता गुटबंदी से ऊपर उठकर घोषित प्रत्याशी का साथ देंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

ओवर मेडिकेशन से बचें

ariskon Pharma Pvt.Ltd.

डॉ. एन.के.पी. सिंह

मुजफ्फरपुर के जाने माने चिकित्सक डा. एन.के.पी सिंह का कहना है कि बदलते मौसम का इंतजार हर किसी को रहता है. जब बात मानसून की हो तो मन राहत से भर जाता है, कि अब गर्मी से निजात मिलेगी. लेकिन मौसम का यह बदलाव कई बिमारियों को भी अपने साथ लाता है. ऐसे में जरूरी होता है कि हम अपना पूरा-पूरा ख्याल रखें. इस मौसम में वातावरण में नमी मौजूद रहती है. इस वजह से वैक्टीरिया ज्यादा सक्रिय होते हैं. खांसी, निमोनियां, डायरिया और पेट संबंधी बिमारियां इन दिनों आम है. त्वचा से जुड़ी बिमारियां जैसे खुजली और आंखों में कंजंक्टिवाइटिस की समस्या भी कई बार हो जाता है. ऐसे में इंफेक्शन को कम करने के लिए जरूरी है कि हम अपने आहार में फल-फूल और हरी सब्जियों को शामिल करें. और साफ-सफाई पर पूरा ध्यान दें. साथ ही गर्म पानी को ठंढ़ा कर के सेवन करें. अदरक वाली चाय और निंबू पानी तो जरूर लें. कई बार देखा गया है कि लोग अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक लेते हैं. उन्हें कोई भी दवा डाक्टर के परामर्श के बाद ही लेना चाहिए. साधारण इंफेक्शन में एंटीएलर्जीक और परासिटामोल ही काफी होता है. ओवर मेडिकेशन से भी आदमी को बचना चाहिए. यह शरीर की प्रतिरक्षण शक्ति को कम करता है.

ACOBA CAP/SYP/INJ — Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT — Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX — Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
ACOBA CAP/SYP/INJ — Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT — Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.

प्रस्तुति: शशि सागर

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd. A Division of AriskonPharma

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE

NATURE MOULDED FURNITURE — WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY शर्तें लागू।
Contact : 9386595926, 9334115955

पृष्ठ 17 का शेष

हर दल में माथापच्ची, चालीस सीटों पर किसे मिलेगा

दिल्ली का टिकट

जदयू से दिनेश प्रसाद यादव और भाजपा से सतीश प्रसाद सिंह यहां से भाग्य आजमा सकते हैं. सहरसा सीट पर शरद यादव का मुक़ाबला इस बार लवली आनंद से भी हो सकता है. भाजपा यहां से उन्हें उम्मीदवार बनाना चाहती है, लेकिन बताया जा रहा है कि लवली आनंद आरा या फिर काराकाट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भाजपा के बड़े नेताओं को दे चुकी हैं. आरा में भाजपा के सामने अमरेंद्र प्रताप और काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का पेंच फंस रहा है. इसलिए एक संभावना यह भी तलाशी जा रही है कि लवली आनंद सभी सीटों पर भाजपा के लिए प्रचार करेंगी और चुनाव के बाद उन्हें राज्यसभा में भेज दिया जाए. राजद यहां से अशोक सिंह या फिर किशोर कुमार मुन्ना को चुनाव के मैदान में उतार सकती है.

वैसे मुन्ना भाजपा नेताओं के भी संपर्क में हैं. सुपौल में जदयू सांसद को टिकट के लिए अपने ही पार्टी के विजेंद्र यादव व दिनेश यादव की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. जदयू की नज़र यहां विजय कुमार मिश्र पर भी लगी हुई है. राजद यहां सूर्य नारायण यादव या फिर रामदेव भंडारी पर दांव लगा सकती है. किशनगंज में मुक़ाबला राजद के मो. अख्तारुल ईमान और भाजपा के दिलीप जायसवाल या फिर सिकंदर सिंह के बीच हो सकता है. भाजपा में अगर इन दोनों में से बात नहीं बनी, तो शाहनवाज हुसैन भी प्रत्याशी हो सकते हैं. जदयू यहां अख्तारुल ईमान के भी संपर्क में हैं. पूर्णिया में जदयू का मुक़ाबला भाजपा के उदय सिंह और जदयू के लेसी सिंह के बीच माना जा रहा है. कहीं कोई बात नहीं बनी तो पप्पू यादव यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं. अररिया में राजद इस बार तस्लीमुद्दीन पर दांव लगा रही है. भाजपा से प्रदीप सिंह को टिकट मिलना तय माना जा रहा है. जदयू यहां से सुखदेव पासवान को चुनाव लड़ना चाहती है. मुंगेर में जदयू के कई उम्मीदवार अपना दावा ठोक रहे हैं.

वर्तमान सांसद ललन सिंह महाचंद्र सिंह और मंत्री दामोदर रावत का नाम भी चर्चा में है. राजद से रामबदन राय का लड़ना तय माना जा रहा है. भाजपा से गिरिराज सिंह का नाम उछाला जा रहा है. नवादा में तो लगता है सभी बड़े भूमिहार नेता यही से भाग्य आजमाना चाहते हैं. भाजपा से सीपी ठाकुर, गिरिराज सिंह, किशोर कुणाल, डॉ. अजय कुमार और मौजूदा सांसद भोला सिंह इस सीट के लिए लगे हुए हैं. लोजपा से सूरजभान सिंह की पत्नी का नाम यहां से आ रहा है. जदयू यहां से कौशल यादव को अखाड़े में उतार सकता है. राजद यहां से राजबल्लभ यादव को टिकट दे सकता है. बांका से चर्चा है कि पुतुल सिंह भाजपा के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन मौजूदा समीकरण बताता है कि वह जदयू से ही अपना भाग्य आजमाएगी. अगर पुतुल सिंह ने भाजपा का दामन थामा, तो जदयू यहां से अपने मंत्री नरेंद्र सिंह या फिर दामोदर रावत को चुनाव मैदान में उतारेगी. यहां राजद से जयप्रकाश यादव का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है. जमुई में मौजूदा सांसद भूदेव चौधरी इतने अलोकप्रिय हैं कि उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है. ऐसी स्थिति में यहां से जदयू अपने मंत्री श्याम रजक को मैदान में उतार सकती है. रजक पहले भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं. हालांकि नरेंद्र सिंह यहां से शंकर पासवान को चुनाव लड़वाना चाहते हैं. राजद लोजपा गठबंधन से जमुई से लालू प्रसाद व राबड़ी देवी के क़रीबी विनोद चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं. पिछली बार लालू प्रसाद व राबड़ी देवी के कहने पर ही विनोद चौधरी ने चुनाव न लड़ने का फ़ैसला लिया था, लेकिन इस बार उनका चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है. आरा में इस बार मीना सिंह के मुक़ाबले भाजपा के अमरेंद्र सिंह और राजद के विजय कृष्ण हो सकते हैं. आरा व बक्सर के इलाक़े से हर तबके में विजय कृष्ण की स्वीकार्यता उनकी दावेदारी को मजबूत कर रही है. चुनावों में जगदानंद सिंह की विजय कृष्ण हमेशा मदद करते रहे हैं. अगर किसी कारण उन्हें यहां से टिकट नहीं भी मिला, तो वह मुंगेर से भी भाग्य आजमा सकते हैं. पाटलिपुत्र सीट पर इस बार भाजपा की तरफ़ से नवल किशोर यादव व राजद से लालू प्रसाद की पुत्री मीसा भारती के चुनाव लड़ने की चर्चा है. रंजन यादव की घटती लोकप्रियता के मद्देनज़र रंजन यादव का टिकट भी कट सकता है.

जहानाबाद में रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार का मुक़ाबला राजद के सुरेंद्र यादव से हो सकता है. वैशाली में राजद से रघुवंश सिंह का लड़ना तय है. जदयू यहां अन्नू शुक्ला या फिर राघोपुर के विधायक सतीश कुमार को भी चुनाव मैदान में उतार सकती है. बक्सर में राजद के जगदानंद सिंह का मुक़ाबला इस बार बसपा के ददन यादव से हो सकता है. भाजपा से यहां हीरो मनोज तिवारी व पुलिस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडेय के नाम की भी चर्चा है. वैसे सुखदा पांडेय भी दौड़ में शामिल हैं. जदयू में शिवानंद तिवारी के कोटे से भी किसी को टिकट मिल सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

तथागत की तपोभूमि पर भाजपा का मंथन

सुनील सौरभ

प्राचीन काल में मगध साम्राज्य पूरी दुनिया में अपने राजनीतिक कौशल के लिए प्रसिद्ध था. कभी इसकी तूती बोलती थी. मगध प्राचीन काल से ही शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में चर्चित रहा. राजतंत्र समाप्त होने और आजादी के बाद भी मगध अपनी संवेदनशील राजनीतिक मजबूती के लिए जाना जाता रहा है. मगध ने जिस राजनीतिक दल को साथ दिया, वह सत्ता के शीर्ष पर रहा और जिसे नकारा वह सत्ता से बहुत दूर चला गया. आजादी के बाद पहले आम चुनाव से ही मगध कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन बीसवीं सदी का अंतिम दशक आते-आते जेपी और समाजवादी विचारधारा वाले क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जब प्रभाव खत्म हुआ, तभी से मगध से कांग्रेस का खूंटा ऐसा उखड़ा कि आज तक यहां से खड़ा होने के लिए उसे जमीन नहीं मिला.

वर्ष 1990 के बाद से मगध राजद का ऐसा गढ़ बना कि 15 वर्षों तक बिहार के सत्ता शीर्ष पर लालू का राज रहा. मगध के लोगों का जब लालू प्रसाद के राजद से मोहभंग हुआ तो यहां एनडीए (जदयू-भाजपा) ने 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन इसी बीच बिहार में जदयू-भाजपा के गठबंधन में दरार आ गई और भाजपा को गठबंधन से बेदखल होना पड़ा. भाजपा के गठबंधन से अलग होते ही संयोगवश राज्य में कई दुर्घटनाएं हुईं कि बिहार की विधि व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो गये. इन्हीं घटनाओं में बोधगया के महाबोधि मंदिर में सीरियल बम बलास्ट की घटना भी शामिल है. भाजपा ने जदयू से अलग होने के बाद इस मुद्दे को बिहार की खराब होती विधि व्यवस्था से जोड़कर हवा देना शुरू किया. वहीं दूसरी ओर बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति ऐक्ट में बदलाव आया और मगध में सुखाड़ की स्थिति आदि मामले ने भाजपा को चुनावी मुद्दा दे दिया. इन मुद्दों को देखते हुए मगध पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए भाजपा ने तथागत की तपोभूमि बोधगया के पवित्र निरंजना तट पर कैलाशपति सभागार (महामाया पैलेस) में पिछले 16-17 अगस्त को दो दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की. इसी बैठक से बिहार प्रदेश भाजपा ने आगामी लोकसभा और 2015 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी. देश एवं प्रदेश के भाजपा नेताओं का मानना है

कि यदि मगध पर पकड़ मजबूत हो गई, तो देश तथा राज्य में भाजपा को सत्ता में आते देर नहीं लगेगा. इसे देखते हुए बोधगया में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के दो दिवसीय आयोजन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस बैठक के अंतिम दिन पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुजरात के मुख्य मंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे नंदकिशोर यादव समेत बैठक में शामिल सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया. यह अलग बात है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताते हुए ऐसे प्रस्ताव लाने से परहेज करने की नसीहत भाजपा नेताओं को दी. कभी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा और दुनिया में शांति, अहिंसा, ज्ञान का संदेश फैलाने वाले मगध से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव पारित कर, बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने यह साफ कर दिया कि मगध केंद्र की कांग्रेस सरकार तथा जदयू की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ सत्ता परिवर्तन का जो संकल्प लिया है, वह सफल होगा. देश और राज्य जरूर एक दिन भ्रष्टाचारमुक्त शासन का गवाह बनेगा. फिलहाल मगध के पांच लोकसभा सीटों में से तीन जहानाबाद, औरंगाबाद, तथा काराकट पर जदयू तथा नवादा लोकसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है. विधानसभा के 26 निर्वाचन क्षेत्रों में से 16 पर जदयू है, 8 पर भारतीय जनता पार्टी, एक पर राजद और एक पर निर्दलीय का कब्जा है. भाजपा की नजर अपनी सीटों को मजबूत करने के साथ-साथ जदयू के कब्जे वाली विधानसभा क्षेत्रों पर भी है. 8 के अलावा जदयू के 16 विधानसभा क्षेत्रों में से आधे पर भी भाजपा पकड़ मजबूत बना लेती है, तो मगध में इसकी बढ़त हो जाएगी और राज्य में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. इसे ध्यान में रखते हुए बिहार प्रदेश भाजपा ने बोधगया में प्रदेश कार्य समिति की बैठक कर अपनी चुनावी राजनीतिक रणनीति की शुरुआत कर चुकी है. बैठक में महाबोधि मंदिर सीरियल बम बलास्ट से लेकर बिहार की वर्तमान स्थिति पर गंभीर विचार विमर्श करते हुए नीतीश कुमार को गठबंधन तोड़ने तथा अहंकारी होने का आरोप लगाया गया.

राज्य के सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश करने का आरोप भी बिहार सरकार पर लगा. बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के ऐक्ट में संशोधन करने का भी मुद्दा बैठक में उठा. बेतिया, बगहा कांड से लेकर मशरक में मिड-डे मील से हुई बच्चों की मौत का मामला भी बैठक में उठाया गया. बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्षा मंगल पांडेय ने किया, जबकि बैठक में शामिल पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, प्रतिपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव समेत भाजपा के सभी विधायक, सांसद, विधान परिषद सदस्यों ने इस बैठक के माध्यम से केंद्र की कांग्रेस की सरकार तथा राज्य के नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने और आगामी 27 अक्तूबर को पटना में आयोजित हुंकार रैली को ऐतिहासिक बनाने को आह्वान किया. बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैय्यद शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद, गया के सांसद हरि मांझी, पूर्व सांसद राधामोहन सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह समेत भाजपा के सभी सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य तथा प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया. प्रदेश कार्य समिति की बैठक के आयोजन में गया जिला भाजपा के अध्यक्ष जयनेंद्र कुमार तथा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कृष्ण कुमार सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा. बैठक की समाप्ति पर भाजपा नेताओं का मानना था कि पार्टी ने बोधगया की ऐतिहासिक भूमि से आने वाले लोकसभा तथा विधान सभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चुनाव तैयारियां जोरों पर

लोकसभा चुनाव को लेकर सारण लोकसभा क्षेत्र यानी छपरा में राजद, भाजपा और जदयू में लड़ाई का पूर्वाभ्यास शुरू हो चुका है. सभी दलों और उसके नेताओं की सक्रियता क्षेत्र में अचानक बढ़ गई है.

चंद्रप्रकाश राज

नेता जो दिल्ली और पटना में बैठकर बयान जारी करते हैं, इन दिनों छपरा में दिखने लगे हैं. एक तरफ़ वर्तमान सांसद व राजद सुप्रिमो लालू प्रसाद यादव तैयारी को लेकर सक्रिय हुए हैं, तो वहीं भाजपा महासचिव व महाराष्ट्र के प्रभारी सांसद राजीव प्रताप रूडी भी अब क्षेत्र में उन्हें ललकारते नज़र आ रहे हैं. साथ ही जदयू भी मुक़ाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है.

भाजपा व जदयू के गठबंधन के टूटने के बाद से ही यह माना जाने लगा था कि मुक़ाबला राजद, भाजपा, जदयू और कांग्रेस के बीच ही होगा. राजद सुप्रिमो विभिन्न आयोजनों में पहुंच अपनी सक्रियता दर्ज करा रहे हैं. वहीं राजीव प्रताप रूडी भी अपनी पार्टी के आयोजनों में लगातार शामिल होकर चुनावी आधार पर संपर्क भी कर रहे हैं. राजद के जिलाध्यक्ष बेलागुल मोबिन का दावा है कि इस बार चुनाव में लालू-प्रभुनाथ का समीकरण मतदाताओं के सिर चढ़ कर बोलेगा.

भाजपा के महामंत्री प्रोफ़ेसर केबी सिंह के अनुसार नरेंद्र मोदी की लहर पूरे ज़िले में है. जदयू के प्रदेश नेता शैलेंद्र प्रताप अतिपिछड़ों, महादलितों और पार्टी के जनाधार का गुणा-गणित लगाते हुए कहते हैं कि इस बार तो सारण पर जदयू का क़ब्ज़ा तय है. राजपूत और यादव बहुल उस क्षेत्र में मुस्लिम, कुर्मी, अतिपिछड़ा, भूमिहार, ब्राह्मण मतदाता निर्णायक साबित होंगे. बदली हुई दलीय स्थिति में अगर राजीव प्रताप रूडी को राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण वोटों का थोक में फ़ायदा होता दिख रहा है, तो लालू प्रसाद को भी विश्वास है कि यादव, मुस्लिम व प्रभुनाथ समर्थक वोटों का फ़ायदा उन्हें होने जा रहा है. गौरतलब है कि पिछले चुनाव में राजीव प्रताप रूडी भाजपा-जदयू गठबंधन के उम्मीदवार थे, लेकिन लालू प्रसाद ही बाज़ी मार ले गए. उस दिलचस्प मुक़ाबले में रूडी को मामूली वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन सारण में तब और अब में काफ़ी बदलाव आ चुका है. उस प्रमंडल के कद्दावर नेता और महाराजगंज के सांसद प्रभुनाथ सिंह अब राजद के साथ हैं. जानकार बताते है कि यहां आख़िरी चरण में लड़ाई राजपूतों व यादवों के बीच ही होती रही है. सारण लोकसभा क्षेत्र के बनावट पर गौर करें, तो उस लोकसभा क्षेत्र में छपरा शहर, गड़खा, मढ़ौरा, अमनौर, परसा और सोनपुर छह विधान सभा क्षेत्र हैं. यहां दो राजपूत, दो यादव, एक कुर्मी व एक दलित विधायक हैं. वहीं तीन विधानसभा क्षेत्र छपरा शहर, सोनपुर व गरखा भाजपा के पास है, जबकि परसा व अमनौर जदयू के पास तथा मढ़ौरा पर राजद का क़ब्ज़ा है.

वैसे सारण समाजवादियों का गढ़ रहा है. भारत सरकार के पूर्व मंत्री रामबहादुर सिंह, देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू व राजेंद्र प्रसाद के बीच सेतु का काम करने वाले महेंद्रनाथ सिंह ने भी यहां का प्रतिनिधित्व किया. वर्ष 1957 को छोड़कर 1952 से 1977 तक कांग्रेस ने यहां परचम लहराया था. वर्ष 1952 में महेंद्र नाथ सिंह, 1957 में राजेंद्र प्रसाद सिंह (प्रसोपा), 1962, 1967 एवं 1977 में लालू प्रसाद ने उस क्षेत्र से जीत दर्ज की। वर्तमान सांसद दो बार यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं. सारण संसदीय क्षेत्र के चुनावी आकड़ों का विश्लेषण किया जाए, तो यहां संपन्न हुए चुनाव में सदैव राजपूत व यादव जाति के प्रत्याशियों की ही जीत हुई है. वर्ष 1980 में प्रोफ़ेसर सत्यदेव सिंह, 1984 में रामबहादूर सिंह, 1989 में लालू प्रसाद, 1990 के उपचुनाव में लालबाबू राय, 1991 में भी लालबाबू राय, 1996 में राजीव प्रताप रूडी, 2004 और 2009 में लालू प्रसाद को जीत मिली.

वर्तमान में राजद, भाजपा, जदयू और कांग्रेस चारों पार्टियां अपना-अपना ताल ठोक रही हैं. जदयू की ओर से प्रत्याशी के रूप में मिथिलेश कुमार सिंह, सलीम परवेज, रामप्रवेश राय, छोटेलाल राय, शैलेंद्र प्रताप सिंह की चर्चा है. वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में यहां डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सिंह, सेवादल के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, नजरे हसन, अनिल कुमार सिंह, के नाम को

लालू प्रसाद यादव

सलीम परवेज

राजीव प्रताप रूडी

भी पार्टी के कार्यकर्ता आगे कर रहे हैं. उस क्षेत्र में प्रभुनाथ व उनके समर्थकों का राजद में शामिल हो जाने के कारण भी राजद को फ़ायदा होता दिख रहा है. वहीं राजद के आधार वाले समर्थकों की नाराज़गी व नरेंद्र मोदी की लहर को देखते हुए भाजपा अपने जीत का दावा कर रही है. जदयू अपने सामाजिक मतों के ध्रुवीकरण व सुशासन के आधार पर जीत का दावा ठोक रही है. वहीं कांग्रेस अपने मजबूत दमखम से मुक़ाबला चतुष्कोणीय बनाने में जुटी है. चुनाव के घोषणा के बाद बनने वाले स्थानीय समीकरण और अगले विधान सभा चुनाव के समीकरण भी इस लोकसभा चुनाव में अपना प्रभाव दिखाएंगे. इन सबके बीच राजपूत व यादवों के स्थानीय क्षत्रपों की भूमिका भी निर्णायक होगी. पिछले लोकसभा चुनाव में उसी आधार पर लालू प्रसाद की कांटे की टक्कर में जीत हो पाई थी. इस बार भाजपा भी अपने जीत के लिए सभी प्रयास में लगी हुई है. भाजपा के राष्ट्रीय राजनीति में राजीव प्रताप रूडी के बढ़े हुए क़दम भी सहयोगी साबित हो रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : मेरे ससुर जी के आंख में मोतियाबिंद की शिकायत है और वे ऑपरेशन से बचना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में CINERARIA MARITIMA REPL डालना उचित होगा। रिचा स्वामी, राजस्थान

उत्तर : आप CINERARIA MARITIMA REPL दिन में 2 बार दोनों आँखों में 2-2 बूँद डालें। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक चालू रखें। आपको स्थायी निदान मिलेगा। क्योंकि यह बाजार में अन्य आईड्रॉप से अधिक प्रभावशाली व परिष्कृत है।

प्रश्न : डॉं साहब मेरी उम्र 23 वर्ष है, गलत आदतों के कारण अत्यधिक कमजोरी है, इच्छा मात्र से ही असंयमित हो जाता हूँ। मधुरेन्द्र, देहरादून

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी आयु 33 वर्ष है एवं मैं विवाहित हूँ पेशाब में धातक्षीणता की शिकायत है। जिससे मैं कफी चिंतित रहता हूँ। कोई अच्छा और हानिरहित उपाए बतायें। आविद, फिरोजाबाद।

उत्तर : आप निराशा मन से निकाल दें और विगोरा 5000 की 6 शीशी का कोर्स करें एवं विगोरा ऑयल से मालिश करें। यह होमियोपैथिक लिक्यूड दवा है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।

प्रश्न : मेरी उम्र 54 साल है, मैं बाबासीर का मरीज हूँ, पिछले कुछ दिनों से इच्छा होते हुए भी समर्थ नहीं हो पाता हूँ। स्थायी उपचार बतायें। सुधीर सिंह, जयपुर

उत्तर : सुधीर जी! बाबासीर की रोकथाम के लिये आप पाइलेलैक्स लिफलेट के निर्देशानुसार इस्तेमाल करें और विगोरा 5x का 6 शीशी का कोर्स करें और सुबह-शाम हाई पावर मुसली आयल से दो महीने तक लगातार मालिश करें। आपको लाभ होगा।

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 68 वर्ष है। शरीर से बिल्कूल स्वस्थ्य हूँ, लेकिन इच्छाशक्ति के रहते हुये भी शरीर साथ नहीं देता। कोई आयुर्वेदिक तात्कालिक समाधान बतायें। जगदीश प्रसाद, झरिया।

उत्तर : आप सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आयुर्वेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।

प्रश्न : पिछले 7-8 वर्षों से मेरे घुटनों और कमर में बहुत दर्द रहता है। दर्द की वजह से चलना-फिरना मुश्किल हो गया है कोई आयुर्वेदिक उपचार बतायें। देवंती सिंह, दिल्ली

उत्तर : आप ऑर्थोविट कैप्सूल सुबह-शाम एक कैप्सूल लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालिश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 24 वर्ष है। अविकसित सीना के कारण हीन-भाव से ग्रसित हूँ। आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा।

उत्तर : सीना का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं Breastriim Oil का सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से सीना का विकास आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आएंगी।

प्रश्न : बालों के निरन्तर झड़ते रहने के कारण सिर पर गंजापन हो गया है, मैं इस समस्या से बहुत चिन्तित हूँ, उपाय बतायें । उपेन्द्र सिंह, कानपुर

उत्तर : बालों के झड़ने, टुटने से बचने के लिए आप केशवर्धक तेल का नियमित इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से बाल झड़ना एवं टूटना तत्काल समाप्त हो जायेगा।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्ता आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें : REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें 9304291051

किसी भी रोग संबंधी निदान के लिए Dr. Advice पुस्तिका (होमियोपैथिक) निकटतम स्टॉकिस्ट से मुफ्त प्राप्त करें।

REPL द्वारा जनहित में प्रकाशित

» एक नज़र «

कार्यकर्ता सम्मेलन 14 सितंबर को

लोकसभा कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अमित कुमार मंटू ने की. मंटू ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि लोकसभा कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी पंचायत स्तर पर शुरू कर दें. इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को एकजुट होकर काम करना होगा. बैठक में लोकसभा क्षेत्र के हसनपुर, अलौली, सिमरी बख्तियारपुर, बेलदौर, परबत्ता एवं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में कमिटी का गठन कर और जोर-शोर से तैयारी शुरू करनी होगी. मंटू ने कहा कि आगामी 14 सितंबर को लोकसभा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि इस अभियान समिति के कोषाध्यक्ष पूर्व मुखिया विरेंद्र सिंह को बनाया गया है. वहीं मुल्कराज आनंद ने खगड़िया ज़िला को सूखा क्षेत्र घोषित करने की मांग की. बैठक में वीरेंद्र सिंह, साकेब अहमद, शैलेंद्र कुमार वर्मा, पंकज कुशवाहा, तुरंती सिंह, विजय यादव, कौशल किशोर सिंह, दीपक कुमार, कृष्ण कुमार सिंह, मुल्कराज आनंद सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे.

कार्रवाई की मांग

सदर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय चौधरी टोला, रहीमपुर उत्तरी वार्ड नं.-1 में अनियमितताओं को लेकर भाजपा प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार चौधरी ने ज़िला शिक्षा पदाधिकारी श्याम बाबू राम को आवेदन दिया. चौधरी ने बताया कि विद्यालय में चल रहे मध्याह्न भोजन में लूट-खसोट मची है. वहीं मीनू के अनुसार बच्चों को भोजन भी नहीं दिया जाता है. उन्होंने बताया कि विद्यालय में पठन-पाठन नहीं होने के कारण बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है, लेकिन रजिस्टर पर बच्चों की ज़्यादा उपस्थिति दर्ज की जाती है. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक कभी भी समय से विद्यालय नहीं आते हैं. इतना ही नहीं विद्यालय के भवन निर्माण की राशि भी निकाल ली गई है, लेकिन अबतक भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जिसकी जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है. भाजपा प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार चौधरी ने अविलंब जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है.

– नंदकिशोर शर्मा

मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू

सीतामढ़ी शहर के मध्य स्थित ऐतिहासिक श्री राधा कृष्ण मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया गया है. शहर के लक्ष्मी किशोरी उच्च विद्यालय के समीप स्थित मंदिर के नये छत ढलाई को लेकर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पुरोहित पंडित घनश्याम झा, हरि नारायण दास व दिलीप दास ने पूजन कराया. यजमान अनूप प्रसाद सुंदरका, राम स्वार्थ राय, बजरंग लाल गाडिया, लप्पू जी, अभय प्रसाद एवं मदन प्रसाद ने सपत्नीक विधिवत पूजन की. तक़रीबन दो करोड़ की लागत से होने वाले निर्माण कार्य के पूजन के मौक़े पर पूर्व सांसद सीताराम यादव, मनोज कुमार, दिलीप कुमार यादव, जेपी राय, राम श्रेष्ठ राय व शैलेंद्र कुमार समेत अन्य थे.

विजय को बधाई

सीतामढ़ी शहर के कोट बाज़ार निवासी दुर्गा प्रसाद सर्राफ के पुत्र विजय सर्राफ ने सीएमजे यूनिवर्सिटी मेघालय से स्टडी ऑफ इ कॉमर्स इन इंडिया इंपलीमेंटेशन एंड चैलेंज विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है. डॉ. पुनीत कुमार पाठक के निर्देशन में उपलब्धि पाने वाले श्री सर्राफ को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है. – ब्रजेश

नदी अतिक्रमण मुक्त हो

सीतामढ़ी ज़िले में जन समस्याओं को लेकर आंदोलन की श्रृंखला चलाने वाले संघर्ष यात्रा के अध्यक्ष शशि शेखर ने एक बार फिर से लक्ष्मणा नदी का मुद्दा उठाया है. उन्होंने ज़िला पदाधिकारी को एक आवेदन देकर सोनबरसा प्रखंड के दुलारपुर घाट से रुन्नीसैदपुर तक नदी की धारा को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है. साथ ही नदी की धारा में कचरा और अन्य वस्तुओं को फेंकने से उत्पन्न हुई स्थिति का हवाला देते हुए, इस पर रोक लगाने की गुहार लगाई है. नव निर्मित लखनदेई पुल के पाया का स्थान परिवर्तित किये जाने की जांच का आग्रह भी उन्होंने किया है.

चतरा में अवैध वसूली

चतरा ज़िले में इन दिनों आधार कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है. इसकी शिकायत ज़िले के उपायुक्त हंसराज से भी की गई है. उपायुक्त ने संबंधित एनजीओ को फटकार भी लगाई है. करमा के उपमुखिया नरेश दत्त पाठक ने बताया कि यहां वसूली अभी भी जारी है. एक व्यक्ति से दो सौ रुपये से कम नहीं लिया जाता. एक रात एनजीओ के लोग वासुदेव यादव के घर आकर जमा किये गये पैसे ले गये. एनजीओ के इस अवैध उगाही में कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी साथ मिल रहा है.

– अमरेंद्र सिंह

भारतीय किसान संघ

की ओर से भारत के सभी किसानों व भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस व रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ

भारत के तमाम किसान 13 सितम्बर 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुँचकर कॉरपोरेट परस्त सरकार को अपनी उपज के लाभकारी (दाम) मूल्य के लिए बाध्य करें।

विजय नारायण राव
प्रांतीय मंत्री सह उत्तर बिहार प्रभारी
भारतीय किसान संघ, कलमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार
मो .09472302465, 07277080688

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

02 सितंबर–08 सितंबर 2013

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) के अधिकारियों की भूमिका काफ़ी संदिग्ध रही है. यहां रोज नये विवाद हो रहे हैं. कॉलेज की दुर्दशा पर भाकपा नेत्री शालिनी मिश्रा ने अफसोस जाहिर किया. उन्होंने दोषियों के ख़िलाफ़ प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ मजाक करने और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.

सीतामढ़ी

आर-पार के मूड में भाजपा-जदयू

वाल्मीकि कुमार

तक़रीबन डेढ़ दशक पुराने गठबंधन में दरार आने के साथ ही भाजपा व जदयू आगामी लोकसभा चुनाव में आर-पार के मूड में आ गई है. कुछ समय पहले तक एक दूसरे के निर्णय को सिर आंखों पर बैठाने वाले गठबंधन दल के नेता अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ ताल ठोक रहे हैं.

रुन्नीसैदपुर में मंचासीन मंत्री, पूर्व सांसद, विधायक,

सीतामढ़ी ज़िले के कुल 8 विधान सभा में से 4 विधान सभा सीटों पर भाजपा और 4 पर जदयू का क़ब्ज़ा है. उनमें 3 क्षेत्र रुन्नीसैदपुर, बेलसंड व बाजपट्टी सीट की कमान महिला विधायक क्रमश: गुड्डी देवी, सुनीता सिंह चौहान व डॉ. रंजू गीता संभाल रही हैं, तो वहीं सुरसंड विधान सभा क्षेत्र से जदयू के ही शाहिद अली ख़ान विधायक हैं. वहीं सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, मेजरगंज से दिनकर राम, परिहार राम, नरेश प्रसाद यादव रीगा व विधान सभा क्षेत्र का कमान भाजपा के मोतिलाल प्रसाद के हाथों में है. बिहार में गठबंधन दरकने के बाद अब राजनीति का नया अध्याय शुरू हो गया है. सीतामढ़ी ज़िले के तक़रीबन सभी विधान सभा क्षेत्रों में पहले भाजपा नेतृत्व के निर्देश पर जदयू के क़ब्ज़ा वाले क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया गया, जिसमें प्रदेश के भाजपा नेताओं ने भागीदारी कर पार्टी कार्यकर्ताओं में जदयू के ख़िलाफ़ रोष का बीजारोपण करने का काम किया.

अब बारी जदयू की थी. जदयू ने भी विधान सभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर नीतीश सरकार की उपलब्धियों का ढिंढ़ोरा पीटना शुरू कर दिया है. पिछले दिनों सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खादी वस्त्रागार परिसर में आयोजित जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में क्षेत्र के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी एवं राज्यसभा में संसदीय दल के नेता शिवानंद तिवारी समेत अन्य ने गठबंधन टुटने पर अपना पक्ष रखा. उन्होंने यहां तक कहा कि वर्तमान सरकार को बदनाम करने की साजिश भाजपा कर रही है. उन्होंने बिहार शरीफ और बेतिया समेत अन्य स्थानों पर हुई घटना का उदाहरण दिया. नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे गुजरात में मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं. लाल क़िला से बतौर प्रधानमंत्री भाषण का पूर्वाभ्यास भी शुरू कर दिया है. वहीं आरएसएस, विहिप और बजरंग दल कानाफुसी कर लोगों को भ्रमित करने में लगे हैं. जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गठबंधन की नींव से लेकर टूटने तक का वृतांत सुनाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन बना था. तभी भाजपा से कहा गया था कि अगर भाजपा के कुछ चेहरों को आगे लाया गया तो गठबंधन प्रभावित हो सकता है. भाजपा के कुछ सिद्धांत और नीति सामाजिक शांति के लिए घातक माना गया था. हाल के महीनों में जेडीयू के धैर्य का भाजपा परीक्षा लेने लगी थी, जिसका परिणाम सामने है. चौधरी ने कहा कि जेडीयू ने विकास की गति को बनाये रखने का भरोसा दिया था, जो निभाया जा रहा है, लेकिन भाजपा ने जनता के साथ विश्वासघात किया है. सरकार को बदनाम करने की साजिश करने वालों का जल्द ही पर्दाफ़ाश किये जाने की उम्मीद उन्होंने जताई. विधायक गुड्डी देवी ने कहा कि कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचा कर साजिश करने वालों का मुंहतोड़ जवाब देने का काम करे. वहीं जदयू नेता राजेश चौधरी ने भाजपा को विश्वासघाती क़रार दिया.

जदयू जिलाध्यक्ष राम जीवन प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में राज्यसभा सदस्य अनिल साहनी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कहकशा परवीन, सांसद अर्जुन राय, पूर्व सांसद नवल किशोर राय, विधायक गुड्डी देवी, डॉ. रंजू गीता, महादलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राम बालक पासवान समेत अन्य ने भाजपा को कसूरवार ठहराते हुए जदयू कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगने की अपील की. इस दौरान राजद से मजहरुल हक़ व भाजपा से कामेश्वर झा, सोनेलाल चंद्रवंशी व मुखलाल महतो समेत 5 कार्यकर्ताओं ने जदयू का दामन थामा. इससे पूर्व बाजपट्टी विधान सभा क्षेत्र के मधुबन मध्य विद्यालय में आयोजित सम्मेलन में पार्टी नेताओं ने भाजपा का ईंट से ईंट बजाने का आह्वान कार्यकर्ताओं से किया. पूर्व जदयू जिलाध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद सिंह ने तो भाजपा, विहिप और संघ पर उन्माद फैलाने तक का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने यह कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का खाता तक खुलने वाला नहीं है. वहीं मोहन कुमार सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ कोई साजिश सफल होने वाला नहीं है. बेलसंड विधायक सुनीता सिंह चौहान के पति व वरीय नेता राणा रंधीर सिंह चौहान ने कहा कि हमेशा से भाजपा की संस्कृति गाली देने और अपमानित करने की रही है.

विधायक डॉ. रंजू गीता ने स्थानीय समस्याओं का निदान करने की गुहार मंत्री से लगाई. कार्यक्रम के दौरान क़रीब चार दर्जन से अधिक लोगों ने अन्य दलों से रिश्ता तोड़ कर जदयू की सदस्यता ग्रहण की. भाजपा एवं जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन का प्रभाव आम-अवाम पर कितना पड़ेगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है. चर्चाओं पर गौर करें तो बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर करने का भरोसा दिला कर सत्ता पर काबिज होने वाले एनडीए के प्रति आम लोगों में गुस्सा है. वहीं राजद-कांग्रेस, भाकपा-माकपा, रालोसपा-लोजपा समेत अन्य पार्टियां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ज़ोरदार तैयारी में लगी हुई हैं, जबकि सीतामढ़ी ज़िले में एनडीए के दोनों बाग़ी एक दुसरे की औकात नापने की तैयारी कर रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

कॉलेज एक प्राचार्य दो

इंतेज़ारुल हक़

पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी स्थित श्री अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय के असली प्राचार्य कौन हैं, प्रो. धीरेंद्र कुमार सिंह या प्रो. संजय कुमार सिंह. इस सवाल को लेकर जिले में एक नई बहस छिड़ी हुई है.

इन दिनों श्री अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय के दो प्राचार्यों एवं उनके सहयोगियों द्वारा गुटबाज़ी की जा रही है, जिससे यहां पढ़ाई कर भविष्य संवारने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लग गया है, तो वहीं कॉलेज के अस्तित्व पर भी ख़तरे के बादल मंडराने लगे हैं. हालत यह है कि अपने ही लोग दिशा बदलती नदी के दो किनारों की तरह हो गए हैं और बीच का बहता हुआ पानी (शिक्षक व कर्मचारी) चक्कर खाने लगा है. वैसे उस कॉलेज में प्राचार्य पद को ले गुटबाज़ी कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ वर्षों से इसमें काफ़ी तेजी आई है. स्वतंत्रता दिवस के मौक़े पर भी कॉलेज परिसर में आयोजित ध्वजारोहण के समय गुटबाज़ी देखने को मिला, जब दोनों प्राचार्यों प्रो. धीरेंद्र कुमार सिंह व प्रो. संजय कुमार सिंह दोनों ने ध्वजारोहण का प्रयास किया. इससे माहौल काफ़ी ख़राब हो गया, तब प्रशासन को विधि-व्यवस्था कायम रखने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा. अंत में दोनों प्राचार्यों को ध्वजारोहण से अलग करते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच शिक्षा विभाग के कार्यक्रम पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने कॉलेज का मुख्य द्वार बंद कर ध्वजारोहण किया. वर्ष 1980 में शहर के बनिया पट्टी मुहल्ला में अधिवक्ता ठाकुर रामपति सिंह व उनके साथियों द्वारा स्थापित यह कॉलेज इस तरह गुटबाज़ी का शिकार हो जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था. जानकार बताते हैं कि वर्ष 1992 से ही इस महाविद्यालय में गुटबाज़ी चल रही है और इसका खामियाजा समय-समय पर छात्रों व उनके अभिभावकों को भुगतना पड़ा है. गुटबाज़ी के कारण ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति(उच्च माध्यमिक) ने सत्र 2009-11 व 2010 -12 में इस कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी थी और उच्च न्यायालय पटना ने दायर लोक हित याचिका के तहत फ़ैसला सुनाते हुए आवंटित कोड को रद्द कर दिया था. बावजूद इसके, छात्रों का नामांकन किया गया और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया. साथ ही मानसिक और आर्थिक तौर पर उनका शोषण भी किया गया, जिसका छात्रों ने जमकर विरोध भी किया. जानकार बताते हैं कि एक दिसंबर, 2005 को पूर्व प्राचार्य देवकुमार सिंह की मौत के तुरंत बाद कॉलेज के शिक्षक अरविंद कुमार सिंह के प्राचार्य बनने के बाद महाविद्यालय के इतिहास में एक काला अध्याय शुरू हो गया. श्री सिंह शिकारगंज थाना में दर्ज कांड संख्या 72/2001 के अभियुक्त हैं और न्यायालय द्वारा फ़रार घोषित होने के बावजूद प्राचार्य की कुर्सी पर डटे रहे. जब मामला तुल पकड़ने लगा, तब महाविद्यालय की एक मात्र बची डॉनर शांति सिन्हा ने उन्हें निलंबित कर दिया. आम सभा बुलाकर एक नई कमिटि गठित की और प्रो. धीरेंद्र कुमार सिंह को प्राचार्य घोषित किया. प्रो. रामश्रय प्रसाद सिंह उस कमिटि के अध्यक्ष बनाये गए. 25 मई, 2011 को प्रो. धीरेंद्र ने प्राचार्य की कमान संभाल ली और कॉलेज विधिवत चलने लगा. डॉ. अजय कुमार सिंह, प्रो. सुनील कुमार सिंह, डॉ. मो. शाहिद इकबाल व प्रो. धंनजय सिंह उनके मजबूत सहयोगी के रूप में काम करते रहे. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक)ने भी प्रो. धीरेंद्र को प्राचार्य मान लिया और सत्र 2011-013, 2012-014 एंव 2013-015 के लिए मान्यता दे दी. उसके साथ ही महाविद्यालय में नामांकन शुरू हो गया और छात्रों का फॉर्म भरा जाने लगा. इसी बीच महाविद्यालय में कार्यरत वीरेंद्र कुमार सिंह पर 8 हज़ार रुपये गबन का आरोप लगा और नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद वह जेल चले गये. जेल से छुटने के बाद वह प्राचार्य प्रो. संजय सिंह के गुट में शामिल हो गये. 31 जुलाई, 2013 को तीन बजे प्रो. संजय सिंह, अपने सहयोगियों के साथ आए और कॉलेज का ताला तोड़कर प्रवेश कर गए और प्राचार्य की कुर्सी पर काबिज हो गए. पुछे जाने पर प्रो. संजय सिंह ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) ने 19 अप्रैल, 2007 के बाद की बनी कमिटि को अवैध घोषित कर दिया है. इसलिए हरेंद्र सिंह ही वास्तविक सचिव हैं और मैं ही प्राचार्य हूं. शांति सिन्हा की कमिटि 20 फरवरी, 2011 को बनी है, जो अवैध है. उधर मामला तुल पकड़ता देख नगर थाना में उनकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. जानकार बताते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) के अधिकारियों की भूमिका भी इसमें काफ़ी संदिग्ध रही है और यही कारण है कि यहां रोज नये विवाद हो रहे हैं. यह भी ख़बर है कि दो अन्य कमिटियां भी इस कॉलेज पर अपना दावा ठोकने में लगी हैं. कॉलेज की दुर्दशा पर भाकपा नेत्री शालिनी मिश्रा ने अफसोस जाहिर किया. उन्होंने दोषियों के ख़िलाफ़ प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ मजाक करने और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने इसके लिए आंदोलन करने की भी धमकी दी है. ■

डॉ. धीरेंद्र कुमार सिंह

शालिनी मिश्रा

प्रो. संजय कुमार सिंह

स्वतंत्रता दिवस के मौक़े पर कॉलेज परिसर में आयोजित ध्वजारोहण के समय गुटबाज़ी देखने को मिली, जब प्राचार्यों प्रो. धीरेंद्र कुमार सिंह व प्रो. संजय कुमार सिंह ने ध्वजारोहण का प्रयास किया.

feedback@chauthiduniya.com